चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

www.chauthiduniya.com

रामदेव के साथ अब बेईमान भारत

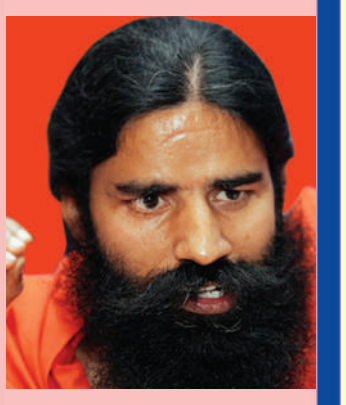

पेज 3

पश्चिम बंगाल बना दुल्हनों का बाज़ार

पेज 4

साइबर अपराध और साइबर क़ानून

पेज 5

साई की महिमा

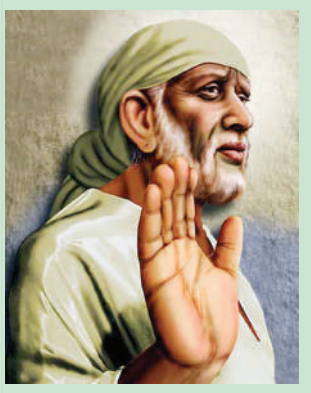

पेज 12

मूल्य 5 रुपये

दिल्ली, 26 अप्रैल-02 मई 2010

प्रियंका गांधी कांग्रेस की आंधी

प्रियंका ख़ुद को प्रियंका रॉबर्ट वाडरा लिखती हैं, लेकिन कांग्रेस उन्हें प्रियंका गांधी के रूप में सामने लाना चाहती है, क्योंकि लोगों के मन में यही नाम सालों से चमक रहा है. बिहार चुनाव में कांग्रेस इस सुपर तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल करने जा रही है, इसके बाद उत्तर प्रदेश और फिर लोकसभा के चुनाव में भी जीत की आशा केवल और केवल प्रियंका गांधी ही हैं. राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोकसभा में पूर्ण बहुमत अनिवार्य शर्त है और कांग्रेस हर क़ीमत पर यह शर्त जीतना चाहती है. कांग्रेस इस क़दम से एक ओर विपक्षी दलों को धराशायी करना चाहती है और दूसरी ओर राजीव गांधी जैसा बहुमत राहुल गांधी के लिए हासिल करने का सपना पाल रही है.

मनीष कुमार

कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी को बिहार के चुनावी दंगल में उतारने वाली है. कांग्रेस के चुनाव प्रचार में प्रियंका का सबसे अहम रोल होगा. चुनाव से पहले और चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका के बिहार दौरे की तैयारी शुरू हो गई है. बिहार के पार्टी संगठन का जायज़ा लिया जा रहा है, जिसके बाद यह तय होगा कि वह किस ज़िले में कब जाएंगी. कांग्रेस पार्टी चाहती है कि बिहार में प्रियंका का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए. प्रियंका को बिहार के दो सौ से ज़्यादा जगहों पर घुमाया जाएगा. प्रियंका को बिहार चुनाव में सक्रिय करने के पीछे कांग्रेस का उद्देश्य बिहार में सरकार बनाना नहीं है, बल्कि यह गांधी परिवार की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे चुनौतीपूर्ण योजना का एक हिस्सा है, जिसके तहत 2014 के लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत दिलाकर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है.

कांग्रेस के लिए 2014 का लोकसभा चुनाव करो या मरो की स्थिति जैसा है, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के संगठन की स्थिति अच्छी नहीं है. इन राज्यों में सिर्फ़ संगठन की ताक़त पर कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ सकती है. कांग्रेस के रणनीतिकारों को यह लगता है कि प्रियंका इस स्थिति से निजात दिला सकती हैं. वह संगठन को दरकिनार करके सीधे जनता से संवाद स्थापित करने में पूरी तरह से सक्षम हैं. सोनिया गांधी को इस बात पर भरोसा है कि मज़बूत संगठन न होने के नुक़सान की भरपाई प्रियंका अपनी छवि और योग्यता से कर सकेंगी. प्रियंका में वह प्रतिभा है कि गरीबी हटाओ जैसे नारों को जन्म दे सकती हैं. वह मुद्दे को जनता का नारा बनाने में सक्षम हैं. ऐसे नारों के सहारे किसी भी चुनाव के माहौल बदला जा सकता है. प्रियंका की इसी काबिलियत से देश भर के नेता भयभीत हैं. कांग्रेस पार्टी भी जानती है कि जब प्रियंका चुनाव के प्रचार में उतरेंगी तो विरोधियों में भगदड़ मच जाएगी.

कांग्रेस पार्टी ने यह तय कर लिया है कि राहुल गांधी को 2014 में देश का प्रधानमंत्री बनाना है. पार्टी 2019 तक इंतज़ार नहीं करना चाहती है. इस योजना को साकार करने के लिए पार्टी ने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है. राहुल गांधी अपनी टीम के साथ मिलकर पार्टी संगठन को अपने हिसाब से शक्ल देने में लगे हैं. इस योजना के बारे में कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पुख्ता ख़बर नहीं है. कांग्रेस के रणनीतिकारों को यह लगता है कि अगर पार्टी को लोकसभा चुनाव 2014 में बहुमत पाना है तो बिहार और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव उसे जीतने होंगे. पहला इम्तहान बिहार में होना है. बिहार में पार्टी की स्थिति मज़बूत करना ज़रूरी है. वहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बिहार में सिर्फ़ दो सीटें मिली थीं. बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रियंका के ज़बरदस्त प्रचार के ज़रिए बिखरी हुई पार्टी को संगठित करना चाहती है. पार्टी संगठन न भी हो, क्योंकि इतनी जल्दी संगठन नहीं बनता, पर मतदाताओं को प्रभावित किया जा सकता है. चुनाव के नज़रिए से पुराने वोटबैंक को वापस खींचना, युवाओं के बीच पार्टी को लोकप्रिय बनाना और महिलाओं एवं अल्पसंख्यकों का विश्वास हासिल करना जैसे बिंदु प्रियंका के एजेंडे में प्रमुखता से डाले गए हैं. कांग्रेस पार्टी को लगता है कि जिस तरह राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में करिश्मा किया, वैसा ही करिश्मा बिहार में प्रियंका गांधी करने में सफल होंगी.

अब सवाल है कि क्या प्रियंका बिहार में यह कमाल दिखा पाएंगी? लोगों को प्रियंका में इंदिरा गांधी की झलक दिखाई देती है. प्रियंका में एक एक्स फैक्टर है. पिछले चुनाव में जिस तरह प्रियंका ने मोदी को जवाब दिया, कांग्रेस बुढ़िया पार्टी है के जवाब में जिस तरह उन्होंने कांग्रेस गुड़िया पार्टी है कहा, उसे लोगों ने ज़्यादा पसंद किया. प्रियंका ने बड़ी समझदारी के साथ अपनी मार्केटिंग भी की है. उन्होंने सबसे पहले ख़ुद को दादी इंदिरा गांधी जैसा बताया. सबूत में नाक दिखाई और कहा कि यह इंदिरा गांधी जैसी है और फिर अपनी साड़ियों के बारे में बताया कि वे तो उनकी दादी की ही हैं. इतना ही नहीं, साड़ियां भी वह इंदिरा जी की तरह ही पहनती हैं. प्रियंका ने संदेश दे दिया कि वह न केवल बहादुर हैं, बल्कि विपक्ष का सामना भी कर सकती हैं और देश को बेहतर युवा नेतृत्व दे सकती हैं. प्रियंका 2004 में पहली बार चुनाव प्रचार में उतरीं. उन्होंने अपना सिक्का रायबरेली में आजमाया. यहां कांग्रेस पार्टी की तरफ़ से गांधी परिवार के क़रीबी सतीश शर्मा और भाजपा के उम्मीदवार अरुण नेहरू थे, जो किसी जमाने में राजीव गांधी के क़रीबी थे. प्रियंका के रायबरेली में आते ही चुनावी माहौल बदल गया. उनका पहला भाषण ही इतना प्रभावी था कि उनके विरोधियों के भी होश उड़ गए. रायबरेली की पहली मीटिंग में प्रियंका ने कहा, मुझे आपसे एक शिक़ायत है. मेरे पिता के मंत्रिमंडल में रहते हुए जिसने गद्दारी की, भाई की पीठ में छुरा मारा, जवाब दीजिए, ऐसे आदमी को आपने यहां घुसने कैसे दिया? उनकी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? प्रियंका ने यह भी कहा, यहां आने से पहले मैंने अपनी मां से बात की थी. मां ने कहा कि किसी की बुराई मत करना. मगर मैं जवान हूं, दिल की बात आपसे न कहूं तो किससे कहूं?

> **राहुल गांधी एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के नेताओं को प्रोत्साहन देना चाहते हैं. राहुल गांधी की यह योजना है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में 2014 के चुनाव में स्वच्छ छवि वाले युवा उम्मीदवारों को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिया जाए. यही वजह है कि इन दोनों संगठनों की देखरेख का काम राहुल के तुगलक रोड स्थित आवास से हो रहा है.**

प्रियंका गांधी जहां जातीं, वहां इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को याद करना नहीं भूलतीं. रायबरेली के इस चुनाव में प्रियंका ने कहा कि मुझे यहां आकर गर्व महसूस हो रहा है. यह इंदिरा जी की कर्मभूमि है. वह मेरी दादी ही नहीं थीं, सारी जनता की मां भी थीं. इस चुनाव में अरुण नेहरू (भाजपा) और सतीश शर्मा (कांग्रेस) आमने-सामने थे. चुनाव प्रचार के दौरान दोनों ही एक-दूसरे पर सीधा हमला करने से बचते रहे. अरुण नेहरू की जीत लगभग पक्की थी, लेकिन प्रियंका ने चुनाव से तीन दिन पहले आकर ऐसा माहौल बना दिया कि सतीश शर्मा जीत गए. यही प्रियंका गांधी का जादू है. उनमें जनता को इंदिरा गांधी की झलक दिखती है. इसी जादू का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी बिहार में करना चाहती है. बिहार के चुनाव में प्रियंका का जादू कितना चलेगा, यह अभी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि बिहार में अपनी ज़मीन खो चुकी कांग्रेस मज़बूत होगी, जिसका फ़ायदा उसे 2014 के लोकसभा चुनाव में मिलेगा.

2014 के चुनाव का अंकगणित कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा नहीं है. अगर राहुल गांधी को पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनाना है तो संगठन को मज़बूत करने के साथ-साथ कई तरह के राजनीतिक दांव खेलने पड़ेंगे. राहुल गांधी के लिए माहौल बनाना पड़ेगा. ऐसी स्थिति पैदा करने की ज़रूरत पड़ेगी कि देश की जनता को यह लगे कि कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं है. 2009 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को अभूतपूर्व सफलता मिली. लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के सदस्यों की संख्या 203 है. कई राज्यों में तो कांग्रेस ने इतनी सीटें जीतीं, जिसे फिर से दोहराना नामुमकिन सा है. 2009 में कांग्रेस ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर की लगभग सारी सीटें जीत लीं. इन राज्यों में फिर से ऐसा करिश्मा दिखाना मुश्किल होगा. आंध्र प्रदेश में 42 में से 33 सीटें जीतकर कांग्रेस ने इतिहास रच दिया. इसके अलावा असम में 7, गुजरात में 11, केरल में 13, मध्य प्रदेश में 12, पंजाब में 8 और राजस्थान में 20 सीटें जीतकर कांग्रेस ने तमाम राजनीतिक विश्लेषकों को आश्चर्यचकित कर दिया. उत्तर प्रदेश में पार्टी 21 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर रही और महाराष्ट्र में उसे 17 सीटें मिलीं. भारतीय राजनीति का तकाज़ा यह है कि हर चुनाव में 30 फ़ीसदी वर्तमान विजेता चुनाव हार जाता है. आंकड़े अगर सच होते हैं तो इसका मतलब यह है कि 2014 के चुनावों में इन राज्यों में कांग्रेस की सीटें कम होंगी. अगर आंकड़ों पर यक़ीन न भी किया जाए, फिर भी यह कहा जा सकता है कि इन राज्यों में ऐसी जीत फिर से हासिल करना नामुमकिन है. सोनिया गांधी इसी नामुमकिन चुनौती को मुमकिन बनाने की तैयारी में जुट गई हैं. कांग्रेस की रणनीति यह है कि जिन राज्यों में 2009 के चुनाव में कम सीटें आई हैं, वहां पार्टी को मजबूत करना है, ताकि 2014 के आम चुनाव में 203 से ज़्यादा सीटें मिल सकें (शेष पृष्ठ 2 पर)

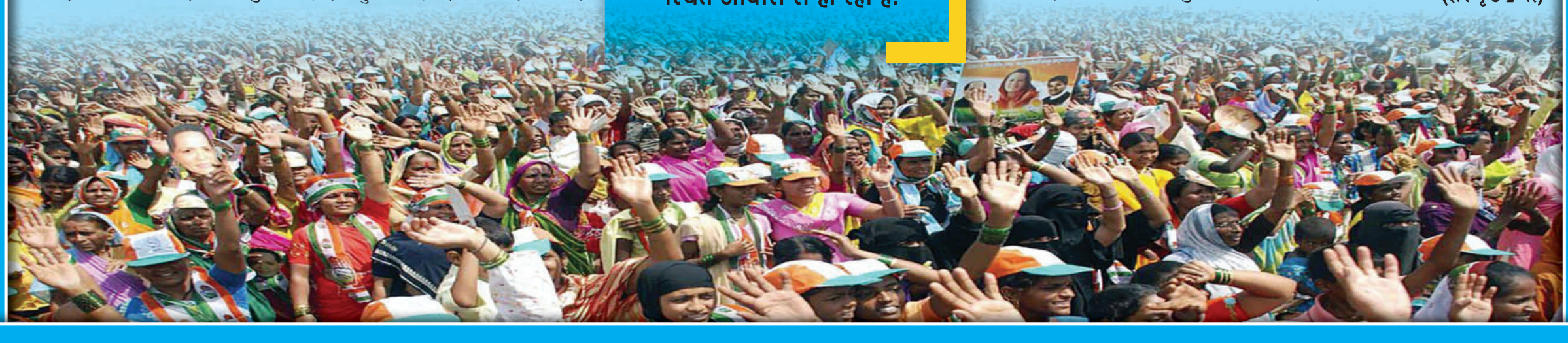

वेटलैंड्स के रखरखाव और इस पर निगरानी रखने के लिए नई नीति बनाई गई है और संरक्षित क्षेत्रों में माइनिंग पर रोक लगाने की दिशा में भी कार्ययोजना बनाई जा रही है.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

निजी स्टाफ पर गिरेगी गाज

कैबिनेट की अप्वायंटमेंट्स कमिटी ने मंत्रियों के निजी स्टाफ के रूप में काम करने वाले नौकरशाहों के लिए अधिकतम समय सीमा निर्धारित करने का फ़ैसला किया है. नए नियम के मुताबिक़, कोई भी अधिकारी, चाहे वह किसी भी ओहदे पर क्यों न हो, अधिकतम 10 वर्षों तक ही किसी मंत्री के निजी स्टाफ के रूप में काम कर सकता है. अखिल भारतीय सेवाओं से संबद्ध अधिकारियों को मंत्रियों के निजी सचिव या ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (ओएसडी) के रूप में नियुक्ति के मामलों में इस समय सीमा का ध्यान रखना अब ज़रूरी होगा. इस नए नियम से कई अधिकारियों को अपने मौजूदा पदों से हटने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, लेकिन शीर्ष पदों पर बने मंत्रियों के ख़ासमख़ासों की सेहत पर ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला.

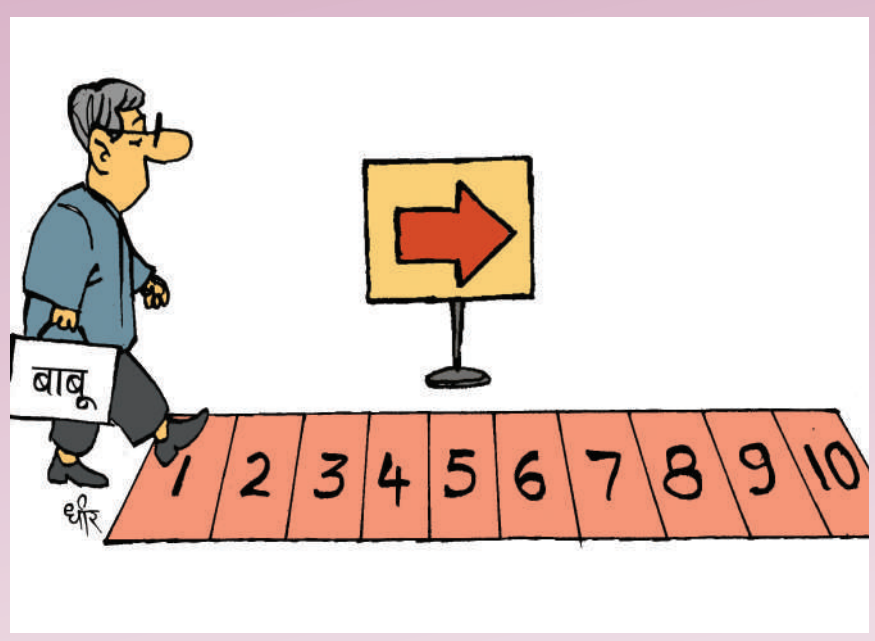

अभी दर्ज़नों अधिकारी ऐसे हैं, जो अपने संबंधित मंत्रियों के हर क़दम पर निगाह रखते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि यूपीए सरकार अभी तक कुल मिलाकर छह साल ही सत्ता में रही है. लेकिन दस साल की यह समय सीमा कई मंत्रियों और उनसे जुड़े अधिकारियों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है. हालांकि इस नए नियम के बारे में अभी कोई अपनी ज़ुबान खोलने को तैयार नहीं है, लेकिन एक वरिष्ठ अधिकारी जिन पर इसकी गाज गिर सकती है, वह हैं ओमिता पॉल. पॉल यूपीए सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री प्रणब मुखर्जी के निजी स्टाफ में शामिल हैं.

यदि यह नियम वास्तव में अमल में लाया जाता है तो पॉल के पास वित्त मंत्रालय की सलाहकार बनने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा. वैसे यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि प्रणब बाबू एक बार निर्णय कर लें तो वह अक्सर अपने मनमाफिक काम कराने में सफल होते हैं.

काम करो या ...

के पी रघुवंशी की महाराष्ट्र के एटीएस (एंटी टेररिस्ट स्क्वॉयड) प्रमुख पद से विदाई ने स्वाभाविक रूप से मुंबई पुलिस के हलकों में हलचल मचा दी है. उनकी जगह राकेश मारिया को नया एटीएस प्रमुख नियुक्त किया गया है, जो इससे पहले तक ज्वाइंट कमिश्नर, क्राइम के पद की ज़िम्मेदारी संभाल रहे थे. 1980 बैच के आईपीएस अधिकारी रघुवंशी को असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, क़ानून एवं व्यवस्था के पद पर भेजा गया है. हिमांशु राय, जो फ़िलहाल ज्वाइंट कमिश्नर, क़ानून एवं व्यवस्था हैं, की मारिया के उत्तराधिकारी के रूप में ताजपोशी हो सकती है.

अब मारिया अपनी नई ज़िम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हो रहे हैं तो उनके लिए भी संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, अपनी क़ाबिलियत दिखाओ या फिर बोरिया–बिस्तर समेटने के लिए तैयार रहो. दंतेवाड़ा में नक्सलियों द्वारा 76 जवानों की सामूहिक हत्या के बाद यह संदेश और भी स्पष्ट हो चुका है.

कभी नहीं से देर भली

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि वन और पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत वन एवं वन्य जीवों और पर्यावरण मामलों के लिए अलग-अलग विभाग होंगे. मौजूदा व्यवस्था में पर्यावरण मंत्रालय के अधीन वन्यजीवों के लिए एक अलग शाखा है, जिसके मुखिया पर्यावरण सचिव विजय शर्मा हैं. हाल के दिनों में पन्ना और रणथंभौर बाघ अभयारण्यों में बाघों की लगातार घटती संख्या के

मद्देनज़र काफी शोरशराबा हुआ है. संभव है, प्रधानमंत्री का यह फ़ैसला इसी परिप्रेक्ष्य में लिया गया हो. वेटलैंड्स के रखरखाव और उस पर निगरानी रखने के लिए नई नीति बनाई गई है और संरक्षित क्षेत्रों में माइनिंग पर रोक लगाने की दिशा में भी कार्ययोजना बनाई जा रही है. अगला नंबर कहीं जंगलों के समीप रहने वाले लोगों के लिए नौकरियों के मुद्दे का तो नहीं है!

dilipcherian@chauthiduniya.com

अब भारत में भी इंडिया फर्स्ट लाइफ़ इंश्योरेंस

भारत के दो प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों–बैंक ऑफ बड़ौदा एवं आंध्रा बैंक के साथ यूके की अग्रणी जोखिम, संपदा एवं निवेश कंपनी लीगल एवं जनरल के एक संयुक्त उद्यम इंडिया फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने इसकी शुरुआत करने की घोषणा की है. इस मौके पर वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडिया फर्स्ट के प्रबंध निदेशक एवं अध्यक्ष एम डी माल्या, मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. पी नंदागोपाल, आंध्रा बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक आर एस रेड्डी और लीगल एवं जनरल के ग्रुप चीफ एक्जीक्यूटिव टिम ब्रीडन आदि मौजूद थे. इस अवसर पर प्रबंध निदेशक माल्या ने कहा हम विशेषकर ग्रामीण एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में आम लोगों को जीवन बीमा का लाभ देने का प्रयास करेंगे.

इंडिया फर्स्ट बीमा कंपनी का मुख्यालय मुंबई में है और इसकी कुल जमा पूंजी 330 करोड़ रुपये है. बैंक ऑफ बड़ौदा और आंध्रा बैंक एक साथ अपने पांच करोड़ ग्राहकों तक इसे पहुंचाने का प्रयास करेंगे. इसके लिए बीमा कंपनी साल के अंत तक पूरे देश में 4500 शाखाएं खोलने की योजना बना रही है. फिलहाल इस बीमा कंपनी के उत्पाद 1750 बैंक शाखाओं में उपलब्ध हैं, जिसमें 1150 बैंक ऑफ बड़ौदा और 600 आंध्रा बैंक में उपलब्ध हैं.

बैंक ऑफ बड़ौदा की इंडिया फर्स्ट में 44 फीसदी हिस्सेदारी है, जबकि आंध्रा बैंक और लीगल एंड जनरल की क्रमश: 30 एवं 26 फीसदी हिस्सेदारी है. शुरुआती दौर में कंपनी की योजना इसे ग्राहकों के लाभानुकूल बनाना है. यही वज़ह है कि इसके प्रारंभिक उत्पादों को विशेष प्रकार की बचत, शिक्षा एवं सेवानिवृत्ति के आधार पर ग्राहकों की विभिन्न अवस्थाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

प्रियंका गांधी, कांग्रेस की आंधी

पृष्ठ 1 का शेष

और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जा सके. कांग्रेस पार्टी को यह भी लग रहा है कि 2014 अच्छा मौक़ा है, क्योंकि विपक्षी पार्टियां कमज़ोर हो रही हैं और कोई भी पार्टी फ़िलहाल कांग्रेस को चुनौती देने के क़ाबिल नहीं है. अगर यह मौक़ा हाथ से निकल गया तो काफी देर हो जाएगी. कांग्रेस पार्टी राहुल को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 2019 तक का इंतज़ार करने को तैयार नहीं है.

कांग्रेस की जीत में रोज़गार गारंटी योजना, महिलाओं को सुरक्षा गारंटी, महिला शिक्षा योजना, स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, किसानों की क़र्ज़ माफी योजना एवं पिछड़ी जातियों के लिए योजना आदि लोकलुभावन कामों का बड़ा हाथ रहा है. इसलिए नई सरकार में विकास का पहिया और भी तेज़ी से दौड़ना तय है. सोनिया गांधी का नेशनल एडवाइज़री काउंसिल का अध्यक्ष बनना भी कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है. इसके ज़रिए आने वाले समय में ग़रीबों, अल्पसंख्यकों एवं ग्रामीणों के विकास की विभिन्न योजनाएं और मनरेगा आदि जैसी योजना सही ढंग से लागू हों, इस पर सोनिया गांधी का पूरा ध्यान रहेगा. इससे महिला आरक्षण, नरेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं ग्रामीण विकास आदि की सफलताओं का क्रेडिट सोनिया गांधी को मिलेगा. इसके अलावा भी कांग्रेस 2014 के आम चुनाव की तैयारी में लग गई है. कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार में पार्टी को मजबूत करना कितना जरूरी है, इसके सबूत हमें 14 अप्रैल को अंबेडकरनगर में हुई रैली से मिलते हैं. कांग्रेस पार्टी ने इस रैली में कहीं भी कुछ भी संसाधन और पैसा मुहैया कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी. देश के सारे कांग्रेसी मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को यह बात साफ–साफ बता दी गई है कि पार्टी संगठन और खासकर राहुल गांधी के किसी भी कार्यक्रम में साधनों की कमी नहीं होनी चाहिए. सामाजिक कार्यों के ज़रिए ग्रामीण इलाक़ों में कांग्रेस पार्टी को मज़बूत करने के लिए ग़ैर सरकारी संस्थान खोले जा रहे हैं और उन्हें धन मुहैया कराया जा रहा है. इसके अलावा कांग्रेस पार्टी अख़बार और टीवी चैनल खोलने की तैयारी में है, ताकि पार्टी के कामों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो सके. साथ ही राहुल गांधी ने संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी खुद पर ले ली है. वह बिहार और उत्तर प्रदेश में युवाओं को मौका देना चाहते हैं. उनकी रणनीति यह है कि 2014 के चुनावों में बिहार और उत्तर प्रदेश में नए चेहरे मैदान में उतरें. उन्हें लगता है कि पुराने नेताओं की छवि और उनके आपसी झगड़ों की वजह से इन राज्यों में पार्टी की यह दुर्गति हुई है. राहुल गांधी एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के नेताओं को प्रोत्साहन देना चाहते हैं. राहुल गांधी की यह योजना है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में 2014 के चुनाव में स्वच्छ छवि वाले युवा उम्मीदवारों को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिया जाए. यही वजह है कि इन दोनों संगठनों की देखरेख का काम राहुल के तुगलक रोड स्थित आवास से हो रहा है. कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच यह दफ्तर राहुल सचिवालय के नाम से जाना जाता है. बताया यह जा रहा है कि इस दफ्तर से पार्टी संगठन को सिर्फ निर्देश दिए जा रहे हैं, यहां सलाह–मशविरों के लिए कोई जगह नहीं है.

बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रियंका के ज़बरदस्त प्रचार के ज़रिए बिखरी हुई पार्टी को संगठित करना चाहती है. पार्टी संगठन न भी हो, क्योंकि इतनी जल्दी संगठन नहीं बनता, पर मतदाताओं को प्रभावित किया जा सकता है.

2014 में कांग्रेस के सामने कई चुनौतियां होंगी. पिछली बार कांग्रेस के पक्ष में लोगों की राय इसलिए सबसे ज़्यादा बनी कि राहुल गांधी एवं सोनिया गांधी ने साफ कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनना है, जबकि बाक़ी दलों में प्रधानमंत्री पद के कई–कई दावेदार घूम रहे थे. भारत की जनता ने इन्हें इसलिए पसंद किया, क्योंकि ऐसे लोग कम होते हैं, जो सत्ता हाथ में रहते हुए भी सत्ता के शीर्ष पर नहीं जाते. कांग्रेस की दूसरी चुनौती यह होगी कि केंद्र सरकार को महंगाई और बेरोज़गारी को प्राथमिकता देनी होगी. सही प्रशासन, कमज़ोर वर्गों के लिए योजनाएं, किसानों की आत्महत्या पर रोकथाम और खेती को लाभकारी बनाने जैसे बिंदु भी उसे अपनी प्राथमिकताओं में शामिल करने होंगे. दलित एवं अल्पसंख्यक ख़ुद को सुरक्षित समझें, उन्हें आर्थिक विकास का फ़ायदा और राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी मिले, यह भी सरकार का कर्तव्य है. अल्पसंख्यकों के लिए, ख़ासकर रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट को अविलंब लागू करना होगा. इसके अलावा मनमोहन सरकार को इस बात से भी सतर्क रहने की ज़रूरत है कि 2014 तक कोई आर्थिक घोटाले न हों. कांग्रेस पार्टी अगर इन बातों का ध्यान रखेगी तो उसे देश में हर जगह प्यार एवं समर्थन मिलेगा. और, उसकी महायोजना सफल हो सकती है.

manish@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
देश का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 2 अंक 7
दिल्ली, 26 अप्रैल–02 मई 2010

संपादक
संतोष भारतीय

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63, नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के – 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के –2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–4783999/11–23418962
विज्ञापन + 91 9873575318
प्रसार + 91 9910220786
फैक्स न. 0120–4783950

पृष्ठ–16 (+4)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

हिंदी-हिंदू-हिंदुस्तान के प्रणेता एवं काशी हिंदू विश्व विद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय ने भी हिंदू महासभा का गठन राजनेता बनने के उद्देश्य से किया, उनकी आशाओं पर जनता ने पानी फेर दिया.

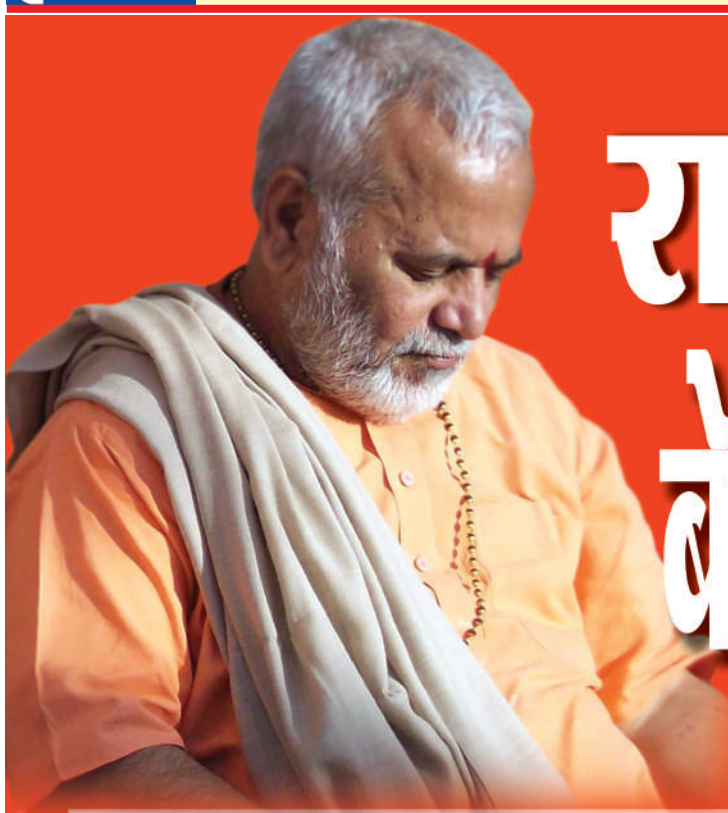

रामदेव के साथ अब बेईमान भारत : चिन्मयानंद

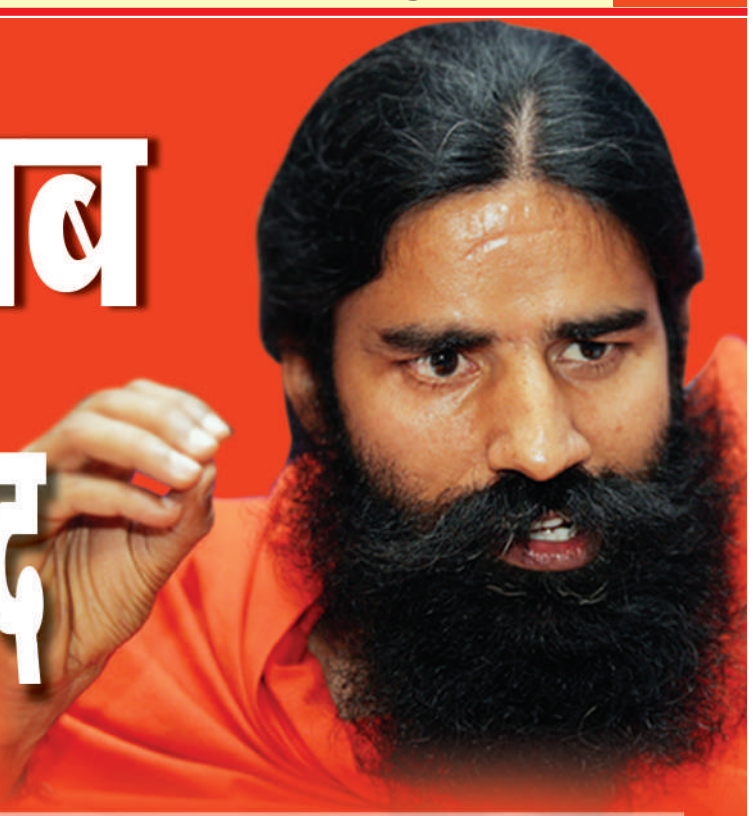

राजकुमार शर्मा

परमार्थ आश्रम हरिद्वार के परमाध्यक्ष एवं पूर्व सांसद स्वामी चिन्मयानंद महाराज का मानना है कि भारत की जनता बाबा रामदेव को अपने नेता के रूप में न कभी स्वीकार कर सकती है, न उन्हें किसी तरह का राजनीतिक क़द प्राप्त हो सकता है. इसके पहले भी एक देव ने राजनीति में आने का दिवास्वप्न देखा था, वह जयगुरुदेव थे. उनका क्या हश्र हुआ, यह सबके सामने है. चिन्मयानंद कहते हैं कि भारत के महान संत करपात्री जी महाराज ने भी एक दल बनाकर उसका इस्तेमाल करके राजनीतिक सफलता हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन वह भी असफल रहे. हिंदी–हिंदू–हिंदुस्तान के प्रणेता एवं काशी हिंदू विश्व विद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय ने भी हिंदू महासभा का गठन राजनेता बनने के उद्देश्य से किया, उनकी आशाओं पर जनता ने पानी फेर दिया.

चिन्मयानंद कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जनआस्था के मुद्दे राम मंदिर को उछाल कर उसका पूरा राजनीतिक लाभ लिया, किंतु जनभावना का निज स्वार्थ के लिए प्रयोग करने के कारण भारतीय जनमानस ने उसे बाद में उन्हीं क्षेत्रों में बुरी तरह नकार दिया, जहां उसे सर्वाधिक समर्थन मिला था. भाजपा को देश की जनआस्था के साथ खिलवाड़ की सजा आज तक मिल रही है. महान समाजवादी चिंतक एवं विचारक डॉ. राम मनोहर लोहिया की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि डॉ. लोहिया ने लोकधर्म को ही राजनीति की संज्ञा दी थी और उनका मानना था कि इसका प्रयोग राष्ट्रहित में किया जाना चाहिए.

स्वामी चिन्मयानंद ने कहा कि पहले तो बाबा रामदेव के साथ एक बीमार भारत जुट रहा था, किंतु अब उनके साथ बेईमान भारत जुट चुका है और योगगुरु पूरी तरह से बेईमान भारत से घिरे हुए हैं. देश के चंद व्यवसायी अपने व्यवसायिक उद्देश्य साधने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं. रामदेव ने भी योग को अब जनकल्याण से हटाकर चंद लोगों के कल्याण तक सीमित कर दिया है. उन्होंने अपने साथ जुटी आस्था का व्यवसायिक प्रयोग शुरू कर दिया है. धर्म–आस्था का व्यवसायिक प्रयोग एक नितांत निंदनीय कार्य है, जिसे देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी. चिन्मयानंद ने देश की जनता की राजनीतिक समझ की सराहना करते हुए कहा कि यह पब्लिक है, सब जानती है. बाबा रामदेव के खेल का अब अंतिम चरण चल रहा है, जिसमें मतिभ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है.

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री एवं बसपा प्रमुख मायावती द्वारा बाबा रामदेव को निशाने पर लेने के सवाल पर स्वामी चिन्मयानंद ने कहा कि मायावती भारतीय राजनीति की विडंबना की उपज मात्र है, जिसने दलितों के सहारे सत्ता का सुख तो पूरी तरह से प्राप्त किया, किंतु उसने दलित–कमज़ोर वर्ग का कोई भला नहीं किया. उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि अब तो मायावती दलित की बेटी से दौलत की बेटी बन गई है. वह भारतीय राजनीति में मानक नहीं बन सकती.

> रामदेव एवं राखी सावंत में एक समानता दिखती है कि दोनों ने जनचर्चा में आने के लिए अंग प्रदर्शन का रास्ता अपनाया और दोनों की चर्चा भी एक जैसी होती है. जो तेज़ दौड़ लगाता है, वह गिरता भी तेज़ी से है और जब वह गिरता है तो संभल नहीं पाता. उन्होंने कहा कि शोहरत पा चुके रामदेव के गिरने के दिन लगता है कि बेहद क़रीब आ चुके हैं.
>
> *–ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी*

भारत साधु समाज के देवभूमि के अध्यक्ष, संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति एवं जैराम संस्थाओं के संस्थापक ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी ने बाबा रामदेव के राजनीतिक भविष्य पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जो तेज़ दौड़ लगाता है, वह गिरता भी तेज़ी से है और जब वह गिरता है तो संभल नहीं पाता. उन्होंने कहा कि शोहरत पा चुके रामदेव के गिरने के दिन लगता है कि बेहद क़रीब आ चुके हैं. उन्होंने अपनी जैराम संस्थाओं का ज़िक्र करते हुए कहा कि कई महान संतों ने इसे अपने त्याग–तपस्या और वर्षों की कड़ी मेहनत से सींचा. आज यह संस्था वटवृक्ष की तरह आकार ले चुकी है और समाज निर्माण में अपनी भूमिका निभा रही है. यह जो कुछ दिख रहा है, वह समाज का दिया और समाज के लिए है, जिसे व्यवस्थित रूप से चलाने का दायित्व मुझे सौंपा गया है. बाबा रामदेव ने ऐसा क्या समाज को दे दिया कि लोग उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार कर लेंगे. विनोदी स्वभाव के धनी ब्रह्मचारी कहते हैं कि रामदेव एवं राखी सावंत में एक समानता दिखती है कि दोनों ने जनचर्चा में आने के लिए अंग प्रदर्शन का रास्ता अपनाया और दोनों की चर्चा भी एक जैसी होती है. रामदेव को एक व्यवसायिक संत बताते हुए उन्होंने कहा कि जैसे एक बार रावण ने भगवा वेश धारण करके सीता जी को छलने में सफलता प्राप्त कर ली थी, उसी तरह कई लोग अब भी भगवा धारण करके बाबा कहलाने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं. सनातन धर्म में संत बनने के लिए संताचरण करना पड़ता है. किसी भी बाबा को जनता रूपी सीता की भावना से खेलने की छूट नहीं दी जा सकती. और, संत वेश का जिसने भी बदनीयती से इस्तेमाल किया, उसका हश्र हमेशा बुरा रहा. रामदेव को एक सफल व्यापारी बताते हुए उन्होंने कहा कि जो दिखता है, वह बिकता है. बहुत पहले से ही आयुर्वेद एवं संतों में जनता की अगाध आस्था रही है. आज भी लोकजीवन में दादी मां के नुस्खे के रूप में अनेक औषधियां प्रचलन में हैं. एक व्यापारी सफल संत और राजनेता नहीं हो सकता. रामदेव का उपयोग पहले लोगों ने एक बाबा बनाने के लिए किया और अब उसी बाबा से लोग अपना व्यापार चला रहे हैं. जनता की अदालत में सदैव दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है. भारतीय जनमानस की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि जनता की पहचान–परख क्षमता बहुत तेज़ है, वह समय पर अपना काम करती है.

feedback@chauthiduniya.com

देश का पहला इंटरनेट टीवी

तीन महीने में रचा इतिहास

- हिन्दी की सबसे पॉपुलर वेबसाइट
- हर महीने 7,00,000 से ज़्यादा पाठक
- हर दिन 25,000 से ज़्यादा पाठक
- स्पेशल प्रोग्राम–भारत का राजनीतिक इतिहास
- समाचार–राजनीति, खेल, पर्यावरण, मनोरंजन
- संगीत और फ़िल्मों पर विशेष कार्यक्रम
- साई की महिमा

www.chauthiduniya.tv

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301

शादी होने के बाद दुल्हनों की कई श्रेणियां हो जाती हैं. एक श्रेणी वह होती है, जिसमें लोग उन्हें सिर्फ़ पत्नी के रूप में रखते हैं.

पश्चिम बंगाल बना दुल्हनों का बाज़ार

बिमल राय

मां-बाप की ग़रीबी कुछ लड़कियों-बच्चों की बदक़िस्मती बन गई है. ख़ुशहाल ज़िंदगी का सपना दिखाकर उनके अरमान तरह-तरह से रौंदे जा रहे हैं. सरकार भी जानती है कि यह गोरखधंधा कौन कर रहा है, लेकिन उसने आज तक सिर्फ़ चिंता ही जताई, किया कुछ भी नहीं. आख़िर वजह क्या है?

बंगाल के सीमावर्ती ज़िलों में ओ पार यानी बांग्लादेश से लाई जाने वाली लड़कियां कटी पतंग की तरह होती हैं, जिन्हें लूटने के लिए कई हाथ एक साथ उठते हैं. इनमें होते हैं दलाल, पुलिस, स्थानीय नेता और पंचायत प्रतिनिधि. अवैध रूप से सीमा पार से आने वाली इन लड़कियों की मानसिक हालत बलि के लिए ले जाई जा रही गाय की तरह होती है. एक समय था, जब स्थानीय स्तर पर इनका अवैध पुनर्वास आसान होता था. स्थानीय लोग इन घुसपैठिया परिवारों से शादी का रिश्ता नहीं क़ायम करना चाहते हैं और इन्हें बंगाल से बाहर घर बसाने का ख़तरा उठाना ही पड़ता है. सीमावर्ती ज़िलों के मूल बंगालियों में धीरे-धीरे उभरते आक्रोश ने इनकी परेशानी और बढ़ा दी है. पिछले माह बांग्लादेश के तालाथाना से लाई गई तपती मंडल के साथ कुछ ऐसा ही हुआ. बशीरहाट के चारघाट बाछारपाड़ा की एक विधवा राधारानी ने अपने बांग्लादेशी रिश्तेदारों की मदद से उसे सीमा पार कराया. पड़ोसी तारापद विश्वास ने हरियाणा के दूल्हे मुकेश चोमार की व्यवस्था की. पहले तो दोनों की कोर्ट में शादी कराने की कोशिश की गई, पर तपती के पास भारतीय नागरिकता का कोई सबूत न होने से कामयाबी नहीं मिली. राधारानी के घर में दोनों की शादी का मंडप सज गया, पर घबराई तपती ने हरियाणा के दूल्हे से शादी करने से इंकार कर दिया और पुलिस से शिक़ायत कर दी. पुलिस को शक़ पहले से था और इसकी वजह भी थी, क्योंकि तारापद और राधारानी के घरों में साल में दर्ज़नों शादियां होती थीं. तारापद के पास एक कट्ठा भी ज़मीन नहीं है, पर उसका पक्का घर बन रहा था. एक बात ग़ौरतलब थी कि इन शादियों में दूल्हे भी बंगाल के नहीं, बल्कि मुख्यत: उत्तर प्रदेश और हरियाणा के होते थे, जबकि ज़्यादातर दुल्हनें बांग्लादेश से लाई जाती थीं. 24 मार्च को जब इस सच से परदा हटा तो दूल्हा-दुल्हन के साथ चार अन्य लोगों को भी गिरफ़्तार कर लिया गया. पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो दूल्हे ने शादी के बहाने देह व्यापार के इस गोरखधंधे का खुलासा किया. दूल्हा जेल में है और अवैध रूप से सीमा पार करने वाली तपती भी सलाखों के पीछे है. चौथी दुनिया ने जब अपने स्तर पर छानबीन की तो कई तरह के सच सामने आए. वारदात के बाद पुलिस ने तारापद एवं उसकी पत्नी को मुख्य अभियुक्त बनाया. शादी का मंडप राधारानी के घर में बना था, पर उसे अभियुक्त नहीं बनाया गया. तारापद की पत्नी ने बताया कि भगीरथ सरदार, जयंत मंडल, बिमल बाइन एवं हर्षित विश्वास ने पहले पुलिस बुलाने की धमकी देकर उसके पति से पैसे ऐंठने की कोशिश की, पर बात न बनते देख पुलिस को बुला लिया. चारघाट की महिला समिति की सदस्य शहनाज़ बेगम ने गांव के कई परिवारों का हवाला देते हुए बताया कि हरियाणा के दूल्हों से शादी करके लड़कियां किस तरह चैन की ज़िंदगी गुज़ार रही हैं. पुलिस ने अपना हिस्सा न मिलने पर यह कार्रवाई की है. गांव के लोगों ने भी दबी ज़ुबान से तस्करी की बात स्वीकार की, क्योंकि राधारानी का घर एक तरह से मैरिज हॉल बन गया था. जब हमने शादी के बिचौलिए से संपर्क किया तो वह हरियाणा का नहीं, बल्कि गोरखपुर का रामाश्रय निकला. चोमार के बारे में उसने कोई जानकारी होने से ही इंकार कर दिया. इस तरह शक़ पूरी तरह यक़ीन में बदल गया है कि कहीं इन शादियों में अंतरराज्यीय गिरोह का तो हाथ नहीं है? उत्तर 24 परगना के ही मछलंदपुर से पांच किलोमीटर दूर देगंगा थाना इलाक़े की कलसुर पंचायत की झूमा को भी उसका दूर का रिश्तेदार वशीर अली काम दिलाने के बहाने लेकर फ़रार हो गया. उसकी शादी पहले हो चुकी थी, इसलिए मां टूनू बीबी को संदेह हुआ और उसने अपहरण की रिपोर्ट दर्ज़ करा दी. पुलिस ने इस मामले में लड़के के पिता आकाश मंडल, उसकी पत्नी, ससुर अबुस मंडल और रिश्तेदार बाबू मंडल को गिरफ़्तार कर लिया. लड़की ने किसी दबाव में कहा कि वह अपनी मर्ज़ी से गई थी, लेकिन पुलिस ने नाबालिग बताते हुए उसके बयान को ख़ारिज कर दिया. पुलिस के कड़े रुख़ की वजह से अब तक चारों की जमानत नहीं हो पाई है. झूमा की मां टूनू ने चौथी दुनिया को बताया कि अगर काम दिलवाने का इरादा था तो मुझे बताया क्यों नहीं गया? अब दलालों का गिरोह टूनू पर मामला वापस लेने के लिए दबाव बना रहा है. चौथी दुनिया ने उत्तर 24 परगना के कई इलाक़ों का दौरा किया और देखा कि किस तरह गांवों में दलालों का जाल फैला हुआ है. इस धंधे में दलाल कई स्तर पर काम करते हैं. महिला दलाल बतौर चूड़िहारिन और दूसरे सौंदर्य प्रसाधन बेचने के बहाने उन घरों की तलाश करती हैं, जिन घरों में जवान लड़कियां होती हैं. इनमें ख़ासकर ग़रीब घरों की लड़कियों के अभिभावकों से वे योग्य दूल्हे खोजने का प्रस्ताव रखती हैं. शुरुआती हामी भरने के बाद उन अभिभावकों को उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के अच्छे एवं ख़ुशहाल परिवारों के युवक दिखाए जाते हैं. लड़का दिखाने की रस्म के समय उसकी आय को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है. ग़रीब अभिभावक भी बिना किसी ख़र्च के शादी की चिंता से मुक्त होने के लोभ में फंस जाते हैं और हामी भर देते हैं. उनसे दहेज नहीं मांगा जाता.

शादी होने के बाद दुल्हनों की कई श्रेणियां हो जाती हैं. एक श्रेणी वह होती है, जिसमें लोग उन्हें सिर्फ़ पत्नी के रूप में रखते हैं. बताने की ज़रूरत नहीं कि ख़ासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ परिवार पीढ़ियों से बहिष्कृत होते हैं. यानी दो पीढ़ी पहले भी परिवार के किसी सदस्य ने अगर किसी विजातीय से शादी की हो, तो उससे भात का रिश्ता नहीं होता. छानबीन के दौरान लोगों ने उत्तर 24 परगना के देगंगा प्रखंड के हसरतुल्ला का नाम बताया, जो अपनी बेटी मोती बीबी और दामाद के साथ मिलकर महिलाओं की तस्करी का धंधा करता था. शाहिदा नामक लड़की द्वारा अपनी रामकहानी बताने के बाद उसका पर्दाफाश हुआ था. हालांकि पिछले दो-तीन सालों से वह इस धंधे को छोड़ चुका है. ज़्यादातर फ़र्ज़ी दूल्हों का मक़सद होता है, दुल्हनों को कुछ समय बाद बेच देना. कुछ अपनी आमदनी का ज़रिया बनाने के लिए उन्हें देह व्यापार में लगा देते हैं. शादी के बाद ज़्यादातर दुल्हनों पर अत्याचार का सिलसिला शुरू हो जाता है. उन्हें पहले एक सेलनुमा कमरे में बंद रखा जाता है और हर समय निगरानी रखी जाती है. उन्हें पूरी तरह तोड़ने के लिए मारा-पीटा भी जाता है. जो दुल्हन टूट जाती है, उसके लिए सुख-सुविधाओं के दरवाजे खुलने लगते हैं.

सीमावर्ती इलाक़े में काम कर रही स्वयंसेवी संस्था सेंटर फॉर कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट (सीसीडी) की सहयोगी संस्था नारी विकास मंच ने कुछ सालों पहले यानी 90 के दशक में ऐसी कई लड़कियों को मीडिया के सामने पेश किया था. इनमें दो बहनें मरजीना और लालबीबी भी थीं. एक ही मंडप में इनकी शादी करके पिता माछार अली ख़ुश हुआ कि एक बड़ी चिंता दूर हो गई, पर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में रसूलपुर गांव के दो दूल्हे शेरवानी में सजे दलाल थे. देह की मंडी के दलाल. सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर उतरते ही दूल्हों का नक़ाब हट गया और दलाल-दर-दलाल इनके बिकने का सिलसिला शुरू हो गया. 10 हज़ार से लेकर 50 हज़ार रुपये तक दोनों बहनें कई बार बिकीं. आख़िर में एक दिन आज़ाद होकर वे अपने मायके आ गईं. उत्तर 24 परगना के उत्तर चौरासी गांव की मरज़ीना एवं लालबीबी की तरह पास के चिडिंगा गांव की शाहिदा भी थी. देगंगा के खेजूर डांगा इलाके की माबिया को फिरोज़ा बीबी नामक दलाल ने बेचा था. इसी तरह मुर्शिदाबाद की मेहरुसिन्ना और स्वरूपनगर की काजल सरदार को भी शादी का झांसा देकर बेच दिया गया.

झूमा

काजल सरदार

बिजली विश्वास

मेहरूसिन्ना

नारी विकास मंच ने ज़िले की कुल 25 लड़कियों का पता लगाया है, जिनमें फातिमा (बेटी-अजित अली, उत्तर चौरासी), आयरा (बेटी-मोहर अली, उत्तर चौरासी), जहांनारा (बेटी-हानिफ अली, उत्तर चौरासी), सुप्रिया (बेटी-अब्दुल रऊफ, उत्तर चौरासी), पारुल (बेटी- मेछेर अली, माटीकोमरा), बेगम बीबी (बेटी-खैरुद्दीन मंडल, माटीकोमरा), आसुरा ख़ातून (बेटी-अब्दुर्रहमान, चिडिंगा), आरजीना ख़ातून (बेटी-फकीर अहमद, चिडिंगा), मुमताज़ (बेटी-शमशेर मिस्त्री, चिडिंगा), विजया (बेटी-छोरे मोमिन, दक्षिण चौरासी), फिरोज़ा (बेटी-जमात अली, उत्तर चौरासी), बिजली कर्मकार (उत्तर चौरासी), मोमना (बेटी- जमात अली खरदार, उत्तर चौरासी). सीमा से सटे होने के कारण बंगाल के उत्तर 24 परगना में ऐसे मामले धड़ल्ले से हो रहे हैं. जबकि मुर्शिदाबाद बच्चों की तस्करी के लिए कुख्यात होता जा रहा है. अरब देशों में ऊंट दौड़ और मस्जिदों के सामने भीख मंगवाने के लिए इस ज़िले से भी अपंग बच्चों की तस्करी की जाती है. 1997 में सउदी अरब से सैकड़ों अपंग बच्चों को मुक्त कराकर भारत वापस भेजा गया था. उनमें से ज़्यादातर मुर्शिदाबाद ज़िले के थे. सीसीडी के शमसुर हक ने बताया कि तस्करों का गिरोह पूरी तरह क़ब्ज़े में आ चुकी दुल्हनों को दोबारा मायके भेजकर यह प्रचारित करता है कि वे वहां कितनी सुखी हैं. इससे दलालों को अगला शिकार तलाशने में सुविधा होती है. कोलकाता की चेतला इलाक़े की रीता जायसवारा (14 साल) को उसकी परिचित माया बारुई ने बेहला में काम दिलवाने के बहाने से फुसलाया. हालांकि उसने उसे उत्तर प्रदेश भेज दिया, जहां उसे आर्केस्ट्रा कंपनी में नाचने पर मजबूर किया गया. रीता को कोलकाता पुलिस ने बीते मार्च के पहले सप्ताह में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से मुक्त कराया.

बर्दवान विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान विभाग की ओर से वुमेन स्टडीज रिसर्च सेंटर की छानबीन से पता चला कि शादी के नाम पर बंगाल से लड़कियों की ख़रीद में अंतरराष्ट्रीय तस्कर गिरोह शामिल है. संगठन की प्रमुख निदेशक इशिता मुखोपाध्याय ने बताया कि दहेज न लगने की सुविधा की वजह से अभिभावक अपनी कमसिन बेटियों को भी ब्याह देते हैं. 2001 की जनगणना और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के मुताबिक़, बाल विवाह के राष्ट्रीय औसत के मुक़ाबले बंगाल की दर 39.16 है. नेशनल क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक़, महिलाओं की तस्करी के मामले में नई दिल्ली और पश्चिम बंगाल सबसे ऊपर हैं. 2005 में बंगाल 61 मामलों के साथ दूसरे नंबर पर था और यह कुल मामलों के राष्ट्रीय प्रतिशत का 40.9 था. सीआईडी की एक टीम ने महिषादल थाना इलाक़े से तेरोपोखा से 12 किशोरियों के साथ 4 दलालों को हाल में गिरफ़्तार किया है. जिन राज्यों में इन दुल्हनों की खपत होती है, उनमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब और गुजरात (कच्छ ज़िला) आदि शामिल हैं. मालूम हो कि पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान में पुरुष-महिला का अनुपात काफी कम है.

आंकड़ों पर ग़ौर करें तो 2007 में देश में वेश्यावृत्ति के 69 मामलों का पता चला, जिनमें से 55 लड़कियां केवल बंगाल की थीं. 2006 में ऐसे 123 मामले दर्ज़ किए गए. इनमें से 43.9 प्रतिशत लड़कियां बंगाल की थीं. सुंदरवन इलाक़े में पिछले साल 25 मई को आए आइला तूफान के बाद संदेशखाली, हिंगलगंज, गोसाबा और पाथेर प्रतिमा जैसे इलाक़ों में महिलाओं एवं बच्चों की तस्करी का गिरोह सक्रिय हो गया. छानबीन से पता चला कि उत्तर भारत के राज्यों में घरेलू कामकाज के लिए किशोर-किशोरियों को भेजने में अभिभावकों को कोई हिचक नहीं होती. संदेशखाली की रेणुबाला ने भी अपने 12 वर्षीय बेटे और 10 वर्षीय बेटी को दिल्ली भेजा है. मानीपुर पंचायत के प्रधान भाग्यधर मंडल ने भी स्वीकार किया कि इलाक़े में आई आपदा के बाद से तस्कर गिरोह सक्रिय हो गए हैं. मंडल के मुताबिक़, इलाक़े के हर गांव से औसतन छह लड़कियां लापता हैं. जब उन्होंने लोगों को अपने बच्चे बाहर भेजने से मना किया तो सवाल उठा कि क्या आप हमें दो जून की रोटी की गारंटी दे सकते हैं? गांव के लोगों ने कुछ दलालों को पुलिस के हाथों भी सौंपा, पर सबूत के अभाव में वे छूट गए. पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने हाल में विधानसभा में स्वीकार किया था कि पिछले तीन सालों में राज्य से 30 हज़ार लड़कियों एवं बच्चों की तस्करी हुई है. उनमें से 22,353 का अभी तक पता नहीं चल पाया है. जबकि कुल 5325 तस्करों को पकड़ा जा चुका है. राज्य के महिला, बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग और संदेशखाली एवं पाथेर प्रतिमा से सटे इलाक़ों में काम कर रहे स्वयंसेवी संगठन सेव द चिल्ड्रेन की ओर से कराए गए सर्वे से पता चला कि आमतौर पर सुंदर लड़कियों को वेश्यालयों एवं बारों में बेच दिया जाता है, जबकि बाक़ी को उन राज्यों में बेचा जाता है, जहां महिलाओं का अनुपात पुरुषों की तुलना में कम है. सर्वे के मुताबिक़, काम के लिए बाहर भेजे गए 3429 बच्चे अभी भी लापता हैं, इनमें ज़्यादातर किशोरियां हैं. पुलिस के आला अफसर भी इसे स्वीकार करते हैं. इसकी वजह सीमावर्ती इलाक़ों में ग़रीबी तो है ही, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से इसका सटा होना भी एक बड़ा कारण है. मालूम हो कि बांग्लादेशी लड़कियों के बाद सबसे ज़्यादा संख्या में नेपाली लड़कियां ही ख़रीद-फरोख्त के लिए लाई जाती हैं. आंकड़े हक़ीक़त से काफी कम हो सकते हैं, क्योंकि लड़कियों की तस्करी के बहुत सारे मामलों की रिपोर्ट तक नहीं दर्ज़ कराई जाती. मुर्शिदाबाद में 15 साल की लैला खातून ने एक युवक के ख़िलाफ़ शिक़ायत की, पर मामला दर्ज़ नहीं किया गया. वह युवक उसे मुंबई के वेश्यालय के दलालों को बेचने की फिराक़ में था. बाद में डीएसपी के हस्तक्षेप से उसकी रिपोर्ट दर्ज़ कराई जा सकी. इसी तरह एक और मामले में 17 साल की पिंजूरा खातून के मां-बाप तीन महीने से मुर्शिदाबाद थाने का चक्कर काट रहे थे. बहरमपुर की पिंजूरा को उसी गांव की छब्बी बीबी ने मुंबई में बेच दिया. पिंजूरा का पिता अब्दुर रोब ख़ान अपनी फरियाद लेकर ज़िले के तत्कालीन एसपी नीरज सिंह के पास गया, पर बात नहीं बनी. आख़िर में अब्दुर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की शरण में गया और कोर्ट के आदेश के बाद मामले की रपट दर्ज़ कराई गई. छब्बी का पति मुंबई में राजमिस्त्री का काम करता है और वेश्यालयों के दलालों के भी संपर्क में रहता है. कुछ मामले ऐसे भी पाए गए हैं, जिनमें माताओं ने ही अपनी बेटियां बेच दीं. 22 अगस्त 2008 को कोलकाता से 80 किलोमीटर दूर हुगली ज़िले के मोगरा निवासिनी एक मां के चंगुल में फंसी उसकी बेटी आयत्री सिन्हा को छुड़ाकर उसके पति के पास भेजा गया. मायके आई बेटी को मां ने एक तरह से कैद करके वेश्यालय में बेचने के लिए दलाल से एक लाख रुपये में सौदा कर लिया. पूर्व मिदनापुर के कोलाघाट निवासी एवं आयत्री के पति ने जब उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई तो सीआईडी ने उस 21 वर्षीय लड़की को आज़ाद कराया. बताया जाता है कि इन तस्करों की पंचायतों के प्रधानों से मिलीभगत रहती है और बिक्री का एक हिस्सा उन्हें भी मिलता है. वर्ष 2004-2005 के बीच राज्य के मुर्शिदाबाद ज़िले से 62 लड़कियां लापता हुईं, जिनमें से केवल 13 ही अभी तक बरामद की जा सकी हैं. इसी तरह नदिया ज़िले से लापता 813 लड़कियों में से 10, पश्चिम दिनाजपुर की 200 लड़कियों में से मात्र 6, उत्तर 24 परगना की 152 लड़कियों में से 135 और दक्षिण 24 परगना की 41 लड़कियों में से केवल 12 ही देह बाज़ार से मुक्त कराई जा सकी हैं.

चारघाट बाछारपाड़ा के स्थानीय लोग

feedback@chauthiduniya.com

संयुक्त राष्ट्र की जनरल एसेंबली ने 30 जनवरी, 1997 को प्रस्ताव संख्या ए/आरइएस/51/162 के तहत यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ द्वारा अनुमोदित मॉडल लॉ ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स (इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से संबंधित आदर्श क़ानून) को अपनी मान्यता दे दी.

साइबर अपराध और साइबर क़ानून

सूचना तकनीक क़ानून, 2000 की प्रस्तावना में ही हर ऐसे लेनदेन को क़ानूनी मान्यता देने की बात उल्लिखित है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के दायरे में आता है और जिसमें सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए सूचना तकनीक का इस्तेमाल हुआ हो.

जस्टिस राजेश टंडन

17 अक्टूबर, 2000 को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 (सूचना तकनीक क़ानून, 2000) अस्तित्व में आया. 27 अक्टूबर, 2009 को एक घोषणा द्वारा इसे संशोधित किया गया. संशोधित क़ानून में परिभाषाएं निम्नवत हैं :

(ए) यहां क़ानून से तात्पर्य सूचना तकनीक क़ानून, 2000 से है.

(बी) संवाद (कम्युनिकेशन) का मतलब किसी भी तरह की जानकारी या संकेत के प्रचार, प्रसार या उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है. यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, किसी भी तरह का हो सकता है.

(सी) संवाद सूत्र (कम्युनिकेशन लिंक) का अर्थ कंप्यूटरों को आपस में एक-दूसरे से जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाले सैटेलाइट, माइक्रोवेव, रेडियो, ज़मीन के अंदर स्थित कोई माध्यम, तार, बेतार या संचार का कोई अन्य साधन हो सकता है.

बनी रहे. सूचना तकनीक क़ानून 2000 17 अक्टूबर, 2000 को अस्तित्व में आया. इसमें 13 अध्यायों में विभक्त कुल 94 धाराएं हैं. 27 अक्टूबर, 2009 को इस क़ानून को एक घोषणा द्वारा संशोधित किया गया. इसे 5 फरवरी, 2009 को फिर से संशोधित किया गया, जिसके तहत अध्याय 2 की धारा 3 में इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की जगह डिजिटल हस्ताक्षर को जगह दी गई. इसके लिए धारा 2 में उपखंड (एच) के साथ उपखंड (एचए) को जोड़ा गया, जो सूचना के माध्यम की व्याख्या करता है. इसके अनुसार, सूचना के माध्यम से तात्पर्य मोबाइल फोन, किसी भी तरह का व्यक्तिगत डिजिटल माध्यम या फिर दोनों हो सकते हैं, जिनके माध्यम से किसी भी तरह की लिखित सामग्री, वीडियो, ऑडियो या तस्वीरों को प्रचारित, प्रसारित या एक से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है.

सूचना तकनीक क़ानून, 2000 के अंतर्गत साइबरस्पेस में क्षेत्राधिकार संबंधी प्रावधान

मानव समाज के विकास के नज़रिए से सूचना और संचार तकनीकों की खोज को बीसवीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण अविष्कार माना जा सकता है. सामाजिक विकास के विभिन्न क्षेत्रों, ख़ासकर न्यायिक प्रक्रिया में इसके इस्तेमाल की महत्ता को कम करके नहीं आंका जा सकता, क्योंकि इसकी तेज़ गति, कई छोटी-मोटी दिक़्क़तों से छुटकारा, मानवीय ग़लतियों की कमी, कम ख़र्चीला होना जैसे गुणों के चलते यह न्यायिक प्रक्रिया को विश्वसनीय बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है. इतना ही नहीं, ऐसे मामलों के निष्पादन में, जहां सभी संबद्ध पक्षों की शारीरिक उपस्थिति अनिवार्य न हो, यह सर्वश्रेष्ठ विकल्प सिद्ध हो सकता है. सूचना तकनीक क़ानून के अंतर्गत उल्लिखित आरोपों की सूची निम्नवत है :

1. कंप्यूटर संसाधनों से छेड़छाड़ की कोशिश-धारा 65
2. कंप्यूटर में संग्रहित डाटा के साथ छेड़छाड़ कर उसे हैक करने की कोशिश-धारा 66
3. संवाद सेवाओं के माध्यम से प्रतिबंधित सूचनाएं भेजने के लिए दंड का प्रावधान-धारा 66 ए
4. कंप्यूटर या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से चोरी की गई सूचनाओं को ग़लत तरीक़े से हासिल करने के लिए दंड का प्रावधान-धारा 66 बी
5. किसी की पहचान चोरी करने के लिए दंड का प्रावधान-धारा 66 सी
6. अपनी पहचान छुपाकर कंप्यूटर की मदद से किसी के व्यक्तिगत डाटा तक पहुंच बनाने के लिए दंड का प्रावधान- धारा 66 डी
7. किसी की निजता भंग करने के लिए दंड का प्रावधान-धारा 66 इ
8. साइबर आतंकवाद के लिए दंड का प्रावधान-धारा 66 एफ
9. आपत्तिजनक सूचनाओं के प्रकाशन से जुड़े प्रावधान-धारा 67
10. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सेक्स या अश्लील सूचनाओं को प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए दंड का प्रावधान-धारा 67 ए
11. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ऐसी आपत्तिजनक सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण, जिसमें बच्चों को अश्लील अवस्था में दिखाया गया हो-धारा 67 बी
12. मध्यस्थों द्वारा सूचनाओं को बाधित करने या रोकने के लिए दंड का प्रावधान-धारा 67 सी
13. सुरक्षित कंप्यूटर तक अनाधिकार पहुंच बनाने से संबंधित प्रावधान-धारा 70
14. डाटा या आंकड़ों को ग़लत तरीक़े से पेश करना-धारा 71
15. आपसी विश्वास और निजता को भंग करने से संबंधित प्रावधान-धारा 72 ए
16. कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का उल्लंघन कर सूचनाओं को सार्वजनिक करने से संबंधित प्रावधान-धारा 72 ए
17. फ़र्ज़ी डिजिटल हस्ताक्षर का प्रकाशन-धारा 73

सूचना तकनीक क़ानून की धारा 78 में इंस्पेक्टर स्तर के पुलिस अधिकारी को इन मामलों में जांच का अधिकार हासिल है.

सूचना तकनीक क़ानून 9 जनवरी, 2000 को पेश किया गया था. 30 जनवरी, 1997 को संयुक्त राष्ट्र की जनरल एसेंबली में प्रस्ताव संख्या 51/162 द्वारा सूचना तकनीक की आदर्श नियमावली (जिसे यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड लॉ के नाम से जाना जाता है) पेश किए जाने के बाद सूचना तकनीक क़ानून, 2000 को पेश करना अनिवार्य हो गया था. संयुक्त राष्ट्र की इस नियमावली में संवाद के आदान-प्रदान के लिए सूचना तकनीक या काग़ज़ के इस्तेमाल को एक समान महत्व दिया गया है और सभी देशों से इसे मानने की अपील की गई है. सूचना तकनीक क़ानून, 2000 की प्रस्तावना में ही हर ऐसे लेनदेन को क़ानूनी मान्यता देने की बात उल्लिखित है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के दायरे में आता है और जिसमें सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए सूचना तकनीक का इस्तेमाल हुआ हो. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स सूचना के आदान-प्रदान और उसके संग्रहण के लिए काग़ज़ आधारित माध्यमों के विकल्प के रूप में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का इस्तेमाल करता है. इससे सरकारी संस्थानों में भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दस्तावेज़ों का आदान-प्रदान संभव हो सकता है और इंडियन पेनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891 और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 अथवा इससे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े किसी भी क़ानून में संशोधन में भी इन दस्तावेज़ों का उपयोग हो सकता है.

संयुक्त राष्ट्र की जनरल एसेंबली ने 30 जनवरी, 1997 को प्रस्ताव संख्या ए/आरइएस/51/162 के तहत यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ द्वारा अनुमोदित मॉडल लॉ ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स (इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से संबंधित आदर्श कानून) को अपनी मान्यता दे दी. इस क़ानून में सभी देशों से यह अपेक्षा की जाती है कि सूचना के आदान-प्रदान और उसके संग्रहण के लिए काग़ज़ आधारित माध्यमों के विकल्प के रूप में इस्तेमाल की जा रहीं तकनीकों से संबंधित कोई भी क़ानून बनाने या उसे संशोधित करते समय वे इसके प्रावधानों का ध्यान रखेंगे, ताकि सभी देशों के क़ानूनों में एकरूपता

आधुनिक क़ानून की शब्दावली में साइबर क़ानून का संबंध कंप्यूटर और इंटरनेट से है. विस्तृत संदर्भ में कहा जाए तो यह कंप्यूटर आधारित सभी तकनीकों से संबद्ध है. साइबर आतंकवाद के मामलों में दंड विधान के लिए सूचना तकनीक क़ानून, 2000 में धारा 66-एफ को जगह दी गई है.

इंडियन पेनल कोड (आईपीसी) में साइबर अपराधों से संबंधित प्रावधान

1. ईमेल के माध्यम से धमकी भरे संदेश भेजना-आईपीसी की धारा 503
2. ईमेल के माध्यम से ऐसे संदेश भेजना, जिससे मानहानि होती हो-आईपीसी की धारा 499
3. फ़र्ज़ी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल-आईपीसी की धारा 463
4. फ़र्ज़ी वेबसाइट्स या साइबर फ्रॉड-आईपीसी की धारा 420
5. चोरी-छुपे किसी के ईमेल पर नज़र रखना-आईपीसी की धारा 463
6. वेब जैकिंग-आईपीसी की धारा 383
7. ईमेल का ग़लत इस्तेमाल-आईपीसी की धारा 500
8. दवाओं को ऑनलाइन बेचना-एनडीपीएस एक्ट
9. हथियारों की ऑनलाइन ख़रीद-बिक्री-आर्म्स एक्ट

66-एफ : साइबर आतंकवाद के लिए दंड का प्रावधान

1. यदि कोई-

(ए) भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या संप्रभुता को भंग करने या इसके निवासियों को आतंकित करने के लिए-

क. किसी अधिकृत व्यक्ति को कंप्यूटर के इस्तेमाल से रोकता है या रोकने का कारण बनता है.

ख. बिना अधिकार के या अपने अधिकार का अतिक्रमण कर जबरन किसी कंप्यूटर के इस्तेमाल की कोशिश करता है.

ग. कंप्यूटर में वायरस जैसी कोई ऐसी चीज डालता है या डालने की कोशिश करता है, जिससे लोगों की जान को ख़तरा पैदा होने की आशंका हो या संपत्ति के नुक़सान का ख़तरा हो या जीवन के लिए आवश्यक सेवाओं में जानबूझ कर ख़लल डालने की कोशिश करता हो या धारा 70 के तहत संवेदनशील जानकारियों पर बुरा असर पड़ने की आशंका हो या-

(बी) अनाधिकार या अधिकारों का अतिक्रमण करते हुए जानबूझ कर किसी कंप्यूटर से ऐसी सूचनाएं हासिल करने में कामयाब होता है, जो देश की सुरक्षा या अन्य देशों के साथ उसके संबंधों के नज़रिए से संवेदनशील हैं या कोई भी गोपनीय सूचना इस इरादे के साथ हासिल करता है, जिससे भारत की सुरक्षा, एकता, अखंडता एवं संप्रभुता, अन्य देशों के साथ इसके संबंध, सार्वजनिक जीवन या नैतिकता पर बुरा असर पड़ता हो या ऐसा होने की आशंका हो, देश की अदालतों की अवमानना अथवा मानहानि होती हो या ऐसा होने की आशंका हो, किसी अपराध को बढ़ावा मिलता हो या इसकी आशंका हो, किसी विदेशी राष्ट्र अथवा व्यक्तियों के समूह अथवा किसी अन्य को ऐसी सूचना से फ़ायदा पहुंचता हो, तो उसे साइबर आतंकवाद का आरोपी माना जा सकता है.

2. यदि कोई व्यक्ति साइबर आतंकवाद फैलाता है या ऐसा करने की किसी साजिश में शामिल होता है तो उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा सकती है.

2005 में प्रकाशित एडवांस्ड लॉ लेक्सिकॉन के तीसरे संस्करण में साइबरस्पेस शब्द को भी इसी तर्ज पर परिभाषित किया गया है. इसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में फ्लोटिंग शब्द पर ख़ासा जोर दिया गया है, क्योंकि दुनिया के किसी भी हिस्से से इस तक पहुंच बनाई जा सकती है. लेखक ने आगे इसमें साइबर थेफ्ट (साइबर चोरी) शब्द को ऑनलाइन कंप्यूटर सेवाओं के इस्तेमाल के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया है. इस शब्दकोष में साइबर क़ानून की इस तरह व्याख्या की है, क़ानून का वह क्षेत्र, जो कंप्यूटर और इंटरनेट से संबंधित है और उसके दायरे में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचनाओं तक निर्बाध पहुंच आदि आते हैं.

सूचना तकनीक क़ानून में कुछ और चीज़ों को परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार हैं, कंप्यूटर से तात्पर्य किसी भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल या तेज़ गति से डाटा का आदान-प्रदान करने वाले किसी भी ऐसे यंत्र से है, जो विभिन्न तकनीकों की मदद से गणितीय, तार्किक या संग्रहणीय कार्य करने में सक्षम है. इसमें किसी कंप्यूटर तंत्र से जुड़ा या संबंधित हर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर शामिल है.

सूचना तकनीक क़ानून, 2000 की धारा 1 (2) के अनुसार, उल्लिखित अपवादों को छोड़कर इस क़ानून के प्रावधान पूरे देश में प्रभावी हैं. साथ ही उपरोक्त उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत देश की सीमा से बाहर किए गए किसी अपराध की हालत में भी उक्त प्रावधान प्रभावी होंगे.

(लेखक साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन हैं)

feedback@chauthiduniya.com

बच्चों को टीका लगाने का काम प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा किया जाता है और उपयोग करने से पहले दवा डॉक्टर को दिखाई जाती है.

लक्ष्य पूरा कराने के लिए

मौत का टीका

संध्या पांडेय

मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग भ्रष्टाचार और लापरवाही के लिए खासा बदनाम है. इस विभाग को लोग हत्यारा विभाग तक कहने लगे हैं. हाल में दमोह ज़िला मुख्यालय में टीकाकरण योजना के तहत खसरे का टीका लगाने के बाद चार बच्चों की मौत हो गई और दस बच्चे गंभीर रूप से बीमार हो गए. राज्य के लिए यह एक बड़ी घटना है.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दु:ख जताते हुए दोषियों के ख़िलाफ सख्त कार्यवाही की बात कही. साथ ही उन्होंने प्रत्येक बच्चे के परिजनों को एक-एक लाख रुपये का मुआवजा देने का भी ऐलान किया. इससे पहले लोक स्वास्थ्य मंत्री अनूप मिश्रा ने भी दस-दस हज़ार रुपये के मुआवज़े की घोषणा की थी. स्वास्थ्य विभाग ने अपनी प्राथमिक जांच में इसके लिए एएनएम दुर्गा तिवारी को मुख्य रूप से ज़िम्मेदार माना है, जिसे दमोह पुलिस ने भादवि की धारा 304 के तहत ग़िरफ्तार भी कर लिया है. तीन अन्य कर्मचारियों को लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया है. उधर बीमार पड़े दूसरे दस में से चार बच्चों की हालत नाज़ुक है. उन्हें मेडिकल कॉलेज जबलपुर भेजा गया है, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक उनका इलाज कर रहे हैं. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण और भारत सरकार के स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न सर्वेक्षणों में मध्य प्रदेश को देश का अति पिछड़ा राज्य माना जाता रहा है. भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से बच्चों को निरोग और तंदुरुस्त रखने के लिए जन्म से लेकर पांच वर्ष की आयु तक विभिन्न बीमारियों के पांच टीके अनिवार्य रूप से मुफ्त लगाने की व्यवस्था की है, पर टीकाकरण के मामले में मध्य प्रदेश अन्य राज्यों से काफी पीछे है. यहां केवल 40.3 प्रतिशत बच्चों को बुनियादी टीकाकरण का लाभ मिलता है. इनमें शहरी क्षेत्र के 69 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र के 32 प्रतिशत बच्चे शामिल हैं. राज्य में 5 प्रतिशत बच्चे ऐसे भी हैं, जिन्हें किसी तरह का कोई टीका नहीं लगाया जा सका है.

भारत सरकार की इस रिपोर्ट के बाद राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम को लक्ष्य के अनुसार पूरा करने का अभियान चलाया. अभियान के तहत वर्ष 1998 में एक वर्ष तक की आयु के बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण 22 प्रतिशत पाया गया, जो वर्ष 2006 में बढ़कर 36 और वर्ष 2009 में 40.3 प्रतिशत हो गया. लेकिन, फिर भी सरकार शत-प्रतिशत टीकाकरण का लक्ष्य पूरा कर पाने में सफल नहीं हो सकी. कुछ माह पूर्व राज्य के लोक स्वास्थ्य मंत्री अनूप मिश्रा ने विभाग के उच्चाधिकारियों की बैठक में निर्देश दिए थे कि परिवार नियोजन और राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भरपूर प्रयास किए जाने चाहिए. उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए भी निर्देश दिए थे, लेकिन बरसों से सुस्ती और मस्ती में काम कर रहे स्वास्थ्यकर्मियों पर मंत्री के निर्देशों का कोई असर नहीं हुआ. स्वास्थ्य विभाग को अपने बजट आवंटन खर्च और विभिन्न सेवाओं के लक्ष्य पूरे करने का होश आखिरी समय में आया और आनन-फानन में कर्मचारियों को काम में जुट जाने की हिदायत दे दी गई.

घटना वाले शहर दमोह में भी टीकाकरण का लक्ष्य पूरा किया जा रहा है, जिसके तहत बीते 12 मार्च को आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक तीन, चार, छह और नौ सिविल वार्ड में बच्चों का टीकाकरण किया गया. दो वर्ष तक की आयु के बच्चों को डीपीटी, खसरा और टिटनेस के टीके लगाए गए. टीका लगाने का काम एएनएम यानी नर्स स्तर की स्वास्थ्य कार्यकर्ता दुर्गा तिवारी ने किया. टीका लगने के बाद देर रात को कुछ बच्चों की तबियत अचानक बिगड़ गई और उन्हें सामान्य से ज्यादा उल्टी-दस्त होने लगे. इस पर कुछ बच्चों को रात में ही और कुछ को दूसरे दिन सुबह दमोह के ज़िला अस्पताल में भर्ती कराया गया. 13 मार्च को अस्पताल में रोशनी (पुत्री भूरे गोंड, आयु एक वर्ष), आरती (पुत्री मुन्ना ठाकुर, आयु 11 माह) और गौरव (पुत्र राजीव विश्वकर्मा, आयु नौ माह) की मौत हो गई. इसके बाद अरमान नामक एक और बच्चे की मौत हो गई. बच्चों के अभिभावकों ने रोना-धोना शुरू कर दिया. कुछ देर बाद लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया. जानकारी मिलते ही सबसे पहले ज़िला कलेक्टर आरए खंडेलवाल अस्पताल पहुंचे और उसके बाद मुख्य ज़िला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आरके श्रीवास्तव. दोनों अधिकारियों ने बच्चों के परिजनों को सांत्वना दी और बीमार बच्चों के बेहतर उपचार के आदेश दिए.

इसके बाद डॉ. श्रीवास्तव ने निर्देश दिए कि जहां कहीं टीकाकरण के लिए वैक्सीन भेजी गई है, उसका उपयोग न किया जाए और नई वैक्सीन आने तक टीकाकरण रोक दिया जाए. डॉ. श्रीवास्तव ने बताया कि बच्चों की मौत के कारणों की जांच कराई जाएगी और वैक्सीन को जांच के लिए दिल्ली या पुणे की प्रयोगशाला में भेजा जाएगा.

डीपीटी, ख़सरा और टिटनेस जैसी बीमारियों पर रोकथाम की गरज से चलाया गया टीकाकरण अभियान दमोह ज़िले के चार बच्चों की मौत से दाग़दार हो गया. यही नहीं, इस घटना ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त मनमानी, निरंकुशता और भ्रष्टाचार से भी परदा उठा दिया है.

नगर के प्रतिष्ठित और अनुभवी चिकित्सकों का कहना है कि गर्मी के कारण वैक्सीन ख़राब हो गई होगी और इस जानकारी से अनभिज्ञ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अथवा नर्स ने उसी ख़राब वैक्सीन से टीकाकरण कर दिया होगा, जिसके दुष्प्रभाव से बच्चों की तबियत अचानक बिगड़ गई और कुछ की मौत हो गई. शायद उन बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत क़मज़ोर रही होगी. दूसरे दिन अरमान नामक बच्चे की मौत होने पर मामला और भी ज्यादा गंभीर हो गया और लोगों में स्वास्थ्य विभाग के ख़िलाफ गुस्सा बढ़ने लगा. जानकारों का कहना है कि टीकाकरण के लिए दवा को जिस मानक यंत्र में रखकर लगाना चाहिए, वह उसमें नहीं रखी गई थी. स्वास्थ्य सेवाओं के जानकारों का कहना है कि बच्चों को टीका लगाने का काम डॉक्टरों की देखरेख में प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा किया जाता है और उपयोग करने से पहले दवा डॉक्टर को दिखाई जाती है. जब डॉक्टर दवा को प्रमाणित कर देता है, तभी उससे टीकाकरण किया जाता है.

आखिर टीके मौत का कारण कैसे बने? इस बारे में अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि टीकाकरण की वैक्सीन तापमान के मामले में संवेदनशील होती है, इसलिए उसे हमेशा शून्य से 20 डिग्री के तापमान पर रखा जाता है. इस तापमान से बाहर निकालने के बाद वैक्सीन का इस्तेमाल दो से तीन घंटे के भीतर कर लिया जाना चाहिए, वरना बाद में तापमान बढ़ने से वैक्सीन गर्म हो जाती है, जो शरीर के लिए घातक हो सकती है. इस मामले में भी शायद ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रहती. विभाग उन्हें सामान्य प्रशिक्षण देकर काम करने के लिए भेज देता है. उनके कामकाज पर कोई निगरानी भी नहीं रखी जाती. मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में घटिया दवाइयों की ख़रीद और एक्सपायर्ड दवाइयों के उपयोग की शिकायतें जब-तब आती रहती हैं. अस्पतालों में कई बार दवा घोटाला दबाने के लिए बड़ी मात्रा में दवाइयों को नष्ट भी किया जाता है. इन सारे गोरखधंधों के बीच चार बच्चों की मौत जैसे संगीन मामले में सिर्फ एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को दोषी बताकर दमोह ज़िले और राज्य के स्वास्थ्य संचालनालय के आला अफसर अपनी ज़िम्मेदारी से नहीं बच सकते. लोगों की मांग है कि मानवाधिकार आयोग, बाल अधिकार आयोग और लोकायुक्त को इस संगीन मामले को संज्ञान में लेना चाहिए और इसकी गहन छानबीन करानी चाहिए. इसके अलावा जांच के बाद दोषी लोगों को उचित दंड दिया जाना चाहिए.

feedback@chauthiduniya.com

सरैया के यासीन परोरा आज रिक्शा चला रहे हैं, वहीं नूरी और इमरान पान की दुकान. कभी इनके ख़ुद के करघे हुआ करते थे.

बनारसी साड़ी उद्योग

बुनकरों की हालत बदतर, सरकार उदासीन

टूटा ताना बिखरा बाना, घर में बचा नहीं जब दाना,
फांसी के फंदे पर झूल कर, दूसरी दुनिया में खोजा ठिकाना.

सुरेंद्र अग्निहोत्री

कवि अग्निवेद को इस कविता की राह पर चलते हुए बीते वर्ष वाराणसी के गौरगांव निवासी बुनकर सुरेश राजभर पत्नी हीरामनी एवं सात वर्षीय पुत्र छोटू की हत्या करके स्वयं फांसी पर झूल गया. क़र्ज़ के बोझ तले दबे सुरेश के सामने जीने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था. मऊ के ग्राम अतरारी निवासी बुनकरों से विद्युत बकाया की वसूली के लिए तहसीलकर्मियों ने उनका जमकर उत्पीड़न किया. अनेक बुनकरों के विरुद्ध फ़र्ज़ी मुक़दमे दर्ज़ कर दिए गए. इन घटनाओं को लेकर प्रदेश विधानसभा में समाजवादी पार्टी सहित अनेक विपक्षी दलों ने मायावती सरकार को घेरा, लेकिन बुनकरों की आत्महत्या की वजह भुखमरी मानने से इंकार करते हुए सरकार ने पल्ला झाड़ लिया. चदौली, मऊ, आजमगढ़, टाडा, मऊरानीपुर, ललितपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, भदोही एवं पिलखुआ में बुनकर गंभीर संकट से गुज़र रहे हैं. चंदौली के दुलईपुर सतपोखरी गांव में हथकरघा बुनकरों की समस्याओं पर जनसुनवाई में अनेक हैरतअंगेज तथ्य उभर कर आए. रेशमी वस्त्र बनाने वाले कारीगर परंपरागत हुनर छोड़ दिहाड़ी मज़दूरी कर रहे हैं. क़र्ज़ का बोझ उन्हें न तो जीने देता है और न मरने देता है. सरकारी योजनाएं फाइलों में कैद होकर रह गईं. सस्ता सूत और रेशम कहीं नहीं मिलता. नजीर और कबीर भी बनारसी ताने–बाने से जुड़े थे. इनकी पहचान दुनिया में है. बावजूद इसके नजीर और कबीर के वंशज क़रीब डेढ़ दशक से मुफ़लिसी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं. आलम यह है कि पूर्वांचल के लाखों बुनकर मुफ़लिसी के शिकार हैं. सरैया के यासीन परोरा आज रिक्शा चला रहे हैं, वहीं नूरी और इमरान पान की दुकान. कभी इनका ख़ुद का करघा हुआ करता था. यासीन और इमरान तो उदाहरण मात्र हैं. अकेले बनारस में लाखों बुनकर हालात के मारे हैं. चौदहों के सरदार मकबूल हसन कहते हैं कि कौम की बेहतरी के लिए सभी सियासी दलों से बात की गई, लेकिन सभी से आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला. जाड़े की ठिठुरती सर्द रात में हवा में पसरे सन्नाटे के बीच सीलन भरी झरती हुई मिट्टी की दीवार से सटकर करघे पर बाना बुनते बुनकर बस किसी तरह अपना वक़्त काट रहे हैं. बुनकर नेता अनवारुल हक कहते हैं कि किसानों का बिजली का बिल माफ कर दिया गया, मगर बुनकरों का नहीं. कभी बकाया बिजली बिल तो कभी हाउस टैक्स को लेकर बुनकरों को परेशान किया जा रहा है. उनसे तरह–तरह से वसूली की जा रही है. आलमीन सोसायटी के अध्यक्ष परवेज कादिर कहते हैं कि शासन से जो भी योजनाएं आईं, उनका क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हुआ. हथकरघों पर 16–16 घंटे काम करने वाला बुनकर ग़रीबी के गर्त में घुसता चला गया, मगर पावरलूम और चीन से आयातित मशीनों पर नक़ली बनारसी साड़ी तैयार करने वालों की कोठियां तनती चली गईं. बुनकर अब्दुल कुद्दूस कहते हैं कि पहले से बदहाल बुनकरों के पास अब खाने तक का ठिकाना नहीं है.

असली पर नक़ली ने फेर दिया पानी

नक़ली चमक–धमक और पैकिंग के दम पर बाज़ार में बिकने वाली बनारसी साड़ी ने हुनर के बल पर रात–दिन मेहनत करके कला को ज़िंदा रखने वाले बुनकरों की ज़िंदगी में ज़हर घोल दिया है. मशीनों से चंद मिनटों में नक़ली उत्पाद बना देने वाले मिलावटखोरों और नक्कालों ने श्रम के पसीने की बूंदों को मोती मानने वाले लोगों के अरमानों पर डाका डालने का जो नया खेल खेला है, उसने पूरे पूर्वांचल को अपने आगोश में ले लिया है. बंद होता करघा और टूटता बाना रोज एक मौत की ख़बर सुना जाता है. हैंडलूम बनारसी साड़ियों की बेजोड़ कला पावरलूम साड़ियों के आगे भी टिक सकती थी, पर इसे धोखाधड़ी का शिकार होना पड़ा. पावरलूम की रेशमी साड़ियां हैंडलूम के नाम से बिकने लगीं. इससे बड़ा धक्का तब लगा, जब उदारीकरण की नीतियों के चलते चीन से सस्ता रेशमी धागा और फिर सस्ता रेशमी वस्त्र धड़ल्ले से भारत आने लगा. चीनी रेशमी धागे ने पावरलूम के लिए सस्ता कच्चा माल जुटाया, जबकि बनारसी हैंडलूम महंगे देशी बंगलौरी धागे पर निर्भर था. चीन से जरदोजी की मशीनें भी आ गईं, जिससे बनारस के प्रसिद्ध हाथ से जरदोजी (जरी–ब्रोकेड) के काम को धक्का पहुंचा. सूरत के व्यवसायियों ने मौक़े का फ़ायदा उठाया और सस्ते चीनी कपड़े एवं मशीनी जरदोजी से तैयार रेशमी साड़ियां बाज़ार में छा गईं. ग्राहक सस्ते के चक्कर में फंस गए और बनारस का परंपरागत हस्तकरघा बुनकर बर्बाद होता चला गया. वर्ष 2000 से 2005 के बीच चीन से कपड़े का आयात लगभग 15 लाख मीटर से बढ़कर नौ करोड़ मीटर हो गया. लगभग 60 प्रतिशत बनारसी हैंडलूम बुनकर अपना पुश्तैनी व्यवसाय छोड़ चुके हैं. सदियों से चलती आई इस हस्तकला को सरकारी एवं ग़ैर सरकारी संस्थाओं के प्रयासों से बचाया जा सकता है. हैंडलूम कपड़े की परिचायक हैंडलूम मार्क योजना यद्यपि 2006 से जारी है, पर आमतौर पर न तो इसके बारे में बुनकरों को पता है और न ग्राहकों को.

ललितपुर जनपद का बुढ़वार गांव चंदेरी साड़ी बनाने के लिए सारी दुनिया में मशहूर है. चंदेरी साड़ी पहनने से सुंदरता में भले ही निखार आए, लेकिन इसे ताना–बाना के माध्यम से बुनने वाले बुनकरों की ज़िंदगी में स्याह अंधेरा व्याप्त है. कई परिवार चंदेरी साड़ी बुनने के काम में लगे हैं. बुनकरों के परिवारों की आर्थिक हालत इस कदर शोचनीय है कि लगता ही नहीं, यही लोग अपने हाथों से हज़ारों रुपये में बिकने वाली चांदी की जरी एवं रेशम की मखमली साड़ी बुनते हैं. सूत व्यापारियों एवं साड़ी निर्माताओं के लिए 16–16 घंटे खटने के बाद भी मुश्किल से दो जून की रोटी पाने वाले बुनकर बिचौलियों की हेराफेरी के शिकार हैं. आर्थिक शोषण और तंगहाली ने बुनकरों को इतना निर्मम बना दिया है कि वे अपने छोटे–छोटे बच्चों को स्कूल भेजने या खेलने–कूदने देने के बजाय उन्हें दिन भर अपने साथ लगाए रहते हैं. अपनी हालत पर दुःखी और आहत मंज़िल कहते हैं, हम सरकार से भीख नहीं मांगते. दुःख है तो सरकार के रवैये का. एक साड़ी बुनने में चार से सात दिन का समय लगता है, वह भी तब, जब घर के सदस्य भी सहयोग करें. बदले में मज़दूरी मिलती है सौ से डेढ़ सौ रुपये तक. एक बुनकर परिवार के मुखिया अलीमुद्दीन ने बताया कि परिवार में सात सदस्य हैं. इस काम में दो सदस्य हनीफ एवं राशिद लगे हैं, जो बड़ी मेहनत के बाद साठ से अस्सी रुपये रोज़ कमा पाते हैं. चंदेरी साड़ी का निर्माण करने वाले बुनकरों को सरकार की ओर से कोई सुविधा नहीं मिलती. अतीत में ललितपुर जनपद के अंतर्गत आने वाला क़स्बा चंदेरी अब मध्य प्रदेश में है, जिसके कारण बुनकर दोनों ओर से ठगे जाते हैं.

रेशम विकास समिति बनारसी वस्त्र उद्योग संघ के संयोजक गगनेंद्र कुमार केडिया बताते हैं कि 2003 में जब रेशम पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी थी, तभी इसकी सुनवाई के दौरान संघ ने इसका निम्नलिखित कारणों से प्रबल विरोध किया था:

1. देश में चीनी रेशम की गुणवत्ता का वीवोल्टीन रेशम उत्पादित ही नहीं होता.

2. देशी रेशम और चीनी रेशम का उपयोग अलग–अलग है. अतः इसके आयात से देशी रेशम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता.

3. देश में रेशम की मांग (28000 टन) और उत्पादन (1800 टन) में जो 10000 टन का अंतर है, उसे केवल चीन से आयात द्वारा ही पूरा किया जा सकता है.

4. चीन स्वयं चाहता है कि भारत में चीनी रेशम का दाम इतना ऊंचा रहे कि इससे भारत में बना रेशमी कपड़ा मूल्य प्रतिस्पर्धा में चीन द्वारा निर्यातित रेशमी वस्त्रों के मुक़ाबले बाज़ार में न टिक सके. 2003 में रेशम पर लगी एंटी डंपिंग ड्यूटी के बाद चीन से आयातित रेशमी वस्त्रों के आयात में 400 प्रतिशत की वृद्धि हुई. इससे देश में रेशमी वस्त्रों का उत्पादन लुप्तप्राय हो गया. यह उद्योग गत 6 वर्षों से भीषण मंदी की चपेट में है. न जाने कितने बुनकरों ने आत्महत्या कर ली और कर रहे हैं. कई वाराणसी से पलायन कर गए और बहुतेरे अन्य रोज़गारों में लग गए.

5. एंटी डंपिंग ड्यूटी रेशम पर नहीं, रेशमी वस्त्रों पर लगाई जाए, जिससे देश में बनने वाले रेशमी वस्त्र मूल्य स्पर्धा में आयातित रेशमी वस्त्रों से मुक़ाबला कर सकें. पूरे विश्व में कच्चे माल (रेशम) पर आयात शुल्क कम होता है और तैयार माल (रेशमी वस्त्र) पर अधिक होता है. लेकिन सरकार की गाड़ी विपरीत दिशा में चल रही है. यहां रेशमी वस्त्रों पर केवल 10 प्रतिशत आयात शुल्क है, जबकि रेशम पर 30 प्रतिशत.

बनारस का प्रतिनिधित्व

वर्ष 2003 में जब रेशम पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई, तब बनारसी वस्त्र उद्योग संघ और सिल्क ट्रेड एसोसिएशन के विचार भी आमंत्रित किए गए और उन्हें सुनवाई की प्रक्रिया में भी बुलाया गया. बनारस की, जो आयातित रेशम का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी के नवीनीकरण की प्रक्रिया में पूरी तरह उपेक्षा कर दी गई. न तो बनारस से इस उद्योग के किसी प्रतिनिधि के विचार आमंत्रित किए गए, न ही समीक्षा बैठक में किसी को बुलाया गया.

feedback@chauthiduniya.com

जनता को ठगने का महामुक़ाबला

राजेश एस कुमार

क्या सरकार टीवी चैनलों को इसलिए लाइसेंस देती है कि वे जनता को बेवकूफ बनाकर पैसे कमाएं? क्या सरकारी अधिकारियों को पता नहीं है कि उनके द्वारा जारी लाइसेंस का इस्तेमाल देश की जनता को मूर्ख बनाने में किया जा रहा है? रात के बारह बजते ही कई चैनलों पर ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिन पर लाइव लिखा होता है. पर सच्चाई यह है कि उक्त सभी कार्यक्रम रिकॉर्डेड होते हैं. चौथी दुनिया ने इन कार्यक्रमों के टेलीकास्ट के दौरान जब इन चैनलों के दफ्तरों में फोन करके असलियत जाननी चाही तो पता चला कि वहां तो सिर्फ़ टेप प्ले करके छोड़ दिया गया है और स्टूडियों में कोई शूट नहीं चल रहा है. हमारी सरकार से मांग है कि ऐसे चैनलों का लाइसेंस रद्द करे, जो कुछ कंपनियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी करते हैं. और, देश की जनता से हम अपील करते हैं कि टीवी पर आने वाले किसी भी शो में फोन या एसएमएस का बहिष्कार करें.

दरअसल जब टेलीविजन की शुरुआत हुई थी, तब दूरदर्शन ने लोगों को साफ़–सुथरा मनोरंजन परोसने का ज़िम्मा उठाया था. यही वजह है कि हम लोग, नुक्कड़, रामायण और चंद्रकांता जैसे कार्यक्रम लोगों के जेहन में आज भी ताज़ा हैं. फिर केबल चैनल का दौर आया. इस दौर में रात होते ही पुराना और क्लासिक सिनेमा चलने लगा, पर जैसे ही मार्केटिंग, विज्ञापन एवं टीआरपी जैसे फैक्टर्स इन चैनलों की सफलता और असफलता तय करने लगे तो मानों चैनलों का काम ही बदल गया. वे दर्शकों का मनोरंजन करने के बजाय उनसे रुपये ऐंठने की नई–नई स्कीम बनाने लगे. आजकल टेलीविजन में अजीबोग़रीब मुकाबलों के ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं, जो यह साबित करने पर तुले हैं कि भारत की जनता मूर्ख और बेवकूफ है. म्यूजिक का मुक़ाबला, बिग बॉस और दूसरे रियलिटी शो तो जनता के एसएमएस के ज़रिए करोड़ों की कमाई करने में कामयाब होते हैं. मज़ेदार बात यह है कि वोट देने वाले ज़्यादातर दर्शकों को पता भी नहीं चलता है कि यह कार्यक्रम दरअसल कला और छुपे टैलेंट को देश के सामने लाने के बजाय चैनलों की मोटी कमाई का ज़रिया मात्र है.

सबसे पहले उन कार्यक्रमों के बारे में बताते हैं, जो रात के बारह बजते ही देश की जनता को मूर्ख बनाते हुए एसएमएस और फोन कॉल के जरिए जनता की जेबों पर डाका डालते हैं. ऐसे कार्यक्रमों की लंबी फेहरिस्त है. कुछ कार्यक्रम अंकों को दिखाकर उनका जोड़–भाग और कैलकुलेशन करवाते हैं, कुछ फिल्मी पहेली हल कराने के नाम पर अमिताभ बच्चन का चेहरा पहचानने जैसे कठिन सवाल पूछते हैं तो कुछ बड़े ब्रांड्स के प्रोडक्ट की नीलामी के नाम पर विज्ञापन भी कर लेते हैं. वैसे सारी पहेलियों और सवालों के जवाब बहुत आसान होते हैं, लेकिन इन चैनलों पर आने वाले जवाब सुनकर लगेगा कि हमारे देश में गणित की पढ़ाई होती ही नहीं है. ताज्जुब की बात यह है कि 4+18+30–15=? जैसी पहेली को हल करने में पूरे देश को तीन–चार दिन लग जाते हैं और हद तो तब हो जाती है, जब बिना सही जवाब के कार्यक्रम बंद कर दिया जाता है. अगर कोई जीत भी गया तो न उसका फोन नंबर दिखाया जाता है और न उसकी तस्वीर. ऐसा इसलिए, क्योंकि सभी कार्यक्रम महज़ छलावा हैं. लाइव के नाम पर रिकॉर्डेड कार्यक्रम दिखाकर जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है. कार्यक्रमों में क्रिकेट खिलाड़ी या बॉलीवुड की किसी हस्ती की तस्वीर दिखाई जाती है. फिल्मी हीरोइनों के दांत और आंख दिखाए जाते हैं और जनता से चैनल अपील करते हैं कि इन्हें पहचानो. वैसे इन तस्वीरों को इस तरह पेश किया जाता है कि कोई भी बच्चा सही जवाब दे दे. जैसे सचिन और द्रविड़ के चेहरे को मिलाकर पेश करके उन्हें पहचानने के लिए कहा जाता है. अब भला ऐसा कौन होगा, जो सचिन और द्रविड़ का चेहरा न पहचान सके. ऐसे ही अक्षय कुमार की तस्वीर दिखाकर पहचानने के लिए कहा जाएगा. अधिक एसएमएस के लालच में हिंट दी जाती है कि इस अभिनेता ने फिल्म सिंह इज किंग में काम भी किया है. मजेदार बात यह कि दो–तीन दिन बीत जाते हैं, लेकिन एक भी सही जवाब नहीं मिल पाता. चैनल बार–बार लगातार किसी भिखारी की तरह फोन करने की अपील करता रहता है और पहले से रिकॉर्ड किए गए ग़लत जवाब दिखाता रहता है, ताकि लोग समझें कि प्रतियोगिता में और लोग भी लगे हुए हैं. एक ख़ूबसूरत एंकर लगातार यह कहती रहती है कि आपको लाइन पर बने रहना है. आगे यह प्रलोभन देती है कि अगले कॉलर को 3000 रुपये मिलेंगे. ग़लत जवाब देने वाले को भी इनामी राशि का कुछ भाग दिए जाने की झूठी घोषणा की जाती है. फिर कई मिनटों तक कोई कॉल नहीं ली जाती. मतलब यह कि लोग तीन हज़ार रुपये के लालच में लगातार फोन करते रहते हैं और फोन बिजी होने पर एसएमएस करना शुरू कर देते हैं.

उक्त सभी फोन नंबर पीआरएम लाइंस के होते हैं. इस पर कॉल करने पर सामान्य कॉल रेट से कई गुना अधिक यानी छह से बारह रुपये प्रति मिनट ख़र्च होते हैं. फोन करने वाले दर्शक की कॉल को होल्ड पर रखा जाता है. ज़ाहिर है, जितना लंबा इंतज़ार, उतना ही ज़्यादा लंबा फोन बिल. फोन लगे या न लगे, फोन करने वाले का पैसा ज़रूर लग जाता है. कुछ फोन लाइंस में पहले से रिकॉर्डेड संदेश फीड होते हैं और अलग से जवाब तलब किया जाता है. एसएमएस के धंधे से होने वाली कमाई का कुछ हिस्सा फोन कंपनियों को जाता है और बाकी पैसा उनके खाते में जाता है, जिनके नाम से उक्त नंबर रजिस्टर होते हैं. उक्त कार्यक्रम लाइव नहीं होते. सभी कॉल्स चैनल के स्टूडियो के बजाय अलग–अलग कंपनियों के कॉलसेंटर में जाती हैं. जनता को लगता है कि वह चैनल के एंकर से बात कर रही है. जबकि सच्चाई यह है कि वह कॉल किसी कंप्यूटर में जाती है. कॉलसेंटर्स से रिकॉर्डेड टेप टीवी चैनलों में जाते हैं. मतलब यह है कि जो लोग यह समझ कर फोन करते हैं कि वे चैनल के लाइव प्रोग्राम में फोन कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं होता कि इस खेल के पीछे क्या चल रहा है. यह बात और है कि धोखाधड़ी करने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत में एक डिस्क्लेमर लगाकर चैनल सारी ज़िम्मेदारियों से ख़ुद को अलग कर लेते हैं.

अब बात ऐसे कार्यक्रमों की, जिन्हें हम रियलिटी शो कहते हैं. उक्त रियलिटी शो कभी डांस तो कभी संगीत का महामुक़ाबला के नाम से जनता के सामने आते हैं. सर्वश्रेष्ठ गायक कौन है, यह जनता के वोट से तय होता है. नए–नए फॉर्मेट और नए–नए अंदाज़ में लोगों से एसएमएस मंगवा कर टीवी प्रोड्यूसर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं. रही बात हार और जीत की, सच पूछिए तो जनता के वोट का कोई मतलब ही नहीं होता है. हाल में हुए एक ऐसे ही मुक़ाबले में जनता के वोट से शान जीते थे, लेकिन जज की कुर्सी पर बैठे जावेद अख्तर ने एक ऐसा कारनामा किया कि उनकी अकेली च्वाइस लाखों–करोड़ों देशवासियों के वोटों पर भारी पड़ गई. हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जावेद साहब कोई संगीतकार नहीं हैं. अगर शंकर महादेवन को जजों के फ़ैसले से ही जीतना था, तो जनता से लाखों की संख्या में एसएमएस क्यों मंगवाए गए? क्या इन रियलिटी शोज का एकमात्र मक़सद पैसा कमाना है? एसएमएस भेजने वाली जनता का भी हक़ है कि उसे बताया जाए कि किसी भी रियलिटी शो में कितने एसएमएस आए और कहां से आए? एसएमएस और फोन का यह खेल अभी रियलिटी टीवी तक सीमित है, लेकिन संकेत तो यह मिल रहे हैं कि टीवी सीरियलों में भी अब एसएमएस का खेल शुरू होने वाला है. बालिका वधू सीरियल में आनंदी के ठीक होने के लिए टीवी चैनल ने प्रार्थनासभाओं का ड्रामा शुरू किया है. वह दिन दूर नहीं, जब सीरियलों में सबसे पसंदीदा कलाकार को मारकर यह एसएमएस मंगवाया जाएगा कि वह फिर से जिंदा होनी चाहिए या नहीं.

टीवी चैनलों और ख़ासकर न्यूज़ चैनलों की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है. लोगों का मीडिया पर भरोसा है. चंद पैसों और टीआरपी की ख़ातिर इन ज़िम्मेदारियों को ताख पर नहीं रखा जा सकता. इस तरह की धोखाधड़ी के खेल में शामिल होकर न्यूज़ चैनल अपनी साख खोते जा रहे हैं और उनसे जनता का भरोसा उठता जा रहा है. ऐसे में इस भरोसे को कायम रखने की ज़िम्मेदारी भी न्यूज़ चैनलों की है. देश में क़ानून का राज चलता है, यही माना जाता है. धोखाधड़ी, चोरी और जालसाजी के लिए सजा का प्रावधान है. जब कोई छोटा–मोटा चोर पांच हज़ार रुपये की चोरी करता है तो अदालत उसे सजा देती है. अगर यही चोरी करोड़ों की हो, हर रोज़ हो और इसे करने वाले देश की बड़ी–बड़ी कंपनियां और टीवी चैनल्स हों तो क्या सरकार को उन पर कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? अगर इन चैनलों पर जल्द लगाम नहीं लगाई गई तो यह लूट यूं ही जारी रहेगी.

rajeshy@chauthiduniya.com

ग्रेहाउंड्स में ख़ुफ़िया जानकारियों का चतुराई से इस्तेमाल होता था, जहां चूक होने की आशंका कम होती थी.

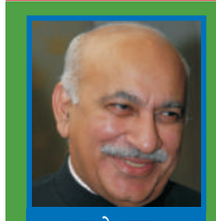

एम जे अकबर

गृहमंत्री जी, आप अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग नहीं सकते

अधिकतर ग़लतियां अक्सर दिमाग़ से शुरू होती हैं. यह सभी जानते हैं कि सुरक्षा मामलों में गृहमंत्री पी चिदंबरम अमेरिकी नीति के बड़े हिमायती हैं. इस नीति में अपनी कमियों पर ख़ास ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन सुरक्षा का यह फ़ार्मूला अमेरिका में मुख्य रूप से विदेशी चुनौतियों से निबटने के लिए तैयार किया गया था, न कि अंदरूनी समस्याओं से मुक़ाबला करने के लिए. सुरक्षा मामलों में अमेरिका देशी और बाहरी, दोनों ही चुनौतियों से मुक़ाबला कर रहा है, लेकिन इसके लिए वह एक ही तरीक़े का इस्तेमाल नहीं करता. वहां सीआरपीएफ जैसी कोई सुरक्षा एजेंसी नहीं है. फिर वहां माओवादियों ने इलाक़ों पर अपना अधिकार भी नहीं जमाया है, आम लोगों के रिहायशी इलाक़ों को अपने गढ़ में तब्दील नहीं किया है. उनके लड़ाके वर्दियों में नहीं होते और न ही घर लौटते समय उन्हें वर्दियां बदलने की ज़रूरत होती है. अमेरिका इराक या अफ़ग़ानिस्तान में अपनी स्थिति मज़बूत करने की अहमियत को समझता है, लेकिन महत्व के हिसाब से यह उसका तीसरा और आख़िरी विकल्प है. यही वजह है कि या तो ऐसा हो नहीं पाता या फिर इसकी प्रक्रिया इतनी धीमी हो जाती है कि यह नज़र नहीं आता. सुरक्षा एजेंसियों की सारी ऊर्जा विरोधियों के खात्मे और अपनी स्थिति मज़बूत करने में ही ख़त्म हो जाती है. इसका मतलब यह है कि इन एजेंसियों का सबसे बड़ा दायित्व ख़ुद अपनी सुरक्षा करना हो जाता है. चिदंबरम का तर्क है कि माओवादियों के प्रभुत्व वाले इलाक़ों में तब तक कोई विकास कार्य नहीं हो सकता, जब तक कि उन्हें वहां से खदेड़ न दिया जाए. कोबरा फोर्स का गठन इसी इरादे से किया गया था. बाद में इसका नाम बदल कर स्पेशल एक्शन फोर्स कर दिया गया. शायद इसकी वजह यह थी कि आम आदमी के लिए बनी सरकार की सुरक्षा एजेंसी के नाम का सांपों की सबसे विषैली प्रजाति से मेल खाना हो सकता है कुछ लोगों को अतार्किक लगा हो. लेकिन आप नाम ही तो बदल सकते हैं, दिमाग़ी सोच और मानसिकता का क्या करेंगे.

गृह मंत्रालय का यह बहुप्रचारित अभियान अनिश्चितता के भंवर में ऐसे उलझ गया है कि हर चीज़ अस्पष्ट नज़र आती है. सरकार के एक विज्ञापन में लिखा गया है, मैं ग़रीब था और मेरे पास रोज़गार का कोई साधन नहीं था, इसलिए मैं माओवादियों के साथ हो लिया. बंदूक़ मेरी पहचान बन गई. मैंने लोगों की हत्याएं कीं, उनकी गर्दनें काट डालीं, विस्फोट कर पुलों और स्कूलों को उड़ाया. लेकिन मेरे पास अब भी कमाई का कोई साधन नहीं है. मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते. मैं न ही अपने परिवार के साथ रह सकता हूं और न ही अपने खेतों में जा सकता हूं. इसके बाद नज़र आता है संदेश, हिंसा का त्याग करें, विकास में साझीदार बनें. यदि इस तथ्य को दरकिनार भी कर दें कि माओवादी सुबह की चाय के साथ हाई प्रोफाइल अंग्रेजी अख़बार नहीं पढ़ते, तो भी यह विज्ञापन हिंसा के रास्ते को त्यागने के बजाय माओवादियों के साथ हो लेने का आमंत्रण ज़्यादा नज़र आता है.

मैं ग़रीब था और अमीरों को और ज़्यादा अमीर बनाने के अलावा सरकार हमारे लिए कुछ ख़ास नहीं कर पाई. ऐसी हालत में बंदूक़ उठाने के अलावा

शायद दूसरा विकल्प भी नहीं है. कोई विकास में साझीदार तभी हो सकता है, जबकि विकास कार्य हों. दंतेवाड़ा मुंबई का मेरीन ड्राइव नहीं है. ग़रीब लोग ग़रीब भले हैं, लेकिन मूर्ख नहीं हैं. उन्हें किसी अलादीन के चिराग से किसी जादू की उम्मीद नहीं है, जो पल भर में उनके सारे अरमानों को पूरा कर दे, लेकिन सरकारी टालमटोल और पक्षपात को वे अपनी क़िस्मत भी नहीं मान सकते. माओवाद की रगों में बहने वाला ख़ून ग़रीबी का है. यदि हम माओवाद को ख़त्म करना चाहते हैं तो पहले ग़रीबी को ख़त्म करना होगा. सुरक्षा के प्रति अमेरिकी दृष्टिकोण का एक विकल्प और भी है, पहले सशक्तिकरण, फिर शिक्षा और अंत में खात्मा. लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी समस्या के समाधान के लिए बंदूक़ आख़िरी विकल्प हो सकती है, न कि पहली. साथ ही यह भी कि कोई सरकार ग़रीब लोगों का विश्वास हासिल करके ही उन्हें बंदूक़ उठाने से रोक सकती है. इस सुझाव में कुछ ऐसा नहीं है, जो अनोखा हो. यदि प्रणब मुखर्जी या एके एंटोनी गृहमंत्री होते तो इस तर्क को बड़ी आसानी से मान लेते. आंध्र प्रदेश में अलग-अलग दलों के नेतृत्व वाली एनटी रामाराव, चंद्रबाबू नायडू और राजशेखर रेड्डी की सरकारों ने सफलतापूर्वक इस नीति को आज़माया था. उन्होंने जगह-जगह पर पुलिस बूथ बनाए और उसे ग्रेहाउंड (शिकारी कुत्ते) नाम दिया, जो लोगों की बोलचाल से जुड़े थे. लोगों का विश्वास हासिल करने के लिए उन्होंने रक्षक वाला रवैया अपनाया, न कि आक्रमणकारी वाला. अनुभवी पुलिस अधिकारियों ने गृह मंत्रालय को सुझाव दिया था कि कोबरा फोर्स का मुख्यालय हैदराबाद में होना चाहिए, ताकि यह इसी पुरानी रणनीति को आत्मसात कर सके, लेकिन चिदंबरम नहीं माने. उन्होंने इसे व्यक्तिगत पहल मान लिया और कोबरा-एसएएफ का मुख्यालय दिल्ली में ही बना रहा.

ग्रेहाउंड्स में ख़ुफ़िया जानकारियों का चतुराई से इस्तेमाल होता था, जहां चूक होने की आशंका कम होती थी. इसी के साथ आर्थिक विकास की गाड़ी को कमज़ोर-पिछड़े लोगों की ओर मोड़ दिया गया. सद्भावनापूर्ण पक्षपात विकास का मूलमंत्र बन गया. इसमें कोई शक़ नहीं कि यह प्रक्रिया धीमी थी. नक्सलवाद को अगले दो-तीन सालों में ख़त्म कर दिया जाएगा, ऐसे बड़े-बड़े दावे नहीं किए गए. महत्वपूर्ण बात यह भी रही कि आंध्र प्रदेश के किसी भी राजनीतिज्ञ ने संकट की घड़ी में उल्टे-सीधे बयान देकर ख़ुद को नेपोलियन साबित करने की कोशिश नहीं की. अनुभवी राजनीतिज्ञ जानते हैं कि केवल एक अतिशयोक्तिपूर्ण बयान भी किसी बड़ी पहल को टांय-टांय फिस्स कर सकता है. ज़्यादा दिन नहीं हुए, जब पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए चिदंबरम ने मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार को राज्य में नक्सलवाद के लिए ज़िम्मेदार ठहराया था. उन्होंने शायद यह कल्पना भी नहीं की होगी कि कुछ ही दिनों के अंदर यह बयान उनके गले की फांस बन जाएगा. लेकिन दंतेवाड़ा के लिए आख़िर ज़िम्मेदार कौन है? चिदंबरम बहाने तलाश करने में व्यस्त हैं, वह यह दावा करते फिर रहे हैं कि यह केंद्र और राज्य सरकारों का संयुक्त अभियान था. लेकिन यह सही नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जंगलों की खाक छान रही कोबरा या स्पेशल एक्शन फोर्स को आदेश दिल्ली से मिल रहे थे. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हेनरी ट्रूमैन ने अपनी मेज पर एक प्लेट लगाई थी, जिस पर लिखा था, यहां आकर सारी ज़िम्मेदारियां ख़त्म हो जाती हैं. यह वाक्य इतना प्रसिद्ध हो गया कि आम लोगों की बोलचाल का हिस्सा बन गया. एक अन्य अमेरिकी राष्ट्रपति काल्विन कुलिज ने इससे ज़्यादा तर्कसंगत प्लेट अपनी मेज पर लगाई, मैं अपनी ज़िम्मेदारियां दूसरे पर नहीं थोपूंगा.

अपनी ज़िम्मेदारियों को दूसरों पर थोपने का मतलब देश को गुमराह करना है.

feedback@chauthiduniya.com

बाल शोषण के ख़िलाफ़ जनजागरण ज़रूरी

बाल शोषण आज हमारे लिए कोई अंजान शब्द नहीं है, बल्कि यह आधुनिक समाज का एक विकृत और ख़ौफ़नाक सच बन चुका है. मौजूदा दौर में निर्दोष एवं लाचार बच्चों को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने की घटनाएं इतनी आम हो चुकी हैं कि अब तो लोग इस ओर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते. जबकि वास्तविकता यह है कि बाल शोषण बच्चों के मानवाधिकारों का उल्लंघन है. हाल में देश में पहली बार बाल शोषण के मामलों की गहराई से जांच-पड़ताल के लिए कुछ पहल की गई हैं. 13 राज्यों में किए गए इस अध्ययन से संभव है कि इससे संबद्ध सभी पक्षों जैसे, परिवार, समुदाय, समाज एवं सरकार को मामले की गंभीरता और उसकी वास्तविकता का पता चले.

केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा यूनीसेफ के सहयोग से कराए गए इस अध्ययन में कई संवेदनशील तथ्य सामने आए हैं. यह पहला मौक़ा है, जब सरकार ने इतने विस्तृत पैमाने पर बाल शोषण के विवादित मसले पर कोई पहल की है. अध्ययन के परिणामों से जो बात सबसे ज़्यादा उभर कर सामने आई है, वह यह है कि 5 से 12 साल तक की उम्र के बच्चे बाल शोषण के सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं. हैरत की बात यह है कि हर तीन में से दो बच्चे कभी न कभी शोषण का शिकार रहे हैं. अध्ययन के दौरान लगभग 53.22 प्रतिशत बच्चों ने किसी न किसी तरह के शारीरिक शोषण की बात स्वीकारी तो 21.90 प्रतिशत बच्चों को भयंकर शारीरिक उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा. इतना ही नहीं, क़रीब 50.76 प्रतिशत बच्चों ने एक या दूसरे तरह की शारीरिक प्रताड़ना की बात कबूली. बात इतने पर ही ख़त्म नहीं होती. मंत्रालय की अध्ययन रिपोर्ट के मुताबिक़, देश का हर दूसरा बच्चा भावनात्मक शोषण का भी शिकार है.

आमतौर पर माना जाता है कि बाल शोषण का मतलब बच्चों के साथ शारीरिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार है, लेकिन सीडीसी (कंसलटेंसी डेवलपमेंट सेंटर) के अनुसार, बच्चे के माता-पिता या अभिभावक द्वारा किया गया हर ऐसा काम बाल शोषण के दायरे में आता है, जिससे उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता हो या ऐसा होने की आशंका हो या जिससे बच्चा मानसिक रूप से भी प्रताड़ित महसूस करता हो. भारत में हालत ऐसी है कि अक्सर बाल शोषण के वजूद को ही को सिरे से नकार दिया जाता है, लेकिन सच यह है कि ख़ामोश रहकर हम बच्चों के साथ दुर्व्यवहार की वारदातों को बढ़ावा ही दे रहे हैं. देश में बाल शोषण की घटनाओं को ऐसे अंजाम दिया जाता है कि दोषी के साथ-साथ पीड़ित बच्चे भी खुलकर सामने नहीं आते. पीड़ित बच्चे शर्मिंदगी के चलते कुछ भी बोलना नहीं चाहते. इसके पीछे भी हमारी सामाजिक बनावट और मानसिकता काफी हद तक ज़िम्मेदार है. हम भी ऐसे बच्चों को कुछ अलग नज़र से देखने लगते हैं. संभवत: इसी लज्जा के चलते उन्हें दुनिया की निगाहों में ख़ौफ़ नज़र आता है. पश्चिमी देशों में हालात ऐसे नहीं हैं. शिक्षा के कारण वहां का समाज और वहां के बच्चे निडर होकर अपनी बात कह सकते हैं. वहां के बच्चों में कम से कम इतना साहस तो होता ही है कि वे दुनिया को खुलकर अपनी आपबीती बता सकें.

पारंपरिक रूप से भारत में बच्चों के लालन-पालन और उनकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी

फोटो-*प्रभात पाण्डेय*

परिवार एवं सगे-संबंधियों की होती है. देश के संविधान में बच्चों के लिए कई तरह के मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है, लेकिन इन अधिकारों को व्यवहार में लागू करने के मामले में ज़रूरत के अनुसार अहमियत नहीं दी जाती है. इसके बावजूद बाल शोषण जैसी गंभीर सामाजिक समस्या को देश में अक्सर दरकिनार कर दिया जाता है. शर्म की बात यह है कि संगीन अपराध की श्रेणी में आने वाले इस कृत्य के वजूद से ही हम इंकार कर देते हैं. जबकि सच्चाई यह है कि समस्या की गंभीरता के नज़रिए से इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहल करने की ज़रूरत है. देश में बाल शोषण के ख़िलाफ़ बनाए गए क़ानूनों की भरमार है, लेकिन इसमें कई गंभीर खामियां भी हैं. आज ज़रूरत इस बात की है कि सरकार, समाज एवं आम नागरिक मिलकर बच्चों के अधिकारों के महत्व को समझें और इसे पूरा करने के लिए मिलकर क़दम उठाएं. अंतरराष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस (19 नवंबर) या बाल दिवस (14 नवंबर) के मौक़ों पर इसके लिए केवल हामी भर देने से कुछ नहीं हो सकता. इस दिशा में लगातार प्रयास करते रहने की ज़रूरत है, ताकि क़ानून और समाज इसके प्रति जागरूक हों. बाल शोषण से संबंधित अनेक ऐसे तथ्यपरक आंकड़े हैं, जो आगे की कार्रवाई के लिए आधार का काम कर सकते हैं. अब वह समय आ चुका है कि हम बाल अधिकारों के प्रति गंभीर हों.

बाल शोषण से निबटने के लिए जो क़ानूनी ढांचा उपलब्ध है, लोगों को उसकी जानकारी नहीं है और न कोई ऐसी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा इस जागरूकता को बढ़ाया जा सके. नतीजतन यह सामाजिक अभिशाप लगातार और गंभीर रूप धारण करता जा रहा है. यह इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे ही हमारा भविष्य हैं और उनके हितों की सुरक्षा किए बग़ैर एक सुरक्षित समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती. इसके लिए सबसे पहले हमें अपने नज़रिए में बदलाव लाना होगा, समस्या के वजूद को स्वीकार करना होगा. यह इतना आसान नहीं है. यह भी संभव है कि बदलाव के लिए लंबी प्रतीक्षा करनी पड़े, लेकिन यदि हम सभ्य समाज होने का दावा करते हैं तो हमें कभी न कभी शुरुआत तो करनी ही होगी.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

अपने हुए पराए

समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडीज के बारे में उनके दोस्तों की अपील पढ़ी. आपने इसे छापकर एक अच्छी पहल की. बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बिहार में जनतादल (यू) की सरकार है. नीतीश कुमार चाहें तो जॉर्ज साहब का इलाज अमेरिका में हो सकता है, लेकिन इस मुद्दे पर उनकी चुप्पी भी रहस्यमय है. अभी भी वक्त है, देश का एक शीर्ष नेता बसपा संस्थापक कांशीराम की तरह एक कमरे में कैद है. आपने सही लिखा कि सारी उम्र गुलामी के खिलाफ संघर्ष करने वाले जॉर्ज आज अपनों के गुलाम बनकर रह गए हैं.

-मनोज कुमार शुक्ल, *वैरी दरियाव, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश.*

आम आदमी की मुश्किल

आज आम आदमी की मुश्किलें समझने वाला कोई नहीं है. कॉमनवेल्थ खेलों के नाम पर दिल्ली सरकार ने जनता पर मनमाने कर थोप दिए हैं. शीला दीक्षित कहती हैं कि दिल्ली के विकास के लिए कीमत तो जनता को चुकानी ही पड़ेगी. यदि कोई यह कीमत दे पाने की स्थिति में न हो तो? पहले लोग आलू में पानी डालते थे, आज पानी में आलू डालते हैं. दालों की कीमतें फिर आसमान छूने लगी हैं. आम आदमी 8.5 प्रतिशत की विकास दर देखे या रोटी-सब्जी?

-अरुण सरोहा, *छात्र-हिंदी पत्रकारिता, दिल्ली विश्वविद्यालय.*

सच्चे लगते हैं बाबा रामदेव

मैं चौथी दुनिया का नियमित पाठक हूं. बाबा रामदेव पर आधारित कवर स्टोरी पढ़ी. अच्छा लगा. भारत तो हमेशा से साधु-संतों और योगियों का देश रहा है. हालांकि आधुनिक दौर के बाबाओं ने हमारी इस गौरवशाली परंपरा को बार-बार कलंकित किया है, लेकिन बाबा रामदेव इन सबसे अलग नजर आते हैं. राजनीति के मैदान में उतरने के उनके प्रयासों का परिणाम क्या होगा, यह अंदाजा लगाना तो अभी मुश्किल है, लेकिन उनकी बातों में सच्चाई और दृढ निश्चय नजर आता है.

-रोशन, *वसंत विहार, नई दिल्ली.*

बाबाओं पर भरोसा कैसे करें

क्या हमारे देश में राजनेताओं की इतनी कमी हो गई है कि बाबा रामदेव योग छोड़ राजयोग के लिए कमर कस रहे हैं? यह सच है कि देश में नेताओं की जो जमात अभी मौजूद है, उसमें विरले ही ऐसे हैं जिनकी नेकनीयती पर आंखें मूंद कर भरोसा किया जा सके, लेकिन इन बाबाओं पर भी कैसे भरोसा किया जाए. हाल के दिनों में हमने कई ऐसे उदाहरण देखे हैं, जिनमें बाबाओं और धर्मगुरुओं के कुकृत्य सामने आए हैं. इसमें कोई शक नहीं कि बाबा रामदेव पर ऐसे कोई आरोप नहीं हैं, लेकिन राजनीति के दलदल में फंसकर वह कब तक इससे बचे रह पाएंगे, यह कहना मुश्किल है.

-श्रवण गर्ग, *लुधियाना पंजाब.*

क्या चाहते हैं बाबा रामदेव

पहले योग, फिर धनयोग और अब राजयोग. आखिर बाबा रामदेव करना क्या चाहते हैं. उन्होंने योग के माध्यम से पहले लोगों के दिलों में जगह बनाई, फिर उसे अपने व्यवसाय में तब्दील कर दिया. इससे मन नहीं भरा तो एक मीडिया हाउस के मालिक बन बैठे. देश-विदेश में संपत्ति जमा की और अब राजनीति के अखाड़े में कूदने के लिए तैयार हो रहे हैं. एक चेहरे के ऊपर इतने चेहरे. देश में बहुरुपिये राजनीतिज्ञों की पहले ही कौन सी कमी है कि रामदेव योग का चोला उतार कर राजनीति का लबादा ओढने की कोशिश कर रहे हैं.

-संजय सिंह, *बाड़मेर, राजस्थान.*

गडकरी पर आलेख अच्छा लगा

भाजपा के नए अध्यक्ष नितिन गडकरी पर आपका आलेख अच्छा लगा. इसमें कोई शक नहीं कि अध्यक्ष चुने जाने से पहले गडकरी भाजपा के कद्दावर नेताओं में शामिल नहीं थे. महाराष्ट्र के बाहर कुछ ही ऐसे लोग हैं जो उनके नाम से भी वाकिफ हों. वह तो आरएसएस की कृपा हुई कि वह इतने बड़े पद पहुंच गए, लेकिन उन्हें देखने से नहीं लगता कि वह अभी भी अपनी हैसियत के साथ न्याय कर रहे हैं. आपका कहना बिल्कुल सही है कि देश की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के मुखिया का इस तरह पेश नहीं आना चाहिए. इससे न केवल उनकी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल पर बुरा असर पड़ेगा, बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिहाज से भी अच्छा नहीं है.

-रामचंद्र पौडियाल, *देहरादून, उत्तराखंड.*

सबको शिक्षा सुनिश्चित करे सरकार

मैं चौथी दुनिया का नियमित पाठक नहीं हूं, लेकिन 12-18 अप्रैल वाले अंक में समान शिक्षा प्रणाली पर उमाशंकर मिश्र का लेख पढ़ने का मौका मिला. कितनी हैरानी की बात है कि देश को आजाद हुए 60 साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन संपूर्ण साक्षरता का लक्ष्य अभी भी कोसों दूर है. इससे भी आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि सरकार अपनी विफलता छुपाने के लिए निजी क्षेत्र और कॉरपोरेट घरानों के सहारे शिक्षा के अधिकाधिक निजीकरण की संभावनाएं तलाश रही है. अमीर बच्चों को तो इससे फायदा होगा, उन्हें देश में रहकर ही विदेशी विश्वविद्यालयों की डिग्री हासिल हो जाएगी, लेकिन उनका क्या होगा जो शुल्क न दे पाने के कारण सरकारी स्कूलों में भी नहीं जा पाते हैं. क्या उनके लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है. कॉरपोरेट घरानों के शिक्षा क्षेत्र में प्रवेश से पहले सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए.

-विकास कुमार, *आरा, बिहार*

आप अपने स्वतंत्र विचार तथा प्रतिक्रियाएं हमें इसी पते पर भेजें.
संपादक, चौथी दुनिया, एफ-2, सेक्टर-11 नोएडा, (उत्तर प्रदेश) पिन-201301
ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

जब तोप मुक़ाबिल हो

संतोष भारतीय

संभलिए, अभी संभलने का मौक़ा है

किसी भी सरकार को सरकार की तरह व्यवहार करना चाहिए. सरकार का मतलब होता है कि वह देश में रहने वालों के जीवन की, भोजन की, काम की, स्वास्थ्य की और उनके सुख–शांति से रहने की आज़ादी की गारंटी दे. जो सरकार इसे जितना ज़्यादा पूरा करती है, वह उतनी ही अच्छी सरकार मानी जाती है. सरकार से यह भी अपेक्षा रहती है कि वह परिपक्व मानसिकता के साथ काम करेगी. जो सरकार समग्र दृष्टि या परिपक्व मानसिक मस्तिष्क का पालन नहीं करती, वह या तो सीमा पर दुश्मन के भड़काने की वजह से युद्ध की स्थिति पैदा कर लेती है या फिर देश में निहित स्वार्थों के उकसाने पर क़त्लेआम करने पर आमादा हो जाती है. हमें भरोसा रखना चाहिए कि हमारी सरकार ऐसी नहीं है.

हमें अफ़सोस टेलीविज़न और अख़बारों पर ज़रूर होता है. मीडिया में ऐसे लोग बड़ी संख्या में आ गए हैं, जिन्हें न देश की बुनियाद की समझ है, न देश के सामाजिक विकास की गति की, न देश की समस्याओं की, न देश के दर्द और तक़लीफ़ की और न ही पत्रकारिता के बुनियादी सिद्धांतों की. दंतेवाड़ा की घटना के बाद, जिसमें 76 जवान मारे गए, अचानक टेलीविज़न चैनलों और अख़बारों के एक बड़े हिस्से की ओर से सरकार को सलाह दी जाने लगी है कि वह नक्सलवादियों या माओवादियों के ख़िलाफ़ युद्ध की घोषणा करे, उन पर हमला करे और उन्हें नेस्तनाबूद कर दे.

ऐसा लग रहा है, जैसे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और मीडिया के एक हिस्से का मिलाजुला रोदन हो रहा है. एक जैसा स्वर देखकर नहीं लगता कि भाजपा विपक्षी दल है और कांग्रेस सत्ताधारी. मीडिया का यह हिस्सा जो नेस्तनाबूद करने की सलाह दे रहा है, ठीक वैसे ही व्यवहार कर रहा है, जैसा वह पाकिस्तान से जुड़ी किसी घटना पर करता है. इतना बहादुर मीडिया है कि जब चीन से जुड़ी कोई ख़बर आती है तो इन्हें सांप सूंघ जाता है और उस समय इन्हें राष्ट्र का कोई खयाल नहीं आता.

सरकार को, नेस्तनाबूद करने की सलाह देने वाले बेशर्म पत्रकार इस बात पर कतई शर्मिंदा नहीं होते कि उन्होंने क्यों देश की समस्याओं पर ध्यान देना छोड़ दिया है. वे क्या स्थितियां बनीं, जिनकी वजह से देश के डेढ़ सौ से ज़्यादा ज़िलों में दंतेवाड़ा जैसे स्थान विकसित हो गए. इन ज़िलों में विकास के लिए गया पैसा किसकी जेब में गया. सड़क, अस्पताल, स्कूल क्यों नहीं बने. यहां पुलिस क्यों ग्रामीण क्षेत्र में जाने से डरती है. क्या सारे ग्रामीण नक्सलवादी या माओवादी हैं. इन विषयों और कारणों पर ध्यान देने की जगह मीडिया का एक हिस्सा मूर्खों की तरह सरकार को सलाह देने में लगा है.

सरकार में, उसकी रणनीति में कितनी कमियां हैं, इसे गिनाने बैठें तो कब अंत होगा कह नहीं सकते. एक अधिकारी कहता है कि जंगल वार की ट्रेनिंग जवानों को नहीं है. दूसरा कहता है कि पूरी ट्रेनिंग है. गृहमंत्री कहता है कि वायु सेना का इस्तेमाल करेंगे तो वायुसेना अध्यक्ष कहते हैं कि हम सीमा पर बाहरी दुश्मनों से रक्षा के लिए बने हैं. पुलिस कहती है कि अर्द्धसैनिक बल उनसे न मदद लेते हैं और न अपने मूवमेंट की जानकारी उन्हें देते हैं, जबकि अर्द्धसैनिक बलों का कहना है कि पुलिस के लोग माओवादियों से न केवल मिले हैं, बल्कि अपनी रक्षा के लिए उन्हें पैसे तक देते हैं. क्या सच है, यह ये तथाकथित सलाहकार नहीं बताते, क्योंकि बताने के लिए इन्हें वहां जाना पड़ेगा या संवाददाताओं को भेजना पड़ेगा, जहां माओवादी हैं.

इन सलाहकार चैनलों के आंखें फाड़कर डरावना चेहरा बनाकर जनता को भयभीत करने वाले उपदेशक पत्रकारों को हम बताना चाहते हैं कि जब वे वहां जाएंगे तो उन्हें ऐसे लोग मिलेंगे, जिनके तन पर कपड़े ही नहीं हैं, न आदमियों के और न औरतों के. उनके पास शराब बनाने और पीने की एक ही वजह है कि वे शराब पीकर अपने दर्द, तक़लीफ़ भूले रहते हैं. उनके पास खाना नहीं है, काम नहीं है, है तो केवल बीमारी और मौत. हज़ारों लोगों के बीच कौन माओवादी है, इसे पहचानना असंभव है. तो क्या उस एक माओवादी को मारने के लिए हज़ारों का कत्ल कर दिया जाए. माओवादियों की ताक़त है, लोगों की ग़रीबी, लोगों की भूख, लोगों का रेंग–रेंग कर जीना. इसमें जब माओवादी कहते हैं कि अच्छी ज़िंदगी नहीं मिलती तो उसके लिए संघर्ष करो और मर जाओ, तो लोग उनकी बात मानते हैं.

उनके पास शराब बनाने और पीने की एक ही वजह है कि वे शराब पीकर अपने दर्द, तक़लीफ़ भूले रहते हैं. उनके पास खाना नहीं है, काम नहीं है, है तो केवल बीमारी और मौत. हज़ारों लोगों के बीच कौन माओवादी है, इसे पहचानना असंभव है. तो क्या उस एक माओवादी को मारने के लिए हज़ारों का कत्ल कर दिया जाए.

इसका मुक़ाबला करना है तो केवल एक रास्ता है, उन्हें पकड़ना जो इस स्थिति के लिए ज़िम्मेदार हैं. ज़िम्मेदारी तय होनी चाहिए. पिछले पचास सालों से इन डेढ़ सौ ज़िलों में रहे कर्मचारी, आईएएस अफ़सर और राजनेता, जिन्होंने मिलकर माओवाद के लिए दंतेवाड़ा जैसे स्थान विकसित किए हैं, पहचानने होंगे. आज और अभी से सरकारों को पहले इन ज़िलों में और साथ ही पूरे देश में ईमानदारी से विकास और समन्वित विकास की योजना बनानी होगी और बिना वक़्त खोए लागू करनी होगी. इसकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए. अफसर, एमएलए, मंत्री जो दोषी निकले, उसे सजा मिलनी चाहिए.

लेकिन ज़िम्मेदारी कौन तय करेगा. मनरेगा जैसी ग्रामीण योजना भ्रष्टाचारियों के लिए लूट का अवसर लेकर आई है. प्रधानमंत्री की चौदह सूत्री योजना में क्या हो रहा है पता नहीं. प्रधानमंत्री ख़ुद सौ दिनों का रिपोर्ट कार्ड देखना ही भूल गए हैं तो ज़ारी क्या करेंगे. अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने की जगह हिटलर की तरह सोचने वाले राय दे रहे हैं, सभी को मार डालेंगे और उन्हें मीडिया के नालायक छोटे हिटलर समर्थन दे रहे हैं कि सबको नेस्तनाबूद कर दो. इन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि समस्याओं का तूफ़ान अपने साथ एक विद्रोह लिए बढ़ता चला आ रहा है. आकाश में उठती गुस्से की आंधी उन्हें पहचाननी चाहिए, जो सरकार चला रहे हैं या जो चलाना चाहते हैं. अगर इस आंधी में तमाशबीन भी शामिल हो गए तो संकट की तस्वीर और बदसूरत हो जाएगी.

इन तथाकथित मीडिया सलाहकारों से कहना चाहेंगे कि सत्ता के दलालों की जगह जनता के हितों के पहरेदार बनें, उसी में शान है. सत्ता से विनम्र अनुरोध है कि बिना दिमाग़ का उतावलापन आपके लिए नई परेशानियां पैदा करेगा. बेहतर हो आप समस्याएं सुलझाइए, लोगों के दर्द–तक़लीफ़ दूर कीजिए, विकास की ईमानदार कोशिश कीजिए और देश को देश के रहने वालों की नज़र से देखिए. ये अपने देश के परेशान–दुखी लोग हैं, किसी दुश्मन देश के रहने वाले नहीं. मूर्खता भरे फ़ैसलों से ऐसा वक़्त नहीं आना चाहिए, जब गोली चलाने वाले हुक्म मिलने पर कहें कि हम अपने ही लोगों पर गोली नहीं चलाएंगे.

संभलिए, अभी संभलने का मौक़ा है.

संपादक
editor@chauthiduniya.com

नक्सल समस्या : राष्ट्रीय स्तर पर नीति बनाने की ज़रूरत

सौमित्र मोहन

छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा ज़िले में नक्सली हमले में एक साथ 76 लोगों की मौत ने देश में लगातार गंभीर बनती जा रही इस समस्या की ओर फिर से ध्यान खींचा है. नक्सलियों की बढ़ती ताक़त, उनके प्रभाव क्षेत्र में विस्तार और मारक क्षमता के मद्देनज़र यह ज़रूरी है कि हम इस समस्या की गंभीरता पर नए सिरे से विचार करें. गुरिल्ला युद्ध कला की तकनीकों में पारंगत नक्सलियों के पास चाक–चौबंद ख़ुफ़िया तंत्र मौजूद है. प्रेरक नेतृत्व, प्रतिबद्ध कैडर, प्रशिक्षित लड़ाके और अत्याधुनिक हथियार, नक्सली आज इस हालत में हैं कि सुरक्षा एजेंसियों की ख़ुफ़िया जानकारियां भी आसानी से उन्हें उपलब्ध हो जाती हैं और वे अपनी मर्ज़ी से कभी भी और कहीं भी हमला कर सकते हैं.

नक्सलियों का प्रभाव क्षेत्र देश के 170 से भी ज़्यादा ज़िलों में फैला है. भूमि सुधारों की कमी, जंगलों के विनाश, माइनिंग या सिंचाई क्षेत्र की विकास परियोजनाओं के चलते विस्थापित हुए आदिवासियों एवं छोटे किसानों और सबसे बढ़कर विकास में क्षेत्रीय असंतुलन का फ़ायदा उठाकर आज वे इस हालत में पहुंच गए हैं. सबसे ज़्यादा हैरानी तो यह जानकर होती है कि नक्सल प्रभावित ज़िलों का दो–तिहाई हिस्सा आदिवासी बहुल क्षेत्रों में ही है. आदिवासी एवं छोटे किसान नक्सलियों के कैडर का सबसे अहम हिस्सा हैं. उनके साथ कुछ डॉक्टर, इंजीनियर और बुद्धिजीवी वर्ग से ताल्लुक रखने वाले लोग भी हैं, जो विध्वंसक कार्रवाइयों में उनके लिए विशेषज्ञ सलाह उपलब्ध कराते हैं. प्रतिबद्ध एवं प्रेरक नेतृत्व, कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज और राष्ट्रविरोधी ताक़तों से मिल रही मदद के सहारे नक्सली आज इतने मज़बूत हो चुके हैं कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए गंभीर ख़तरा बन गए हैं.

कॉम्पैक्ट रिवॉल्यूशनरी ज़ोन (सीआरजेड) के नाम से मशहूर रेड कॉरिडोर नेपाल से शुरू होकर भारत के कुछ सबसे पिछड़े इलाक़ों तक फैला है. इसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र के कुछ इलाक़े शामिल हैं. नक्सलियों का पहला लक्ष्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र के कुछ ज़िलों तक फैले दंडकारण्य वन क्षेत्र में अपने लिए एक बेस एरिया तैयार करना है. द एनेमी विदिन, द फिफ्थ कॉलमिस्ट एवं द ट्रॉजन हॉर्स जैसे नामों से पुकारे जाने वाले नक्सली पिछड़े और अविकसित इलाक़ों में ज़्यादा सक्रिय हैं, क्योंकि इन इलाक़ों में रहने वाले लोग उनकी बातों–प्रोपेगेंडा पर आसानी से यक़ीन कर लेते हैं. शिक्षा एवं विकास से दूर ग़रीबी एवं भूख से बेहाल भोली–भाली जनता नक्सलियों के बहकावे में आकर उनकी बातें मानने के लिए तैयार हो जाती है. आदिवासी बहुल कई इलाक़ों

में तो नक्सलियों का समानांतर प्रशासन भी चलता है. वे स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और जन अदालतों का संचालन करते हैं तो ठेकेदारों, खदान मालिकों एवं उद्योगपतियों और यहां तक कि सरकारी अधिकारियों से भी लेवी के रूप में पैसा वसूल करते हैं.

आम जनता का समर्थन मिलता रहे, इसके लिए नक्सली जंगली इलाक़ों में विकास की किसी भी परियोजना का विरोध करते हैं. लोगों के दिलों में यह भय पैदा करते हैं कि विकास परियोजनाओं का असल उद्देश्य उनकी ज़मीन और अन्य संपत्तियों पर क़ब्ज़ा करना है. सच्चाई यह है कि सरकार की विकास परियोजनाएं यदि सफल हो जाएं तो नक्सली आम जनता को उसके ख़िलाफ़ गोलबंद करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे. अल्प विकास और पिछड़ापन निर्दोष जनता को सरकार के ख़िलाफ़ खड़ा करने में नक्सलियों के लिए कारगर हथियार का काम करता है. यह स्थापित सत्य है कि नक्सलियों के तार देश के अंदर और बाहर अलगाववादी और विध्वंसकारी शक्तियों के साथ भी जुड़े हैं. उक्त ताक़तें नक्सलियों की बेजा मांगों, जैसे आत्म निर्णय का अधिकार आदि का समर्थन करती हैं, जो देश की एकता और अखंडता के लिहाज से खतरनाक है. ऐसे सिद्धांत और आदर्शों के साथ उनके लिए राष्ट्रविरोधी तत्वों के साथ गठजोड़ करना मुश्किल नहीं होता. सच तो यह है कि एक राष्ट्र के रूप में भारत की अवधारणा पर उंगली उठाकर वे राष्ट्रीय अस्मिता और इसके अस्तित्व के लिए वैचारिक स्तर पर भी खुली चुनौती पेश करने में सक्षम होते हैं. नक्सलियों के लिए नक्सलवाद कोई समस्या नहीं है, बल्कि वे तो इसे देश की कई समस्याओं के समाधान के रूप में देखते हैं. ख़बरों के मुताबिक़, नक्सलियों ने नेपाल में सक्रिय माओवादियों से भी गठजोड़ कर लिया है और पश्चिम बंगाल के दोआर क्षेत्र और सिक्किम के तराई इलाक़ों में पीढ़ियों से रह रहे नेपालियों के दिलों में भारत के ख़िलाफ़ असंतोष पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं. उनका उद्देश्य लोगों को आत्म निर्णय के अधिकार के लिए उकसा कर आंदोलन खड़ा करना है, ताकि बड़े पैमाने पर हिंसा फैलाई जा सके. आज नक्सली पाकिस्तानी ख़ुफ़िया एजेंसी आईएसआई के हाथों का भी खिलौना बन चुके हैं. आईएसआई नक़ली दवाओं और नोटों के प्रसार जैसे राष्ट्रविरोधी कामों के लिए उनका इस्तेमाल कर रहा है. इसके बदले में वह नक्सलियों को अत्याधुनिक हथियार और विस्फोटकों के निर्माण एवं इस्तेमाल की तकनीक मुहैया कराता है. सुरक्षाबलों द्वारा ज़ब्त किए गए हथियारों से यह बात प्रमाणित हो चुकी है. मौजूदा माहौल में कट्टरवादी इस्लामी ताक़तों और मार्क्सवादी–लेनिनवादी ताक़तों के बीच एक विस्तृत गठजोड़ की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन सबका एक ही उद्देश्य है, भारत के लिए परेशानियां खड़ी करना.

नक्सलवाद की समस्या से निबटने के लिए हमें अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है. क़ानून और व्यवस्था से बढ़कर हमें इसके सामाजिक–आर्थिक आयामों को ध्यान में रखते हुए नए सिरे से रणनीति बनानी होगी. यदि हम वास्तव में इस समस्या से मुक़ाबला करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुआयामी रणनीति बनानी होगी. दूरदर्शी योजना और केंद्र एवं नक्सल प्रभावित राज्यों के बीच सामंजस्य स्थापित कर एक राष्ट्रीय नीति का निर्माण इस दिशा में पहला क़दम हो सकता है. पुलिसबलों का आधुनिकीकरण करने भर से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें उनकी संख्या बल का भी विस्तार करना होगा. बेहतर प्रशिक्षण, क्षेत्रीय ज़रूरतों के मुताबिक़ रणनीति का निर्माण और सुरक्षाबलों का बेहतर मनोबल स्तर नक्सली ख़तरे से निबटने में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

छत्तीसगढ़ में प्रयोग किए गए सलवाजुड़ूम, जिसमें स्थानीय लोगों को दो हज़ार रुपये के मासिक पारिश्रमिक पर स्पेशल पुलिस फोर्स के रूप में तैनात किया जाता था, की तर्ज पर पब्लिक पीस फोर्स का गठन जैसे क़दमों पर नए सिरे से विचार कर उसे बढ़ावा दिया जा सकता है. 2005 में दंतेवाड़ा में अस्तित्व में आए सलवाजुड़ूम का पिछला अनुभव इस काम में मददगार हो सकता है. जम्मू–कश्मीर के आतंक प्रभावित क्षेत्रों में ऐसी कोशिशें खासी सफल रही हैं और कोई कारण नहीं है कि देश के दूसरे हिस्सों में नक्सलियों से मुक़ाबला करने के लिए ऐसे प्रयास सफल नहीं हो सकते. आंध्र प्रदेश में इस्तेमाल किया गया ग्रेहाउंड प्रयोग भी इसका एक और उदाहरण है. लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऐसी कोशिशों से समाज का विभाजन न हो जाए, वरना इसके परिणाम ख़तरनाक भी हो सकते हैं.

इतना ही नहीं, नक्सलियों से मुक़ाबले के लिए बनाई जाने वाली किसी भी योजना में इससे प्रभावित लोगों का सहयोग और विश्वास हासिल करना अनिवार्य है, अन्यथा कोई भी रणनीति कारगर नहीं हो सकती. सरकारी एजेंसियों को नक्सलियों द्वारा बनाए गए सरकार के जनविरोधी चरित्र को ख़त्म करने के लिए भी प्रयास करने होंगे. हालांकि ऐसे प्रयास अभी भी जारी हैं, लेकिन उन्हें और भी गंभीरता एवं मज़बूती से अमल में लाना होगा. यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ग़रीबी, निरक्षरता और बेरोज़गारी उन्मूलन के लिए शुरू की गई सरकारी योजनाओं जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार योजना, एमपीएलएडी, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, स्पेशल कंपोनेंट प्लान, ट्राइबल सब–प्लान, इंटिग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोज़गार योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण रोज़गार योजनाओं का लाभ लक्षित लोगों तक पहुंच सके.

इसके अलावा नक्सल प्रभावित इलाक़ों के सर्वांगीण आर्थिक विकास के उद्देश्य से विशेष योजनाओं का निर्माण किए जाने की भी ज़रूरत है. यदि सरकार इस ओर ध्यान दे और लोगों का विश्वास हासिल करने की कोशिश करे तो नक्सलियों के प्रभाव वाले इलाक़ों में ख़ुफ़िया तंत्र को भी मज़बूत किया जा सकता है, जो इस गंभीर समस्या से निबटने में अहम भूमिका निभा सकता है.

(लेखक पश्चिम बंगाल में आईएस अधिकारी हैं. आलेख में व्यक्त विचार उनके अपने है और इनका सरकार के विचारों से कोई संबंध नहीं है.)

feedback@chauthiduniya.com

टॉयलेट के बाहर सिक्कों वाली मशीन लगी होगी, जिसमें हर बार टॉयलेट जाने के लिए यात्रियों को भुगतान करना होगा.

सूचना का अधिकार
जानने का अधिकार जीने का अधिकार
चौथी दुनिया की पहल

अब पेंशन की टेंशन नहीं

बिहार के जमालपुर से आर के निराला ने हमें पत्र के माध्यम से दो मामलों के बारे में सूचित किया है. दोनों मामले नगर परिषद जमालपुर से संबंधित हैं. पहला मामला चंपा देवी का है. चंपा देवी नगर परिषद जमालपुर में सफाई मज़दूर के तौर पर नियुक्त थीं. उनकी पेंशन का भुगतान अब तक नहीं हो पाया है, जबकि पटना हाईकोर्ट ने भी भुगतान का आदेश दे दिया है.

दूसरा मामला बेबी देवी का है, जिनके पति की मृत्यु नौकरी के दौरान हो गई थी, लेकिन उन्हें अब तक अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं मिल सकी. इन दोनों मामलों में कई समानताएं हैं, जैसे अधिकारियों और कर्मचारियों की लेटलतीफी, लालफीताशाही और अड़ियल रवैया. लेकिन, आरटीआई क़ानून ऐसे ही अधिकारियों–कर्मचारियों को सही रास्ते पर लाने का काम करता है. यहां पर इन दोनों मामलों का ज़िक्र इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि आमतौर पर सरकारी विभागों में अधिकांश मामले ऐसे ही होते हैं. बाबुओं की फाइल दबाऊ नीति के चलते आम आदमी परेशान होता रहता है. कभी पेंशन, कभी नौकरी तो कभी कोई अन्य मामला. सरकारी बाबू बिना रिश्वत लिए फाइल आगे नहीं बढ़ाते और बेवजह लोगों को दफ़्तर का चक्कर काटने को मजबूर करते हैं. तब ऐसे ही मामलों में आरटीआई (सूचना कानून) का असर दिखता है. अगर किसी सरकारी दफ़्तर में आपका भी कोई ऐसा ही मामला फंसा हो तो आप पहले एक साधारण आवेदन देकर अपनी शिक़ायत अधिकारी तक पहुंचाएं और याद करके आवेदन की प्राप्ति रसीद ले लें. साथ ही आवेदन की एक फोटो कॉपी भी अपने पास रखें. अगर सप्ताह, दस दिनों के भीतर आपके आवेदन पर कोई सुनवाई नहीं होती है तो फिर आप सूचना का अधिकार क़ानून के तहत एक आवेदन देकर अपने पहले वाले आवेदन पर हुई कार्रवाई के बारे में सूचना मांगें. ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि आरटीआई आवेदन डालते ही अधिकारी–कर्मचारी हरक़त में आ जाते हैं, क्योंकि क़ानून के मुताबिक़ उन्हें 30 दिनों के भीतर जवाब देना होता है. हमें विश्वास है कि यदि आप सूचना क़ानून का इस्तेमाल करते हैं तो आपका काम ज़रूर होगा, वह भी बिना रिश्वत दिए. इस अंक में हम उक्त दोनों मामलों से संबंधित एक आरटीआई आवेदन प्रकाशित कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल आप ऐसे मामलों के लिए कर सकते हैं. चौथी दुनिया आपकी किसी भी समस्या के समाधान या सुझाव देने के लिए हमेशा आपके साथ है. आप हमसे पत्र, ईमेल या फोन के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं.

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार कानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ई-मेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा
(गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश
पिन –201301 ई-मेलः
rti@chauthiduniya.com

किसी विभाग में लंबित मामले से संबंधित आवेदन

सेवा में, दिनांक...
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय का नाम....
पता....

विषय: सूचना का अधिकार कानून 2005 के तहत आवेदन

महोदय,
मैंने अपने मामले के संबंध में एक आवेदन आपके विभाग में जमा कराया था. (पूर्व में आपने जो साधारण आवेदन दिया था, उसकी कॉपी संलग्न करें) लेकिन अब तक मेरे आवेदन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. कृपया इस संबंध में मुझे निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराएं.

1. मेरे आवेदन पर हुई कार्रवाई की दैनिक प्रगति रिपोर्ट की एक सत्यापित कॉपी उपलब्ध कराएं.
2. उन अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम और पदनाम बताएं, जिनके पास मेरा आवेदन इस दौरान रहा. कृपया यह बताएं कि किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों के पास कितने वक्त तक मेरा आवेदन रहा और उन अधिकारियों/कर्मचारियों ने उस पर क्या कार्रवाई की?
3. मेरा आवेदन एक अधिकारी/कर्मचारी से दूसरे अधिकारी/कर्मचारी को जब-जब प्रेषित किया गया या प्राप्त किया गया, उसका प्रमाण उपलब्ध कराएं.
4. आपके विभाग के नियम/कानून/आदेश/दिशानिर्देश के मुताबिक ऐसे मामलों का निपटारा कितने दिनों के भीतर हो जाना चाहिए. उस नियम/कानून/आदेश/दिशानिर्देश की एक सत्यापित कॉपी उपलब्ध कराएं.
5. यदि अधिकारियों/कर्मचारियों ने मेरे आवेदन का निपटारा उक्त नियम/कानून/आदेश/दिशानिर्देश के तहत नियत समय के भीतर नहीं किया है तो क्या उक्त अधिकारी/कर्मचारी उक्त नियम/कानून/आदेश/दिशानिर्देश के न माने जाने के लिए दोषी हैं?
6. इन अधिकारियों/कर्मचारियों के रवैये की वजह से मुझे मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा. क्या उक्त अधिकारी/कर्मचारी मेरे मानसिक शोषण के लिए दोषी हैं?
7. इन अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, जिन्होंने उक्त सभी नियम/कानून/आदेश/दिशा-निर्देश का उल्लंघन किया है और जिसकी वजह से मुझे मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा. इन अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कब तक कार्रवाई की जाएगी?
मेरे आवेदन का निपटारा कब तक हो जाएगा?

मैं इस आवेदन के साथ दस रुपये का आवेदन शुल्क जमा कर रहा/रही हूं.

भवदीय
नाम....
हस्ताक्षर....
पता....

ज़रा हट के

एयरलाइन में टॉयलेट शुल्क

हवाई जहाज में टॉयलेट इस्तेमाल करने से पहले यात्रियों को अपनी जेब ढीली करनी होगी. मतलब यह कि आपको पैसे देने होंगे, इसलिए टॉयलेट इस्तेमाल करने से पहले ज़रा विचार कर लें. यह व्यवस्था शुरू की है आयरलैंड की रेयान एयर ने. ख़ास बात यह कि उसने अपने यात्रियों से टॉयलेट के लिए अतिरिक्त शुल्क वसूलना शुरू भी कर दिया है. रेयान एयर ने यात्रियों से 1.65 डॉलर और 1.44 डॉलर यानी क़रीब 73 और 65 रुपये वसूलने का फ़ैसला किया है.

टॉयलेट के बाहर सिक्कों वाली मशीन लगी होगी, जिसमें हर बार टॉयलेट जाने के लिए यात्रियों को भुगतान करना होगा. यह भुगतान यात्रियों के सामान और चेक इन फीस के अतिरिक्त होगा. साथ ही इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि एयरलाइन से कुछ विशेष टॉयलेट सुविधाएं हटाई जा सकती हैं. इस नई योजना के बारे में रेयान एयर के प्रवक्ता स्टीजफन मैक्ना मारा का कहना है, इसके ज़रिए हम यात्रियों की आदतों में सुधार करना चाहते हैं कि वे उड़ान से पहले और बाद में टॉयलेट करें. इसके बाद हम तीन में से दो टॉयलेट हटा सकेंगे और छह अतिरिक्त सीटों की जगह बना पाएंगे.

इंसानों के वेश में एलियंस!

एलियंस के बारे में सभी जानते हैं. अगर आपसे कोई यह कहे कि एलियंस भी हमारे बीच में रहते हैं. मतलब यह कि इंसानों के वेश में घूमते-फिरते हैं तो शायद आप चौंक जाएं, लेकिन इस बात का खुलासा एक सर्वेक्षण में हुआ है. यह सर्वे न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स द्वारा पूरे विश्व में किया गया, जिसमें 20 फ़ीसदी लोगों ने माना कि एलियंस हमारे बीच इंसानों की शक्ल में घूमते हैं. सर्वे में 22 देशों के 23 हज़ार लोग शामिल हुए. उनसे एलियंस की उपस्थिति के बारे में पूछा गया. भारत और चीन में 40 प्रतिशत से ज़्यादा लोगों का मानना है कि एलियंस पृथ्वी पर मनुष्यों के वेश में घूमते हैं. जबकि नीदरलैंड्स, स्वीडन और बेल्जियम के ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं मानते. यहां केवल 8 प्रतिशत लोग ही एलियंस की उपस्थिति पर विश्वास करते हैं.

सर्वेक्षण में हिस्सा लेने वाले लोगों में से 80 प्रतिशत को पक्का भरोसा है कि एलियंस हमारे बीच नहीं रहते. इपसोस मार्केट रिसर्च कंपनी केअधिकारी जॉन राइट का कहना है कि अगर सर्वेक्षण केपरिणामों को देखा जाए तो जिन देशों की जनसंख्या ज़्यादा है, वहां ज़्यादातर लोगों का मानना है कि एलियंस हमारे बीच हैं, लेकिन छोटी जनसंख्या वाले देशों में कम लोग ही ऐसा समझते हैं. हो सकता है कि एक छोटे देश में आप अपने पड़ोसी को ज़्यादा अच्छी तरह जानते हों. ज़्यादातर महिलाएं पड़ोसियों के हालचाल और सामाजिक मेलमिलाप में विश्वास रखती हैं. शायद इसलिए 17 प्रतिशत महिलाओं के मुक़ाबले 22 प्रतिशत पुरुष इस बात को मानते हैं कि हमारे आसपास इंसानों के वेश में एलियंस रहते हैं. इस बात पर विश्वास करने वाले ज़्यादातर लोगों की उम्र 35 साल से कम है, जबकि ऐसा न मानने वालों में ज़्यादा संख्या महिलाओं की है.

राशिफल

दिल्ली, 26 अप्रैल–02 मई 2010

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
इस सप्ताह थोड़ा सतर्क रहें. आपके किसी काम में विरोधी टांग अड़ा सकते हैं. वाहन चलाते समय चौकस रहें. कुछ जगहों पर आपको नुक़सान उठाना पड़ सकता है. संभल कर काम करें.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)
पढ़ने-लिखने में आपकी रुचि बढ़ेगी. इससे आपके ज्ञान में इज़ाफ़ा होगा. कुछ छोटी-मोटी परेशानियां सामने आ सकती हैं, लेकिन आप उनमें सफलता प्राप्त कर लेंगे. नौकरी में कुछ बदलाव हो सकता है. किसी दोस्त के साथ घूमने जाएंगे.

मिथुन (21 मई से 20 जून)
पारिवारिक जीवन में सुख-चैन रहेगा. क़र्ज़ से भी मुक्ति मिलेगी. आय के स्रोत बढ़ेंगे. आपको धैर्य से काम लेना होगा. व्यर्थ के ख़र्चों से बचने का प्रयास करें. ख़ूब मन लगाकर अपना काम करें. आने वाला समय अच्छा होगा.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)
दूसरों के कहने पर किसी तरह के बहकावे में न आएं. कभी-कभी आप दूसरों की बातों को बहुत तूल देते हैं. आपको यह समझना होगा कि विरोधी आपको परेशान करना चाहते हैं. परिवार में किसी का स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)
अपने ओरिजनल आइडियाज को किसी के साथ शेयर न करें. अपने दिमाग़ से ही हर समस्या का समाधान ढूंढें. दूसरे क्या कहते हैं, इसे ज़्यादा तूल न दें. समय आने पर आप ही सबसे आगे होंगे. यह समय मेहनत करने का है.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)
आप सभी कामों को समय पर ख़त्म करने में भरोसा रखते हैं. काम से मुक्त होने पर परिवार के साथ पिकनिक मनाने का कार्यक्रम बना सकते हैं. कुल मिलाकर यह सप्ताह अच्छा रहेगा. किसी समस्या से छुटकारा भी मिलने की संभावना है.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
आपके ज्ञान में बढ़ोत्तरी होगी. किसी परीक्षा की तैयारी के लिए अभी से जुटना होगा. नौकरी करने वाले लोगों के लिए समय आगे बढ़ने का है. आपको अपने सीनियर्स की गुडबुक्स में शामिल होना चाहिए, तभी जल्दी प्रोग्रेस कर सकते हैं.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
जो भी काम करें, काफी सोच-समझ कर ही करें. वरना, बाद में पछताना पड़ सकता है. किसी आर्थिक मामले में रुकावट आ सकती है. किसी मसले पर अपने ही लोगों से बहस हो सकती है.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
यात्रा के योग बनेंगे, जहां से आपको लाभ भी मिल सकता है. नए दोस्त बन सकते हैं. इस सप्ताह आप शॉपिंग का कार्यक्रम भी बनाएंगे, लेकिन बजट बनाकर ही चलें. वरना, आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
किसी व्यक्ति से आपकी बहस हो सकती है, लेकिन बहस न करके कोई और रणनीति अपनानी होगी. मन में सुख-शांति रहेगी और समय भी अच्छा गुज़रेगा. किसी नए काम की ज़िम्मेदारी भी आपको सौंपी जा सकती है.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)
दफ्तर में आपका प्रभाव बढ़ेगा. समय का सदुपयोग करने में आप काफी माहिर हैं. सभी काम आप समय पर पूरा कर लेंगे. कोई मांगलिक कार्य भी संभव है. अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)
यह सप्ताह आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा. जीवनसाथी और परिवार के बुज़ुर्गों का सहयोग भी मिलता रहेगा. लोग आपकी तारीफ करेंगे. रुटीन के कामों को समय पर निपटाने में सफल रहेंगे.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

निराश जनता मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए मजबूर है. घरों में बिजली के पंखे चलते रहें, इसके लिए लोग नए उपकरण ख़रीद रहे हैं तो अपने आसपास निगरानी रखने के लिए सिक्युरिटी गाड्र्स की सेवाएं ले रहे हैं.

हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा

एक राष्ट्र के रूप में आज हम जिन समस्याओं से रूबरू हैं, वह बेवजह नहीं है. आतंकवाद, बढ़ती बेरोज़गारी, ग़रीबी, शिक्षा का अभाव, संस्थाओं के बीच टकराव और सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने के लिए मची होड़ आदि सारी समस्याओं की जड़ में दशकों का कुशासन और देश के प्रति हमारी प्रतिबद्धता में कमी है. यदि विस्तृत नज़रिए से देखें तो उक्त सभी समस्याएं एक-दूसरे से जुड़ी हैं. बाहरी दबावों के चलते देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ें गहरी नहीं जम पाई हैं और यही समस्याओं का सबसे बड़ा कारण है. अभी हाल में मियां नवाज शरीफ ने 18वें संविधान संशोधन विधेयक पर जिस तरह अपना रुख़ अचानक बदल लिया, वह इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है. इससे पहले जेद्दाह में शरीफ के नए रूप को देखकर लगा कि वह वरिष्ठ राजनीतिज्ञ की अपनी भूमिका के प्रति गंभीर हैं, लेकिन 18वें संविधान संशोधन विधेयक पर उनके रवैये को देखकर यह ख़ुशी चंद लम्हों में ही काफूर हो गई. अब तो आलम यह है कि हम एक बार फिर 1990 के दशक के दिनों में पहुंच गए हैं, जब राजनीतिक पार्टियां राष्ट्रहित के बजाय एक-दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में ही लगी रहती थीं. इससे बेख़बर कि ऐसा करके वे ख़ुद अपने लिए भी पतन का रास्ता तैयार कर रही हैं, लेकिन इसके बाद स्थिति में सुधार के लक्षण नज़र आने लगे. ऐसा लगा, जैसे उक्त दल अब आत्मघाती नज़रिए को छोड़ चुके हैं. काश! ऐसा हो पाता. हक़ीक़त तो यह है कि वही पुराना रवैया एक बार फिर नज़र आने लगा है.

यह बात आसानी से हजम नहीं होती कि नवाज शरीफ ने यह क़दम अपने आप ही उठाया हो. इस बात को लेकर अभी भी कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रेस कांफ्रेंस से ठीक पहले किन लोगों ने उनसे फोन पर बात की, क्योंकि प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने जो कुछ भी कहा, उससे तो ख़ुद उनकी पार्टी के लोग भौंचक्के रह गए. हालांकि हम शरीफ से इस बात की उम्मीद नहीं कर सकते कि वह अपनी ग़लती मान लेंगे. वैसे भी प्रधानमंत्री के रूप में उनके दो कार्यकालों के दौरान उनकी छवि एक अक्खड़ और जिद्दी राजनीतिज्ञ की रही है. अब यह बात और है कि उनके कार्यकाल को मुख्य रूप से तीन ही कारणों से याद किया जाता है. पहला न्यायिक प्रक्रिया को कमज़ोर करना, दूसरा शरीयत विधेयक को पास कराने की कोशिश, जिससे उनके हाथों में असीमित अधिकार आ जाते एवं तीसरा मीडिया पर लगाम कसने की नापाक कोशिश. आज हालत यह है कि उनकी पार्टी के लोग भी रक्षात्मक होने को मजबूर हैं. उन्हें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है और मौजूदा माहौल में उन्हें क्या बोलना चाहिए. पिछले कुछ महीनों में शरीफ की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही थी तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) अलोकप्रिय होती जा रही थी, लेकिन केवल एक घंटे में हवा का रुख़ पूरी तरह बदल गया और आज आम लोगों की नज़रों में वह फिर अपनी पुरानी हालत में पहुंच चुके हैं. संविधान में संशोधन की संभावना देख लोगों की उम्मीदों को पर लग गए थे. उन्हें लगने लगा था कि विभिन्न कारणों से बार-बार विधेयक के मसौदे में आए बदलाव के बाद अब स्थिति में सुधार होगा, लेकिन शरीफ और पीएमएल (एन) ने लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया. आज आम जनता उनसे नाराज़ है तो राष्ट्रपति जरदारी अपनी सत्ता बचाने में कामयाब होने के बाद स्वाभाविक रूप से फूले नहीं समा रहे हैं.

इस सारे वाकये का आख़िरी परिणाम यह है कि पीपीपी की छवि में और निखार आ गया है. हालांकि प्रधानमंत्री गिलानी कितने भी दावे क्यों न करें, लेकिन यह विश्वास नहीं होता कि इस मुद्दे पर पार्टी में कोई गतिरोध नहीं है. पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत का नाम बदलने के मुद्दे, जिसके चलते पीएमएल (एन) ने संविधान संशोधन विधेयक को समर्थन देने से इंकार कर दिया, ने पार्टी के पंजाब केंद्रित नज़रिए को एक बार फिर सतह पर ला दिया. एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल का यह संकीर्ण रवैया पूरे देश के लिए ख़तरनाक हो सकता है. शहबाज शरीफ ने तालिबान से जिस तरह पंजाब को निशाना न बनाने की अपील की, उससे पार्टी का विरोधाभासी चरित्र ही उजागर होता है. इससे संदेश यही गया कि शहबाज पंजाबियों को तो तालिबान से बचाना चाहते हैं, लेकिन पठानों, बलूचों या सिंधियों पर अत्याचार से उन्हें ख़ास मतलब नहीं है. यदि इस मुद्दे पर मतदान कराया जाए तो देखने से यही लगता है कि अधिकांश जनता पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत की जगह एएनपी द्वारा सुझाए गए नए नाम पख्तूनख्वा पर अपनी मुहर लगाने की इच्छुक है. लेकिन पता नहीं क्यों, इस मुद्दे पर इतनी हाय-तौबा क्यों मची है. आख़िर देश के हर प्रांत का नाम किसी न किसी समुदाय के नाम के साथ जुड़ा है. चूंकि नवाज साहब पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में रहने वाले अन्य समुदायों को लेकर चिंतित हैं, तो उन्हें पंजाब का नाम बदल कर पंजाब-सरायकिस्तान या फिर पंजाब-गांधार करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए. ऐसा करके वह अन्य लोगों के सामने एक उदाहरण पेश कर सकते हैं.

हालांकि किसी प्रांत का नाम बदलने से भी बड़ी समस्याएं समाधान की आस लिए हमारे सामने खड़ी हैं. सत्ता संस्थानों के बीच बढ़ता आपसी टकराव लगातार गंभीर रूप लेता जा रहा है. पीएमएल (एन) द्वारा अपने वादे से मुकरने को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है. यदि यह सही है तो हम एक बड़ी आपदा के मुहाने पर खड़े हैं. पहले से ही चारों ओर फैली अराजकता में और वृद्धि हो सकती है. और, यह भी संभव है कि संसद के बाहर की शक्तियां भी खुलकर मैदान में उतर आएं. देश में एक बार फिर लोकतंत्र का गला घोंटने की साजिश की बू आने लगी है. वैसे भी ऐसा हो सकता है, इसकी आशंका तो महीनों से व्यक्त की जा रही है. समस्या यह है कि गुब्बारे के अंदर इतने तरह की हवाएं भरी हैं कि आप चाहकर भी उनसे छुटकारा नहीं पा सकते. उत्तर-पश्चिम में आतंकवादियों का कहर जारी है. उन्होंने कई इलाक़ों पर अपना अधिकार कर लिया है और दूसरे इलाक़ों पर भी उनकी नज़रें गड़ी हुई हैं. जो लोग अपने घरों को लौट रहे हैं, उनके सामने टूटे घरों एवं क्षत-विक्षत खेतों के सिवा और कुछ नहीं है. किसी भी कोने से मदद की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है. देश के दूसरे इलाक़ों में लोग न्याय के लिए भटक रहे हैं. बढ़ते अपराधों के कारण लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और सुरक्षा मुहैया कराने के काम में लगे अधिकारियों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि इन अपराधों को नियंत्रित किया जा सकता है.

निराश जनता मामले को अपने हाथों में लेने के लिए मजबूर है. घरों में बिजली के पंखे चलते रहें, इसके लिए लोग नए उपकरण ख़रीद रहे हैं तो अपने आसपास निगरानी रखने के लिए सिक्युरिटी गाड्र्स की सेवाएं ले रहे हैं. ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है कि किसी कार्यवश घर से बाहर निकले लोग इन गाड्र्स की गोलियों का शिकार बन गए. हम ऐसी हालत में जीने को मजबूर हैं, जहां पता नहीं कि अगली गोली किस कोने से आकर हमारे सीने को छलनी कर दे. इसमें कोई शक़ नहीं कि इतनी सारी गंभीर समस्याओं का हल निकालना किसी एक राजनीतिक दल के बूते की बात नहीं है. स्थिति में सुधार के लिए जो पहल अभी तक हुई है, वह रेगिस्तान में पानी की एक बूंद से ज़्यादा नहीं है. एक समस्या की ओर ध्यान जाता नहीं कि दूसरी समस्या विकराल रूप धारण कर हमारे सामने आ खड़ी होती है और परिणाम वही ढाक के तीन पात रह जाता है. आज ज़रूरत इस बात की है कि राजनीतिक शक्तियां एक साथ मिलकर इन समस्याओं से मुक़ाबले के लिए आगे आएं. यह भी ज़रूरी है कि संसद के बाहर की शक्तियों का इसमें कोई दख़ल न हो. देश की बड़ी पार्टियां जिस तरह विभाजित हैं, वह हमारे लिए ज़्यादा ख़तरनाक तो है ही, साथ ही यह इस बात का भी सबूत है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा.

पाकिस्तान से ह. कमिला
feedback@chauthiduniya.com

नवाज शरीफ

The Ormita Commerce Network has entered the Indian marketplace

Ormita provides a mechanism for business owners to turn their excess capacity into needed goods and services. It supplements existing cash income and provides a way to offset costs against new sales. If your business is not at 100% capacity all of the time then you have an opportunity to increase your revenue and reduce your current cash costs.

How It Works

Ormita acts as a clearinghouse for the trade of excess capacities, goods and services - much like an alternative commodity exchange.

Participants buy and sell their excess capacity and/or stock in return for already budgeted expenses, new investments, cash-flow enhancing products, professional services and donations.

Rather than promoting direct trade between participants the Company brokers transact through its centralized marketplace.

1. Transactions are detailed in a centralized "ledger" which records the value of the items purchased (debit) and sold (credit) - much like a clearinghouse does for stocks, or a commercial bank does for cheques.
2. This ledger system utilises a "credit" as a method of accounting with 1 Ormita Credit = 1 Cash Rupee.
3. Just like any brokerage firm, Ormita receives a cash commission on each transaction.
4. Buyers pay no transaction fees to Ormita but they may pay a small percentage of the entire purchase price in cash to the seller. This cash covers the sellers' fees, sales tax and their additional costs to create this new sale.

A Unique Offering

- 24 hour, 7 day a week live brokerage services.
- Buy, sell and transfer funds online.
- No monthly fees and no annual fees.
- Lowest overall price in the industry.
- No cash outlay until we have met both your buying and selling needs.

[1] Subject to customer meeting minimum trading volumes per month.

For more information about Ormita and franchises.

Website:
www.ormita.co.in
Offices:
(011) 433 55 555
Email:
info@ormita.co.in
Blog:
blog.ormita.co.in
Facebook:
www.facebook.com/pages/Ormita-India/370208677506
Twitter:
twitter.com/ormitaindia

Ormita®
Commerce Network

महादेवी लक्ष्मी की भक्तिमतिता का प्राकट्य इस प्रकार होता है कि नहीं चाहने पर भी भजने योग्य भगवान ही हैं और सदा सर्वदा भजने वालों को भगवान अपने हृदय में स्थान देते हैं.

साईबाबा मेरी आत्मा में बसे हैं : अमित पचौरी

विकास कपूर

तात्या टोपे की भूमिका के लिए राष्ट्रीय चेतना पुरस्कार पाने और फ़िल्म-टेलीविज़न के साथ-साथ रंगमंच पर भी अपनी उपस्थिति से दर्शकों को प्रभावित करने वाले अमित पचौरी एक बेहतरीन कलाकार हैं, उससे भी बढ़कर एक अच्छे इंसान. दूरदर्शन के सफल धारावाहिक ॐ नमः शिवाय में श्री हरि विष्णु की सशक्त भूमिका से अपना सफर शुरू करने वाले अमित ने अब तक कई सफल धारावाहिकों एवं फ़िल्मों के साथ-साथ नाटकों में भी अभिनय किया है. अमित की सफल फ़िल्मों में *ख़तरों के खिलाड़ी*, *जंग का ऐलान* एवं *भाई ठाकुर* आदि प्रमुख हैं. वहीं सफल धारावाहिकों में *जय हनुमान*, *सात फेरे*, *रामायण*, *जय मां वैष्णो देवी*, *साईभक्तों की सच्ची कहानियां*, *पृथ्वीराज चौहान* एवं *धर्मवीर* आदि प्रमुख हैं. इन दिनों अमित रंगमंच के लिए अपने नए नाटक *बेग़म साहिबा* की तैयारियों में जुटे हैं. अमित अपनी सफलता का श्रेय शिरडी के साई बाबा को देते हैं. पिछले दिनों अमित से एक लंबी बातचीत हुई. पेश हैं मुख्य अंश:

▶ॐ साई राम अमित...

ॐ साई राम...

▶ज़ी टीवी के सफल धारावाहिक झांसी की रानी में आप द्वारा निभाई गई भूमिका तात्या टोपे के लिए आपको राष्ट्रीय चेतना अवार्ड से सम्मानित किया गया. मेरी और चौथी दुनिया की ओर से ढेर सारी बधाई.

धन्यवाद, यह सब आप सबकी शुभकामना और साई बाबा की कृपा है.

▶आप एक सफल कलाकार हैं, फ़िल्मों के साथ-साथ आपने कई सफल धारावाहिकों में भी मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देते हैं?

केवल अपने साई बाबा को. मैं कुछ नहीं था और साई कृपा से बहुत कुछ बन गया. मेरे बाबा हैं ही ऐसे. वह तो पत्थर पर कृपा करके उसे पारस बना देते हैं.

▶बाबा की कृपा की कोई ऐसी घटना, जिसे आप अपनी प्रेरणा मानते हों?

मुंबई आने के बाद मैं कुछ समय के लिए पनवेल में रहा था. उन दिनों हर वृहस्पतिवार की शाम को मैं नियम से पनवेल के साई मंदिर जाता था. एक दिन मैं मंदिर जा रहा था, तभी एक मारुति वैन के दरवाज़े में एक चार साल की बच्ची का हाथ दब गया. उसके हाथ से ख़ून बह रहा था. बच्ची लगातार चीख़ रही थी, तभी मंदिर के पुजारी जी आए और घायल बच्ची को लेकर मंदिर के अंदर चले गए. उन्होंने बाबा की उदी उसकी चोट पर मल दी. केवल 15 मिनट बाद उस बच्ची के हाथ पर घाव और ख़ून का निशान भी नहीं दिख रहा था. इस दुर्घटना को और साई कृपा का चमत्कार मैंने अपनी आंखों से देखा है. आज भी जब मैं उस घटना को याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दयालु साई बाबा के प्रति मेरा मस्तक श्रद्धा से झुक जाता है और यही घटना मेरे जीवन की प्रेरणा बन गई.

▶साई बाबा की शिक्षा और मार्गदर्शन को आप अपने जीवन में किस प्रकार देखते हैं?

हमारी वास्तविक ज़िंदगी तो लोगों को दिखाई नहीं देती. कैमरे के सामने जैसा हम चरित्र निभाते हैं, लोग हमें वैसा ही मानने लगते हैं, लेकिन सच यह है कि साई शिक्षा और ज्ञान को मैंने अपने जीवन में उतारने की भरपूर कोशिश की. मुझे लगता है कि मैं एक बहुत ही कमिटेड कलाकार हूं.

शूटिंग में समय से पांच मिनट पहले पहुंचना मेरा शुरू से नियम है. मैं अपने सभी सहयोगियों के साथ आत्मीय रिश्ता रखता हूं, क्योंकि साई बाबा की भक्ति के बाद ही मुझे अहसास हुआ कि दुनिया में रहने वाले सभी मेरे अपने हैं और हम सबका मालिक एक है.

▶अमित, साई बाबा की कृपा तुम पर इसी प्रकार बनी रहे. तुम अपने अभिनय से और भी पुरस्कार जीतो, इसी शुभकामना के साथ ॐ साई राम.

धन्यवाद, ॐ साई राम.

feedback@chauthiduniya.com

हमारी भक्ति

साई बाबा के जीवन एवं सच्चरित्र और आपकी अपनी भक्ति से संबंधित किसी एक विषय पर यहां परिचर्चा की जाएगी और श्रेष्ठ विचार भेजने वाले साई भक्त के विचार यहां प्रकाशित किए जाएंगे.

आपकी दृष्टि में शिरडी के साई बाबा कौन थे?

आपके जवाब

1. (सर्वश्रेष्ठ विचार)

यह प्रश्न लगभग हर साईभक्त के मन में बार-बार उठता है कि साई बाबा कौन थे और कौन हैं? कोई उन्हें राम कहता है कोई कृष्ण कोई शिव रूप में पा लेता है तो कोई दत्तात्रेय के रूप में किसी को वे गुरू नानक लगते हैं तो कोई उनमें जीजस क्राईस्ट को ढूंढ लेता है. गहरे अध्ययन के बाद मुझे ऐसा आभास होता है कि अनंतकोटि ब्रह्मांड के नायक साईनाथ ही परात्पर परब्रह्म हैं. यही कारण है कि उनके भक्त उन्हें जिस रूप में देखते हैं वे उसे उसी रूप में प्राप्त हो जाते हैं.

सुमन तलवार, नई दिल्ली

2. साई सच्चेगुरु और सच्चे मार्गदर्शक हैं. वे अपने शिष्यों (भक्तों) पर सदा अपनी अमृतकृपा की वर्षा करते रहे हैं. वैसे भी गुरु का स्थान सभी से श्रेष्ठ माना गया है.

आशीष अरोड़ा, सोनीपत-हरियाणा

3. साई बाबा जी कौन हैं इसे बताने में क्या मुश्किल है? बाबा, पिता के समान पालने वाले, मालिक के समान ध्यान रखने वाले, गुरू के समान रास्ता दिखाने वाले और दोस्त के समान साथ निभाने वाले हैं.

सतनाम सिंह, अमृतसर (पंजाब)

आप अपने विचार sai4world@gmail.com पर मेल करें अथवा शिरडी साईबाबा फाउन्डेशन, पोस्ट बॉक्स नम्बर-17517, मोतीलाल नगर नम्बर-1, गोरेगाँव (पश्चिम), मुम्बई-58 पर डाक द्वारा भेजें या 09999989427 पर एसएमएस करें.

साई बाबा ने फ़कीरी का चोला ही क्यों धारण किया?

Giriraj
Sai Hills
Sai Vihar Township
Spiritual home... away from home

- Fully Furnished and Spacious studio Apartments.
- One Bedroom Apartments.
- Two bedroom Apartments.
- Fully Furnished Villas.

STARTING FROM RS. 9.65 LAKHS*

AUM Infrastructure & Developers
Tel: 011-46594226 / 46594227
www.ssbf.in

कृष्ण की नगरी में आपका अपना घर!

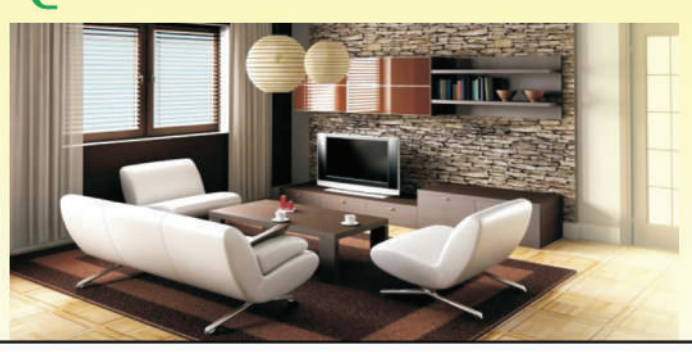

माता महालक्ष्मी की भक्ति

यह शीर्षक देख कर किसी के भी मन में यह संदेह जन्म ले सकता है कि जो नित्य और सनातन हैं, जो सारे संसार को जन्म देने वाली मातृशक्ति हैं, वह क्यों और किसकी भक्ति करने लगीं अथवा उन्हें भक्ति की क्या आवश्यकता? जिस प्रकार देव देवेश्वर भगवान नारायण सर्वव्यापक हैं. उसी प्रकार महादेवी लक्ष्मी भी कण-कण में विराजमान हैं. भगवान विष्णु स्वर हैं तो माता महालक्ष्मी ध्वनि. श्री हरि न्याय हैं तो माता महालक्ष्मी नीति. भगवान विष्णु बोध हैं तो महादेवी बुद्धि. नारायण धर्म हैं तो महालक्ष्मी सत्कर्म. ऐसी महादेवी महालक्ष्मी को भगवद्भक्ति की क्या आवश्यकता? परंतु उनकी भक्ति भी सर्वव्यापक और प्रेरक है. जब समुद्र मंथन द्वारा विविध रत्नों के साथ महादेवी महालक्ष्मी कौस्तुभमणि युक्त माला लेकर स्वयं प्रकट हुईं, तब सभी देवता, दैत्य, मुनि, मानव उनका ऐश्वर्य देखकर उन्हें प्राप्त करने के लिए लालायित हो उठे. परंतु महालक्ष्मी जी तो किसी निर्दोष सर्वगुण संपन्न अविनाशी पुरुष का वरण करना चाहती थीं. समस्त संसार में उन्हें अपनी इच्छा जैसा परमपुरुष प्राप्त नहीं हुआ. रहे एक भगवान नारायण. महादेवी ने देखा कि इनमें तो सभी मंगलमय गुण नित्य निवास करते हैं, परंतु यह तो मुझे देखते ही नहीं. मेरे प्रति अपनी प्रीति को प्रकट भी नहीं करते. मेरी ओर से पीठ किए समुद्र को देखते हुए उसकी लहरें गिन रहे हैं. तो भी महालक्ष्मी जी ने अपने चिर अभीष्ट भगवान नारायण को ही अपने वर के रूप में चुनकर कौस्तुभमणि युक्त माला श्री भगवान के कंठ में डाल दी. अब भगवान भी लक्ष्मी जी की भक्ति-निष्ठा से प्रभावित हो गए और उन्हें अपने वक्षस्थल पर सदा-सदा निवास करने का स्थान दिया. इस प्रसंग से महादेवी लक्ष्मी की भक्तिमतिता का प्राकट्य इस प्रकार होता है कि नहीं चाहने पर भी भजने योग्य भगवान ही हैं और सदा सर्वदा भजने वालों को भगवान अपने हृदय में स्थान देते हैं: *अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसै धन जैसे*. माता लक्ष्मी की भक्ति का उल्लेख करके मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि भले ही आपने जीवन में बड़ी से बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो, ढेर सारा धन और मान-सम्मान प्राप्त कर लिया हो, परंतु एक पल के लिए भी अपने आराध्य को मत भूलिए. उनकी याद और उनका स्मरण आपको सफलता और सच्चाई की ओर अग्रसर रखेगा. शिरडी साई बाबा फाउंडेशन का साई भक्त परिवार पिछले कई वर्षों से समाज के अचेतन में साई की सच्ची भक्ति की चेतना जगाने का पुनीत कार्य कर रहा है. हम इस पावन यज्ञ में आपका भी आह्वान करते हैं. आइए और अपनी भक्ति की समिधा श्री साईचरणों में अर्पित करने के अधिकारी बनिए. साई भक्त परिवार में शामिल होकर अपनी साईभक्ति को और अधिक दृढ़ करने और सदगुरू साई समर्थ की कृपा का अधिकारी बनने के लिए आप अपना नाम साईभक्त.....और फोन नंबर.....कृपया 09999989427 पर एसएमएस करें. ॐ साई राम.

समस्त संसार में उन्हें अपनी इच्छा जैसा परमपुरुष प्राप्त नहीं हुआ. रहे एक भगवान नारायण. महादेवी ने देखा कि इनमें तो सभी मंगलमय गुण नित्य निवास करते हैं, परंतु यह तो मुझे देखते ही नहीं. मेरे प्रति अपनी प्रीति को प्रकट भी नहीं करते.

ऑसिम खेत्रपाल
feedback@chauthiduniya.com

Shirdi Sai Baba Foundation
presents
LIFE IS HOPE Center
Complete
Mind, Body & Soul Rejuvenation

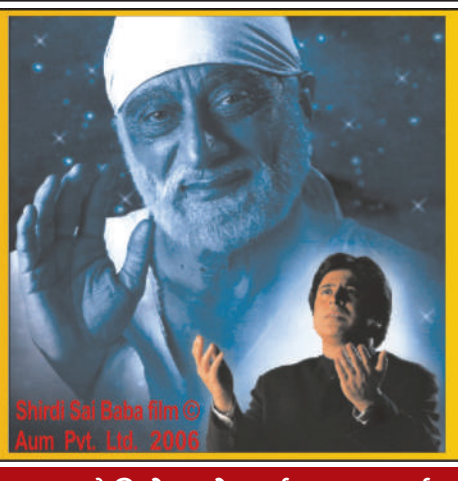

OFFERS CLASSES/SESSIONS FOR:
- Antrang Yoga
- Innovative Meditative Dancing
- Innovative, Healthy, Nutritious Cooking
- Pottery Making
- Stain Glass Painting / Painting (Ladies & Children)
- Theatre - Children
- Spiritual Healing with Aushim Khetarpal
- Discover yourself with Kanu Priya

"Oneness with GOD"
Come and experience the serenity and Connect with the DIVINE

At PACIFIC SPORTS COMPLEX - a World Class Sporting & Swimming facility, opposite Petrol Pump, G.K. - I, Andrews Ganj in South Delhi.

REGISTRATION NOW OPEN
Contact : 01164640005/06 Mobile : 9999041571
E-mail : shirdisaibabafoundation@gmail.com
Register Online at www.ssbf.in

सभी साई भक्तों को विनम्रता से सूचित किया जाता है कि वे अपने साई अनुभव, साई उत्सवों आदि की विस्तृत सूचना (कार्यक्रम, प्रबंधक, तिथि, स्थान और समय सहित) विकास कपूर को sai4world@gmail.com पर मेल कर सकते हैं.

इस बार भी हरिद्वार के कुंभ मेले ने दशाधिक लोगों की बलि ले ली. शासन–प्रशासन की नज़र में फिर भी मेला सकुशल संपन्न हो गया है.

पौराणिक आख्यान, नई व्याख्या

अनंत विजय

प्राचीन भारतीय ग्रंथों में महाभारत और रामायण दो ऐसे ग्रंथ हैं, जिन्हें लेकर विद्वानों के बीच आज भी आकर्षण है. इन ग्रंथों को पिछले सैकड़ों सालों से नए–नए तरीक़े से व्याख्यायित करने और उसके पुनर्पाठ की तमाम कोशिशें जारी हैं. निरंतर अनुसंधान के फलस्वरूप अनेक नए आधार स्रोतों का उद्घाटन भी होता रहा है. हिंदी के अलावा विश्व की अनेक भाषाओं में महाभारत पर अब भी शोध जारी है और देशी–विदेशी अध्येताओं के शोधपरक लेख लगातार प्रकाशित होते रहते हैं. महाभारत में तो इतनी कहानियां और घटनाएं समांतर रूप से घटित होती हैं कि उन्हें एक शोध लेख में समेटना नामुमकिन सा लगता है. देशी–विदेशी शोधार्थियों के बीच इस बात की होड़ सी रहती है कि महाभारत के नवीन शोध–परिणामों के आधार पर विकासशील साहित्य चेतना के आलोक में संपूर्ण परिदृश्य का पुनरावलोकन किया जाए. महाभारत के पात्र कृष्ण में पश्चिम के लेखकों की विशेष रुचि रही है और वे कृष्ण की नीतियों को समग्रता में समझे बग़ैर हल्के तौर पर रेखांकित कर उन्हें धूर्त और पाखंडी तक करार देते रहे हैं. जबकि अगर हम कृष्ण के चरित्र का समग्रता में आकलन करें तो धर्मस्थापन उसका प्रमुख और एकमात्र उद्देश्य है. लेकिन महाभारत को गीता से अलग करके देखने से कृष्ण के चरित्र के बारे में भ्रांतियां पैदा हुई हैं, जबकि उनके चरित्र के आकलन के लिए आलोचकों को महाभारत के साथ–साथ गीता को आधार बनाना चाहिए.

भारत में कम ही लोगों को पता होगा कि महाभारत को कई बार लिखा जा चुका है. इसे विद्वानों ने अपने–अपने तरीक़े से लिखा, लेकिन उसके पात्रों एवं पात्रों के चरित्र के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की. लेकिन जितना बदलाव किया गया, उसे देखकर इसके मूल लेखक वेदव्यास भी आश्चर्यचकित रह जाते. वजह यह है कि अधिसंख्य जनता के दिल में महाभारत को धर्मग्रंथ का दर्ज़ा प्राप्त है, चाहे वह शिक्षित हो या अशिक्षित. हर कोई महाभारत के पात्रों से परिचित है, चाहे वह भीष्म हों, युधिष्ठिर हों, भीम हों, अर्जुन हों या फिर कृष्ण या द्रौपदी. इन पात्रों के नाम से भारत में कई किवदंतियां एवं लोककथाएं भी प्रचलित हैं और जब धर्म एवं सच्चाई की बात होती है तो लोग आज भी युधिष्ठिर को याद करते हैं. देवी–देवताओं के बाद महाभारत के पात्रों को ही भारतीय जनमानस में वृहत्तर स्वीकार्यता है. इसी स्वीकार्यता और पात्रों के चरित्र की विविधताओं से वशीभूत होकर लेखक एवं शोधार्थी इसकी ओर आकर्षित होते हैं. कॉरपोरेट जगत में बेहतरीन करियर छोड़कर गुरुचरण दास पूर्णकालिक लेखक बने और अपनी किताब इंडिया अनबाउंड की सफलता से उत्साहित होकर उन्होंने भारतीय धर्मग्रंथों को नए सिरे से व्याख्यायित करने का फ़ैसला लिया. इस तरह से उनकी नई किताब द डिफिक्लटी ऑफ बीइंग गुड की नींव पड़ी. अपने इस फ़ैसले के बारे में गुरुचरण दास ने बेहद दिलचस्प टिप्पणियां की हैं. जब उन्होंने अपनी मां को इस निर्णय के बारे में बताया तो वह बेहद ख़ुश हुईं और कहा कि जीवन के तीसरे पड़ाव वानप्रस्थ में धर्मग्रंथों की ओर झुकाव स्वाभाविक है. जब उन्होंने एक पूर्व आईएएस अधिकारी, जो इंदिरा गांधी के बेहद क़रीब रहे और खुद को घोर सेक्युलर मानते हैं, को अपने इस निर्णय की जानकारी दी तो उनकी प्रतिक्रिया बेहद दिलचस्प थी, हे भगवान! आप तो भगवा रंग में रंगना चाहते हैं. यह प्रतिक्रिया सुनकर गुरुचरण दास थोड़े विचलित हो गए और उनके मन में सवाल खड़ा हो गया कि यह कैसी धर्मनिरपेक्षता है, जो संस्कृत के ग्रंथों को पढ़ने वालों को राजनैतिक नज़रिए से देखता है. परेशान होना स्वाभाविक है, क्योंकि भारत के छद्म धर्मनिरपेक्षतावादियों ने धर्मग्रंथों और हिंदू जीवन पद्धति को सांप्रदायिकता से जोड़ने का काम किया है. उन्होंने यह पोजिशनिंग कर दी है कि अगर कोई ज्ञान की अपनी समृद्ध विरासत की बात करे, संस्कृत में लिखे ग्रंथों

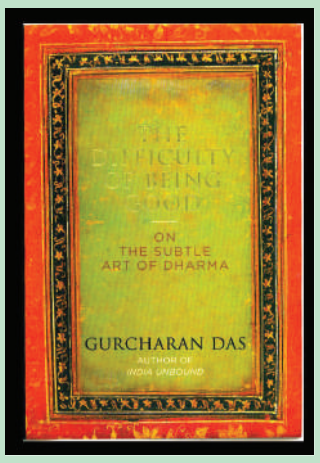

को पढ़ने की ख्वाहिश ज़ाहिर करे, पौराणिक आख्यानों पर शोध या फिर वेद, पुराण एवं उपनिषद पर बहस करे तो वह भगवा ब्रिगेड का सदस्य है. दूसरा जो बड़ा सवाल इस किताब के बहाने से खड़ा होता है, वह यह है कि जब लेखक महाभारत का पुनर्पाठ और उसे नए सिरे से व्याख्यायित करने की योजना बनाता है तो इसके लिए उसने शिकागो विश्वविद्यालय को चुना. इस चुनाव के पीछे लेखक का अपना निर्णय हो सकता है, लेकिन जो संकेत उन्होंने दिए हैं, वे बेहद चिंतित और भारतीय शिक्षा प्रणाली को कठघरे में खड़ा करने वाले हैं. महाभारत को संस्कृत और अंग्रेजी में पढ़ने–समझने के लिए विदेशी विश्वविद्यालय में जाना इस बात की ओर भी संकेत करता है कि हमारे विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा का स्तर कैसा है. हमारी शिक्षा और शोध प्रणाली में विद्वानों का भरोसा क्यों नहीं जम पा रहा है? कोई ऐसी पद्धति क्यों नहीं विकसित हो पा रही है, जहां हम अपने धर्मग्रंथों को नए सिरे से उद्घाटित कर सकें. ये ऐसे सवाल हैं, जो आने वाले दिनों में शिक्षा के कर्ताधर्ताओं के सामने खड़े होकर उनसे जवाब तलब करेंगे.

गुरुचरण दास की किताब समग्रता में महाभारत का न तो पुनर्पाठ है और न ही उसका पुनरावलोकन. डिफिक्लटी ऑफ बीइंग गुड में गुरुचरण दास अपने अप्रोच में बेहद सतर्क और चुनिंदा हैं. इस किताब में उन्होंने महाभारत के पात्रों की चरित्रगत विशेषताओं को शोध का आधार बनाया है और उसे अपने अध्ययन एवं समझ के आधार पर परखने की कोशिश भी की है. इसमें गुरुचरण दास ने दुर्योधन की ईर्ष्या, द्रोपदी के साहस, युधिष्ठिर के धर्मानुसार कर्म, अर्जुन की निराशा, भीष्म पितामह की निस्वार्थता, समाज में अपनी स्थिति को लेकर कर्ण की चिंता, कृष्ण का छल, अश्वत्थामा का बदला, युधिष्ठिर का पश्चाताप और महाभारत का धर्म आदि बिंदुओं पर अलग–अलग अध्याय लिखे हैं. इसके बाद डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड में इस अध्ययन के निचोड़ को अपने निष्कर्ष के रूप में प्रतिपादित किया है. लेकिन एक बात लगातार सालती है कि लेखक ने अनेक जगह देशी–विदेशी लेखकों को उद्धृत किया है. भारतीय लेखकों में आर के नारायण और जी वी नरसिम्हा को तो उन्होंने याद किया है, लेकिन चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को भुला दिया. ऐसा अगर सायास किया गया है तो लेखक को इस बात का संकेत करना चाहिए था, लेकिन अगर असावधानीवश या अज्ञानता में ऐसा हुआ है तो यह एक बड़ी चूक है, क्योंकि महाभारत पर सी राजगोपालाचारी के काम को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है. अपने निष्कर्ष में गुरुचरण दास कहते हैं कि इस ग्रंथ में भगवान के अवतार के रूप में कृष्ण की धूर्तता और छल को जायज़ ठहराना मुश्किल है. हमें कृष्ण को उसी रूप में देखना होगा, जैसा इस ग्रंथ में उनके चरित्र को रचा गया है. उनके व्यक्तित्व के दोनों पहलुओं को सामने रखकर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है. ग्रंथ के मुताबिक़, कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं और इसके अन्य पात्र उन्हें उसी रूप में देखते और इज़्ज़त देते हैं. पिछले लगभग दो हज़ार साल से भारतीय जनमानस कृष्ण के इसी चरित्र को सुनता–पढ़ता रहा है और फिर भी उसकी पूजा करता रहा है. गुरुचरण दास स्वीकार करते हैं कि कृष्ण का चरित्र बेहद दिलचस्प है. यह किताब इस वजह से पठनीय है कि इसमें लेखक की शैली और तर्कक्षमता पाठकों को बांधती है. पर्याप्त शोध और सामग्री के आधार पर लिखी इस किताब में ऐसी कई स्थितियां हैं, जिनका चित्रण और उनके पीछे का तर्क अद्भुत है. जैसे–जब युद्ध के मैदान में विरक्त अर्जुन कृष्ण से पूछता है कि सही क्या है. यहां अर्जुन उनके तर्कों से नहीं, बल्कि उनकी शैली से प्रभावित होता है और उसके मन की सारी शंकाएं दूर हो जाती हैं तथा वह गांडीव उठा लेता है. इस किताब के बारे में सिर्फ़ यही कहा जा सकता है कि इसने महाभारत को एक बार फिर से नए तरीक़े से तर्कपूर्ण ढंग से सामने रखा है और भारतीय जीवन पद्धति के कुछ विचारणीय पक्ष को उसके केंद्र में स्थापित किया है.

(लेखक आईबीएन–7 से जुड़े हैं)

feedback@chauthiduniya.com

पुस्तक अंश मुन्नी मोबाइल

गतांक से आगे

प्रदीप सौरभ

अब यह बात दीगर है कि जमुनापार के दिल्ली में रहने वाले लोग यहां आशियाना बना चुके हैं. फ्लैटों की क़ीमत करोड़ों में है यहां. आज यह सबसे तेज़ी से विकसित होता इलाक़ा है दिल्ली का. दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे जमुनापार के सांसद हैं, इसलिए विकास की रफ़्तार काफी है. आनंद जनता कॉलोनी में ख़ुश थे. मकान मालिकों के गोरखधंधे से आज़ाद. घर की सुखद यादों में आनंद भारती खो गए थे. घर शब्द आनंद भारती के लिए हमेशा बहुत महत्व रखता रहा है. उनके रचनाकर्म में भी और उनके निजी जीवन में भी. पता नहीं, इस शब्द से इतना जुड़ाव और प्रेम रखने के बावजूद आनंद भारती घर की बुनियादी संरचना से कभी जुड़ नहीं पाए. हां, इसकी शुरुआत उन्होंने बहुत यत्न से की थी. उनके सामने शिवानी का मोहक चेहरा तैर गया. बड़ी–बड़ी गहरी आंखें और अल्हड़–चंचल, सांवली–सलोनी शिवानी आनंद भारती को पहली नज़र में ही किसी जादुई एहसास सा मोहाविष्ट कर गई थी. वह विवाह के लिए गहराई से कोई निर्णय ले पाते कि नियति अपना निर्णय ले चुकी थी. इस विषय पर वह ज़्यादा सोच–विचार नहीं कर पाए और विवाह के बंधन में बंध गए. भाग्य का चक्र कई बार मनुष्य को तात्कालिक निर्णय के भंवर में डाल देता है, आज आनंद भारती कुछ ऐसा ही सोचते हैं.

शिवानी के साथ उनका जीवन सामान्य था. शुरू–शुरू में आनंद भारती को कुछ बेचैनी रही, पर बहुत जल्दी वह इस व्यवस्था में सुचारु रूप से बंध गए. दिल्ली में पत्रिका का काम, फिर घर और शिवानी का साथ. उन्हें लगने लगा था कि जीवन में अब स्थायित्व आ गया है. आनंद भारती जनता कॉलोनी में अपनी पत्नी के साथ ख़ुश थे. उस मकान से उनकी सुखद और दु:खद अनेक यादें हैं. इसी मकान में उनकी बेटी का जन्म हुआ था. बड़े प्यार से उसका नाम सूफी रखा था. सूफी के जन्म ने आनंद भारती को सचमुच धारावाहिक बना दिया था. शिवानी का स्नेह, बेटी की मोहक मुस्कान और आनंद भारती की नौकरी सब कुछ एक समीकरण में बंध गए थे. शिवानी भी दिल्ली आकर ख़ुश थी. यहां उसका अपना स्वतंत्र माहौल था. मासूम सी दिखने वाली शिवानी ने गृहस्थी के साथ–साथ बाहर की दुनिया में भी अपना परिचय ख़ूब बना लिया था. सब कुछ ठीकठाक था.

पर बेचैन तबीयत वाले आनंद भारती के लिए रूटीन शब्द बहुत जल्दी आउटडेटेड होने लगता है. यहां भी वही होने लगा था.

दिन भर काम, फिर शाम को मित्रों का जमावड़ा और इधर–उधर की मस्ती. धीरे–धीरे वह पत्रकारों की ट्रेड यूनियन में सक्रिय हो गए थे. अपनी बात कहने और करने का हौसला उनमें भरपूर रहा हमेशा से. संघर्ष से वह कभी घबराते नहीं थे, बल्कि उसमें तपकर वह हमेशा कुछ और निखर उठते थे. इसी ख़ूबी के कारण वह जल्द ही दिल्ली पत्रकार संघ के महामंत्री बन चुके थे. पत्रकारों की ट्रेड यूनियन में उनका विरोधी खेमा उनका दुश्मन बन चुका था. उनके साथ के लोग भी उनकी तरक़्क़ी से जल रहे थे. तमाम व्यस्तताओं के चलते घर पर वह कम समय देने लगे.

आनंद भारती की इस बेचैन तबीयत के साथ शिवानी जुड़ नहीं पा रही थी. उसे आनंद भारती का यह अंदाज़ पसंद नहीं था. सो, घर में खटपट शुरू हो गई थी. छोटी से छोटी चीज़ों में भी व्यवस्था देखने वाले आनंद भारती घर को व्यवस्थित रखने में असमर्थ हो रहे थे. गृहकलह में शिवानी आम पत्नी की तरह तू–तड़ाक करे, ऐसा तो आनंद भारती बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे. अपनी पत्नी को प्यार करने का जज़्बा उनमें भरपूर था, पर इसके लिए वह उनके निजी जीवन में दख़लअंदाज़ी करे, यह बात उन्हें कतई गवारा नहीं थी. इस बीच हिरनी सी आंखों वाली शिवानी का दायरा भी काफी बढ़ चला था. वह भी अपने अधिकारों का बेजा इस्तेमाल करने में कुशल हो गई थी.

अगले अंक में जारी...

चरण वंदना करके निबट गया महाकुंभ

डॉ. कमलकांत बुधकर

जैसे–तैसे आख़िर निबट ही गया उत्तराखंड का पहला महाकुंभ! घोर असुविधाओं और शासन–प्रशासन एवं पुलिस द्वारा बाबा लोगों की चरण वंदनाओं के भरोसे–सहारे ही संपन्न हो गया 2010 का महाकुंभ. सच तो यह है कि आलोक ने आनंदपूर्वक संतों के चरण गहे और निशंक हो गए. यह और बात है कि आख़िर में आकर इन्हीं संतों के कारण लुटिया डूबी और हरिद्वार का कुंभ एक और त्रासदी दे गया. यूं 12 से 15 अप्रैल तक लाखों लोगों ने अपनी आस्था और श्रद्धा के बल पर तमाम परेशानियां झेलकर भी गंगास्नान कर ही लिया. 13 अप्रैल को फ़सल कटने के वार्षिक पर्व बैसाखी, 14 अप्रैल को बारह साला महापर्व महाकुंभ और 15 अप्रैल को अधिक वैशाख पुरुषोत्तम मास के प्रथम दिवस के स्नानपर्व आए और चले भी गए. सरकारी आंकड़ों में इस अवधि में ढाई करोड़ से भी अधिक लोग आकर गंगा नहा गए. अब सरकारी आंकड़ों की पोलपट्टी तो इसी स्तंभ में पहले खोली जा चुकी है. इसलिए मानना चाहिए कि इन त्रिपर्वों पर साठेक लाख लोगों ने हरिद्वार से ऋषिकेश तक आस्था की डुबकी लगाई.

महाकुंभ के शाही स्नान के दौरान क़रीब ग्यारह घंटों तक सामान्य स्नानार्थी के लिए हरकी पौड़ी बंद रही. वहां के सारे मंदिर–देवालय 13–14 अप्रैल की मध्य रात्रि में एक बजे से बंद कर दिए गए, जिन्हें अगले दिन रात को आरती के बाद ही खोलने की अनुमति दी गई. मंदिरों के बाहर पुलिस और अन्य अधिकारियों का पहरा था कि कोई आस्थावान दर्शन करने न घुस जाए. कुंभ के दिन सुबह सात बजे वह अघट घट गया, जिसका डर कुंभ की व्यवस्थित अव्यवस्थाओं को देखकर अधिकांश हरिद्वारवासियों के मन में बैठा हुआ था. एक ओर जहां बैरागियों की दो अणियों दिगंबर और निर्मोही के बीच बैरागी कैंप में जमकर मारपीट और ख़ूनख़राबा हुआ तथा दर्ज़न भर साधुओं को अस्पताल ले जाना पड़ा, वहीं दूसरी ओर जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर पायलट बाबा के कार–कारवां के नीचे कुचल जाने से सात लोग मौत की नींद सो गए. इन सबसे बाखबर प्रदेश के औपचारिक प्रतिनिधि और मुखिया मुख्यमंत्री ने ऐन कुंभ के दिन हरिद्वार आकर सपत्नीक कुंभ स्नान कर लिया तो लगा मानों पूरे उत्तराखंड ने ही गठजोड़े से गंगा में डुबकी लगाकर कुंभ का पुण्य कमा लिया!

यह और बात है कि इस बार भी हरिद्वार के कुंभ मेले ने दशाधिक लोगों की बलि ले ली. शासन–प्रशासन की नज़र में फिर भी मेला सकुशल संपन्न हो गया है. कुंभ वाले दिन घोषित तौर पर सात लोग काल के ग्रास बन गए और सत्रह बुरी तरह घायल हो गए. इसके प्रथम दृष्ट्या दोषी हैं संन्यासियों के प्रमुख पंच दशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर पायलट बाबा. उनकी गाड़ी ने ही इस हादसे को अंजाम दिया. इस दुर्घटना से पहले कुंभ शिविरों में अनेक अग्निकांडों में से एक ही अग्निकांड में तीन महिलाओं की मौत सर्वविदित है. चार महीने के कुंभकाल में कुंभ के लिए ही हरिद्वार आए यात्रियों के साथ हुई अन्य दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या भी शामिल कर ली जाए तो यह आंकड़ा अधिक बड़ा हो जाएगा. 14 अप्रैल का घटनाक्रम सबको विदित है. सब जान गए हैं कि कुंभ स्नान की सुबह किस तरह ललतारौ पुल की तरफ़ से आने वाले निरीह पैदल स्नानार्थियों पर जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर पायलट बाबा के क़ाफिले की गाड़ी चढ़ दौड़ी. हड़बड़ी और भगदड़ में सात लोगों की मौत हो गई और सत्रह बुरी तरह घायल हो गए. कुछ गंगा में गिर गए, जिन्हें बाद में बचा लिया गया. सारी घटना हुई बिरलाघाट के निकट गंगा पुल और पुल के पार चंडी चौक से पहले की सड़क पर.

कुंभ पुलिस के ही एक उच्चाधिकारी ने बताया कि सामने से आती भीड़ पर साधुओं ने लाठियां भांजी और इस अफ़रातफ़री में मची भगदड़ में यात्रियों के दबाव से ही पुल की रेलिंग टूटी. लोग गंगा में गिरे. इस पूरी घटना के बाद पुलिस और प्रशासन ने दबाव बनाया और जूना अखाड़े को शाही स्नान के लिए हरकी पौड़ी जाने से बचने की सलाह दी. वक़्त की नज़ाकत को समझते हुए यह सलाह जूना के सचिव–श्रीमहंत एवं अखाड़ा परिषद

चर्चा कुंभनगर की

के महामंत्री हरिगिरि ने बुद्धिमानीपूर्वक मान भी ली. वे ऐसा न करते तो 1998 के कुंभ की तरह निरंजनी और जूना फिर आमने–सामने होते और तब न जाने क्या–क्या अघटित घट जाता. क्योंकि, निरंजनी अखाड़ा अपने नियत समय से विलंब से पहुंचा और देर तक नहाता रहा. अगर जूना समय से पहुंच जाता तो दोनों अखाड़ों की भिड़ंत को कोई न रोक पाता. बहरहाल अखाड़ों की भिड़ंत तो नहीं हुई, अलबत्ता जनता के साथ महामंडलेश्वर का क़ाफिला भिड़ गया. अब यहां प्रश्न यह पैदा होता है कि अखाड़े के महामंडलेश्वर को गाड़ियां दौड़ाते हुए जनमार्ग पर आने की अनुमति किसने दी? पूरे शहर को जब प्रशासन ने वाहनविहीन कर रखा था तो पायलट बाबा के क़ाफिले की गाड़ियां उस मार्ग पर कैसे आईं? अगर उन्हें आना ही था तो ललतारौ पुल से उस ओर जाने वाले पैदल यात्रियों को क्यों नहीं रोका गया? सामर्थ्यवान कुंभ पुलिस के सामने परस्पर संवाद की ऐसी क्या मजबूरी थी कि क्षेत्र के अधिकारी परस्पर संपर्क भी नहीं कर सके और एक–दूसरे को वास्तविक स्थिति से अवगत भी न करा सके?

चलिए, यह सब तो हो गया. अब जनता पूछ रही है कि बाद की कार्रवाई के नाम पर जूना अखाड़े या उसके महामंडलेश्वर पायलट बाबा के ख़िलाफ़ क्या हो रहा है? सात मौतों की क़ीमत सरकार ने तो पांच लाख रुपये प्रति मृतक के हिसाब से पैंतीस लाख रुपये लगा दी और मजिस्ट्रेटी जांच का लॉलीपॉप थमाकर पल्ला झाड़ लिया, पर करोड़पति अखाड़े और उसके अरबपति मंडलेश्वरों ने मृतकों के परिवारों को दो रुपये की मदद करने का कलेजा भी नहीं दिखाया. यह कैसे संत हैं और उनकी कैसी मानवीय संवेदनाएं हैं? उधर सारा कुंभकाल गवाह रहा है कि वोटों के लोभ–लालच के चलते शासन–प्रशासन संतों के सामने कितना पंगु और निरीह रहा. पर अब तो कुंभ बीत गया. अब तो चमचागीरी छोड़कर सात मौतों के दोषियों पर नकेल कसने की हिम्मत दिखाओ. फिर वे दोषी चाहे पुलिस के लोग हों या संतों की जमात के. निरीहों की मौत से ऊपर कोई नहीं है. पर दुर्भाग्य यह कि धोबी की ग़लती के लिए गधे के कान उमेठे जा रहे हैं. व्यवस्था के दोष के लिए पायलट बाबा के वाहन चालक के ख़िलाफ़ मुक़दमा क़ायम करके कर्तव्य की इतिश्री समझी जा रही है. उधर हरकी पौड़ी पर पहला अखाड़ा निरंजनी आनंद अखाड़े के साथ अपनी समयावधि बीत जाने पर पहुंचा और देर तक रहा. वह तो अच्छा हुआ कि उसके पीछे आने वाला दूसरा अखाड़ा जूना था, जो कुछ शर्म और कुछ प्रशासनिक दबाव के कारण शाही जुलूस लेकर हरकी पौड़ी तक आया ही नहीं. पर विलंबित स्नान के चलते साधुओं के दो अखाड़ों नया उदासीन और निर्मलों ने तो आरती के बाद ही स्नान किया. तभी पूरे 11 घंटों बाद आम स्नानार्थी हरकी पौड़ी पर स्नान कर सके.

सफाई और सुचारु स्वास्थ्य सेवाओं का दंभ भरने वाला प्रशासन हड़बड़ाया रहा और सारा कुंभनगर एक विशाल कूड़ेदान में तब्दील होता चला गया. कोई बिजली या टेलीफोन का खंभा ऐसा नहीं बचा, जिसके नीचे कूड़े के बड़े–बड़े ढेर न लगे हों. स्नान करके अपर रोड से लौटने वाले यात्री सड़कों पर फैले कूड़े के ऊपर ही चलने के लिए विवश थे. पुलिस बल का भारी इंतज़ाम होते हुए भी पुलिस यात्रियों को केवल रोकने का काम कर रही थी, उनके मार्गदर्शन का नहीं! ये पंक्तियां लिखे जाने की तिथि 15 अप्रैल तक हरिद्वार के लोग थक कर चूर हैं, पर पुलिसिया पाबंदियों के चलते हाउस अरेस्ट ही अधिक हैं. वे अख़बार एवं दूध आदि रोज़मर्रा की चीज़ों को तरस गए हैं. उधर अखाड़ों में धर्मध्वजाओं की चारों रस्सियां ढीली कर दी गई हैं, जिसका अर्थ है साधुओं, अब आप कढ़ी पकौड़ा खाओ और हरिद्वार से विदा लो. कुंभ से उकताए हरिद्वारवासी, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मन ही मन कह रहे हैं कि जाओ अतिथियों, अब आप भी पधारो, ताकि कुछ दिन ही सही, हम भी चैन की सांस लें. उसके बाद हरिद्वार का धर्म तो है स्वागत, सो फिर तैयार रहेंगे हम अगवानी के लिए.

kk@budhkar.in

मोबाइल कंपनी फ्लाई ने अपना मोबाइल फोन फ्लाई सर्कल लांच किया है. फ्लाई बी 430 डीएस मॉडल क्वर्टी कीपैड, डुअल सिम कार्ड वाला फोन है.

सजना है मुझे...

जल्द ही शादियों का मौसम शुरू होने वाला है, और सजना के लिए युवतियों के सजने का समय आ रहा है. इसके लिए जो सबसे पहली बात याद आती है, वह है दुल्हन के कपड़े और उसके गहने. मनपसंद ज्वैलरी, मनपसंद कपड़े, मेकअप और उसकी नज़ाकत उठाने के लिए मौजूद सारे घर–परिवार के बीच दुल्हन किसी राजकुमारी से कम नहीं लगती. हमारे देश में अलग–अलग प्रांत की दुल्हनें, अलग–अलग वेशभूषा, अलग प्रकार के जेवर आदि में ख़ास लगती हैं. ज्वैलरी की ब्रांडेड कंपनी तनिष्क ने इस वेडिंग सीजन में अपना लेटेस्ट कलेक्शन लांच किया है. तनिष्क के वेडिंग कलेक्शन में देश के हर प्रांत, हर राज्य की दुल्हनों के लिए लेटेस्ट डिज़ाइन की ज्वैलरी है. नए डिज़ाइनों में पारंपरिक झुमके ख़ास हैं तो राजस्थानी टीका का ट्रेंडी लुक शानदार है, नए बनावट में गढ़े हार बेहद ख़ूबसूरत लगते हैं तो कड़ा और बाजूबंद का नया बदला रूप स्टाइलिश है. ऐसे ही नथ, पेंडेंट, हथफुल, कमरबंद, मंगलसूत्र, कंगन, टॉप्स आदि के नए–नए स्टाइलिश डिज़ायन प्रभावित करते हैं. सोने से बने इन गहनों में पोल्की और कुंदन से लेकर हीरा तक का इस्तेमाल किया गया है. ब्राइडल कलेक्शन के लांच पर तनिष्क के उपाध्यक्ष संदीप कुलहाली ने कहा कि अलग–अलग क्षेत्रों की दुल्हनों की विशिष्ट सजावट का ध्यान रखते हुए कंपनी ने हर तरह की ज्वैलरी को तैयार किया है. ये ज्वैलरी पारंपरिक, पश्चिमी तथाा फ्यूज़न की शैली में हैं. ये ज्वैलरी 22 व 18 कैरेट सोने से बने हैं. इन विशिष्ट आभूषणों को सोने में तैयार कर नगों और क़ीमती पत्थरों से जड़ा गया है.

दोस्तों से जुड़े रहें

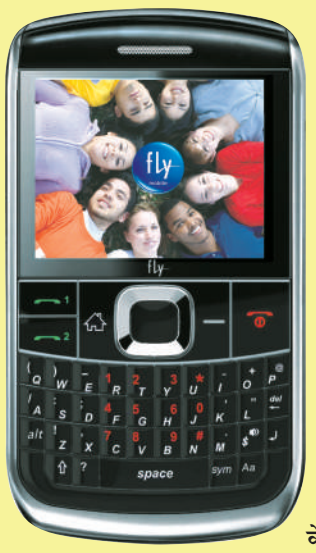

आधुनिक युग में तकनीक ने लोगों को संवाद क़ायम रखने के कई नए रास्ते खोल दिए हैं. आसान और सुलभ रास्ते. इसमें सबसे पहला नाम आता है मोबाइल फोन का. भारत में भी मोबाइल की बढती लोकप्रियता और युवाओं का इसके प्रति क्रेज देखकर कई कंपनियां खुद को भारतीय बाज़ार में स्थापित करने के लिए नए–नए लुभावने ऑफर्स ला रही हैं. इसी क्रम में मोबाइल कंपनी फ्लाई ने अपना हैंडसेट फ्लाई सर्कल लांच किया है. फ्लाई बी 430 डीएस मॉडल क्वर्टी कीपैड, डुअल सिम कार्ड वाला फोन है. इस मॉडल का नाम कंपनी ने फ्लाई सर्कल भी रखा है, क्योंकि इसमें अपने फ्रेंडसर्किल से हमेशा जुड़े रहने का विकल्प उपलब्ध है.

इसमें इंटरनेट सेवाओं के साथ स्काइप, फेसबुक, विंडोज लाइव मैसेंजर, गूगल टॉक, ट्विटर, याहू, एआईएम, माइस्पेस, आईसीक्यू, पिकासा और अन्य इंस्टेंट मैसेजिंग और सोशल नेटवर्क से जुड़ने का मज़ा उठा सकते हैं.

इसके अलावा क्रिकेट व फुटबाल के स्कोर के साथ–साथ पूरी दुनिया के मौसम की जानकारी है. गूगल कैलेंडर पर ख़ुद को व्यवस्थित करने की सुविधा दी गई है. दौड़–भाग भरी आज की ज़िंदगी में रुक कर समाचार सुनना भी मुश्किल होता जा रहा है, इसलिए ख़बरों से रूबरू होने के लिए इस फोन में रॉयटर्स, बीबीसी, न्यूयॉर्क टाइम्स, याहू जैसे सूत्रों से समाचार प्राप्त करने के विकल्प भी मौजूद हैं. किसी भी तरह की यात्रा के दौरान आमतौर पर देखा जाता है कि लोग अपने मोबाइल के साथ व्यस्त रहते हैं, ख़ासकर गेम्स खेलते हुए. इस फोन की विशेष बात यह है कि आप खेलते हुए दिमाग़ को तंदुरुस्त भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें दिमाग़ को तेज़ करने वाले सुडोकू और रैपीड फायर क्विज़ जैसे मज़ेदार पज़ल गेम हैं. कंपनी ने मोबाइल लवर्स के लिए इस फोन की क़ीमत काफी कम यानी 3849 रुपये रखी है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

फन है बाइक राइडिंग

आज जब दोपहिया वाहनों का जीवन चक्र छोटा होता जा रहा है तो आधुनिक तकनीकों से युक्त दोपहिया वाहनों के क्षेत्र में टीवीएस कंपनी लगातार बेहतरीन पेशकश कर रही है. पिछले दशक में टीवीएस ने बिल्कुल नए छह प्लेटफॉर्म पेश किए हैं, जिनमें अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. वैश्विक रुझानों के साथ कामयाब तालमेल बनाए रखने और ऑटोमोबाइल डिज़ाइन और तकनीक के विश्वस्तरीय विकास के लिए कई नए मॉडल्स लांच किए हैं. हाल ही में लांच किए गए टीवीएस जाईव भारत की पहली ऑटो क्लच मोटरसाइकिल है. इस ख़ास मॉडल के लिए कहा जा सकता है कि स्वदेशी रूप से निर्मित देश की पहली फोर स्ट्रोक बाइक है. 110 सीसी की क्षमता वाले इंजन से लैस इसमें अनूठी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. यह रोटरी गियर तकनीक है जिसे ऑटोमेटिक क्लच के साथ जोड़ा गया है. इस बाइक का चार स्तरीय स्पीड वाला इंजन, 8.1 बीएचपी/7500 आरपीएम पर ज़बरदस्त फोर स्ट्रोक परफॉरमेंस और 8.1 एनएम का टॉर्क/5500 आरपीएम पर देता है. मात्र 110 किलोग्राम वजन के टीवीएस जाइव को चलाना बिल्कुल आसान और कंफर्टेबल है. इसके एलॉय व्हील्स, इसे 1260 एमएम का व्हील बेस उपलब्ध कराते हैं, जिससे मोड़ आदि पर इसे निकालना आसान है. इस बाईक के ईंधन टैंक की क्षमता 12 लीटर है, जिसमें दो लीटर ईंधन रिज़र्व रह सकता है. क्लच लीवर का न होना इस मोटरसाइकिल की सबसे ख़ास ख़ूबी है, इससे इस मोटरसाइकिल को चलाना एक हैंड फ्री गियर शिफ्ट का अनुभव देता है. यह बाइक लगभग हर ऐसे शख्स द्वारा चलाई जा सकती है जिसे संतुलन बनाना आता हो, क्योंकि इसमें गीयर बदलने के दौरान क्लच–गीयर का तालमेल ख़ुद बिठाने की ज़रूरत नहीं होती. इसका नीचे झुका हुआ रोटरी गियर सिस्टम, सवार को टॉप गीयर से न्यूट्रल अवस्था में पहुंचने में सक्षम बनाता है. बाइक को स्टार्ट करते समय न्यूट्रल रखना भी ज़रूरी नहीं है. बाइक किसी भी गीयर में स्टार्ट की जा सकती है और सुविधा के लिए इसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट के साथ भी फिट किया गया है. यह देश की पहली ऐसी बाईक है, जिसमें सीट के नीचे स्टोरेज स्पेस दिया गया है, जो वॉटर बॉटल, वाहन के दस्तावेज़ और यहां तक कि एक फोल्डिंग छाता रखने लायक़ जगह है. इसकी एक्स शोरूम क़ीमत 41,500 रुपये है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

गर्मियों में दिखें हॉट और आकर्षक

गर्मियों का स्वागत पूरे उत्साह के साथ करने के लिए महिलाओं के परिधान बनाने वाले निट्स वियर ब्रांड विरसा ने नए कलेक्शन लांच किए हैं.

स्टाइल और पर्सनालिटी को निखारने में कपड़े महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं. मौसम बदलते ही कपड़ों का स्टाइल बदल जाता है. इन गर्मियों का स्वागत पूरे उत्साह से करने के लिए महिलाओं के परिधान बनाने वाले लुधियाना की निट्स ब्रांड विरसा ने नए कलेक्शन लांच किए हैं. यह कलेक्शन बिल्कुल नए, ठंडक देने वाले और ताज़गी भरने वाले फैब्रिक से तैयार किए गए हैं. इनमें गर्मियों के अनुकूल शेड और ट्रेंडी डिज़ाइन का भी पूरा ध्यान रखा गया है. बेहद आरामदायक और आकर्षक डिज़ाइन वाले इस कलेक्शन में रंगों का चुनाव बिल्कुल अलग हटकर किया गया है. इनमें समुद्री नीला, बसंती हरा, गहरा नीला, हल्का गुलाबी, आर्किड और नियॉन लाल के अतिरिक्त तमाम अन्य रंग मौजूद हैं जो आपको गर्मियों में ठंडक का अहसास देंगे. विरसा ने यह संग्रह उन महिलाओं और युवतियों के लिए प्रस्तुत किया है जो अपने व्यवहार के अनुसार अपने व्यक्तित्व में भी बदलाव लाकर चार चांद लगाना चाहती हैं. आधुनिक फैशन और ट्रेंड को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए इस संग्रह में हर तबके के लोगों को प्रभावित करने की क्षमता है. विरसा निट के प्रबंध निदेशक अशोक साहनी कहते हैं कि विरसा के इस समर कलेक्शन के ज़रिए ब्रांड ने महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ परिधानों के तमाम विकल्प प्रस्तुत करने की कोशिश की है, ताकि वे इस उमस भरे मौसम में भी आरामदायक और तरोताज़ा महसूस कर सकें. विरसा मुख्यत: आज की महिलाओं के लिए ख़ास ब्रांड है. कंपनी अपने उत्पादों को लेकर काफी सतर्क रहती है ताकि वह अपने ग्राहकों की गुणवत्ता और फैशन संबंधी मांगों को पूरा कर सके. यह कलेक्शन 600 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक के रेंज में देश के सभी प्रमुख स्टोरों में उपलब्ध है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

ललित मोदी अपने सामने किसी की नहीं सुनते और विवाद तो मानो उनके व्यक्तित्व का एक हिस्सा है.

विवादों का बादशाह ललित मोदी

आदित्य पूजन

इतिहास के पन्ने पलटिए और ललित मोदी के छात्र जीवन पर नज़र डालिए. अमेरिका की ड्यूक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान मोदी पर नशीली दवाओं के इस्तेमाल और अपहरण की कोशिश का आरोप लगा था

हो सकता है कि ललित मोदी को क्रिकेट से बहुत प्यार हो. लेकिन सच यह है कि मोदी को क्रिकेट से कहीं ज़्यादा प्यार विवादों से है. विवादों को जन्म देना और विवादों में बने रहना, मानो उनका बचपन से शौक़ रहा हो. विश्वास नहीं होता तो इतिहास के पन्ने पलटिए और उनके छात्र जीवन पर नज़र डालिए. अमेरिका की ड्यूक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान मोदी पर नशीली दवाओं के इस्तेमाल और अपहरण की कोशिश का आरोप लगा था. उन्हें इसके लिए सजा हुई थी और जुर्माना भी भरना पड़ा था. जवानी के जोश में युवा अक्सर ऐसी ग़लतियां कर बैठते हैं, लेकिन अब आईपीएल कमिश्नर की हैसियत से मोदी जो कुछ कर रहे हैं, वह महज़ जोश में की गई बयानबाज़ी भर नहीं है, बल्कि कुछ और है. इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है कोच्चि टीम को लेकर ललित मोदी और केंद्रीय विदेश राज्यमंत्री शशि थरूर के बीच जारी ताज़ा विवाद, जो अब अदालत तक पहुंच चुका है. कोच्चि टीम की फ्रेंजाइजी को लेकर मोदी द्वारा ट्विटर पर की गई टिप्पणी से शुरू हुआ यह मामला अब इन दोनों हस्तियों के बीच खुली लड़ाई में तब्दील हो चुका है.

दरअसल, विवाद की शुरुआत तब हुई, जब ललित मोदी ने कोच्चि टीम प्रबंधन से फ्रेंजाइज़ियों के नाम सार्वजनिक करने की मांग की. साथ ही उन्होंने यह दावा भी किया कि थरूर उन्हें इससे रोकने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि आईपीएल के नियम-क़ायदों के मुताबिक़ शेयरधारकों का नाम सार्वजनिक करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मोदी आईपीएल के सर्वशक्तिमान अधिकारी हैं और अपनी मर्ज़ी से काम करना उनकी आदतों में शुमार है. जब टीम प्रबंधन ने उनकी बात मानने से इंकार किया तो उन्होंने ख़ुद ही ट्विटर पर इसका खुलासा कर दिया. शेयरधारकों में एक नाम सुनंदा पुष्कर का भी है, जो थरूर की महिला मित्र मानी जा रही हैं और चर्चाओं पर भरोसा करें तो थरूर जल्द ही उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखने वाले हैं. ज़ाहिर है, मोदी की यह टिप्पणी थरूर को नागवार गुजरी और उन्होंने आईपीएल कमिश्नर के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल दिया. विवादों से चोली-दामन का रिश्ता रखने वाले मोदी भी भला कहां चुप बैठने वाले थे. उन्होंने कोच्चि टीम और सुनंदा के साथ थरूर के रिश्तों पर सवाल उठाए.

मोदी के खुलासे से भड़के थरूर और उनके सहयोगियों ने पलट वार करते हुए राजस्थान रॉयल्स टीम के साथ मोदी के संबंधों पर स्पष्टीकरण मांगा. यहां तक कह डाला कि आईपीएल कमिश्नर कोच्चि टीम की बोली रद्द कराना चाहते थे और इसके बदले अहमदाबाद की टीम बनाने के लिए जोर लगा रहे थे. फ्रेंचाइज़ियों के प्रवक्ता ने कहा कि मोदी अभी भी टीम का मालिकाना हक़ बेचने के लिए कंपनी पर दबाव डाल रहे हैं और तरह-तरह की धमकियां दे रहे हैं. सवाल यह है कि मोदी कोच्चि टीम के ख़िलाफ़ क्यों हैं? लेकिन बात इतने पर ही नहीं रुकी. मामला आगे बढ़ा तो एक और महिला का नाम सामने आया. गैब्रिएला दिमित्रिएदेस नामक यह महिला दक्षिण अफ्रीकी मॉडल हैं और आईपीएल के दूसरे सीज़न के दौरान मिस आईपीएल बॉलीवुड की दावेदार रह चुकी हैं. थरूर का आरोप है कि मोदी ने गैब्रिएला का वीजा रोकने के लिए उनसे आग्रह किया था. थरूर ने उनकी बात अनसुनी कर दी तो मोदी ने उनके ख़िलाफ़ मोर्चा खोल दिया.

सच्चाई यह है कि ललित मोदी अपने सामने किसी की नहीं सुनते और विवाद तो मानो उनके व्यक्तित्व का एक हिस्सा है. छात्र जीवन के बाद उन्होंने क्रिकेट प्रशासन के क्षेत्र में क़दम रखे तो इसके लिए अपना नाम तक बदल लिया. राजस्थान क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बनने के लिए उन्होंने राज्य सरकार की मदद से एसोसिएशन के संविधान को ही बदल डाला. उनके तानाशाही रवैये के ख़िलाफ़ असंतोष बढ़ा और अध्यक्ष के अलावा आईपीएल में उनकी हैसियत पर ख़तरा मंडराने लगा तो वह पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के भी उपाध्यक्ष बन गए. आईपीएल की शुरुआत के बाद तो हर रोज़ विवादों के एक नए अध्याय की शुरुआत होने लगी. थरूर के साथ ताज़ा विवाद भी मोदी से जुड़े विवादों के अंतहीन सिलसिले का एक नया हिस्सा है. थरूर ने कोच्चि टीम के फ्रेंचाइज़ियों को एक साथ लाने के लिए परामर्शदाता की भूमिका निभाई तो अहमदाबाद की टीम बनवाने का उनका सपना धराशायी हो गया. वह थरूर के साथ आर-पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हो गए और उनके व्यक्तिगत मामलों को सार्वजनिक करने पर उतारू हो गए.

शशि थरूर और ललित मोदी के बीच का यह विवाद नैतिकता और नियम-कानून की सभी सीमाएं पार कर चुका है. अपने तानाशाही रवैये के चलते बार-बार विवादों में आने वाले ललित मोदी की राजनीतिज्ञों से निकटता जगज़ाहिर है, लेकिन इस बार उनका मुक़ाबला एक ऐसी शख्सियत से है, जो राजनीति के साथ-साथ कूटनीति का भी माहिर खिलाड़ी है. ऐसे में ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका अंदाज़ा लगाना काफी मुश्किल है.

aditya@chauthiduniya.com

आईपीएल टीम मालिकों के नाम सार्वजनिक क्यों नहीं

इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की शुरुआत को क्रिकेट के खेल के लिए एक क्रांतिकारी कदम माना जाता है. बालीवुड की चाशनी में ग्लैमर के तड़के के साथ इसने गेंद और बल्ले के खेल को नया आयाम दिया, लेकिन इसके साथ ही विवादों का एक नया पिटारा भी खोल दिया. आईपीएल में हर साल अरबों रुपये का वारा-न्यारा होता है, लेकिन यह पैसा कहां से आता है और कहां जाता है, इसकी कोई तथ्यपरक जानकारी उपलब्ध नहीं है. सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर टीमों की खरीद-बिक्री में किसके पैसे लगे हैं और किसने कितने पैसे लगाए हैं. थरूर से भड़के मोदी आज भले कोच्चि टीम के शेयरधारकों के नामों को लेकर हल्ला मचा रहे हों, लेकिन उन्होंने यह रवैया दूसरी टीमों के लिए क्यों नहीं अपनाया. सूत्रों पर भरोसा करें तो आईपीएल में कई नामी-गिरामी शख्सियतों की काली कमाई लगी हुई है, जिसमें अंडरवर्ल्ड के कुछ लोग भी शामिल हैं, जो खेल से ज्यादा सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग से करोड़ों की कमाई करते हैं, लेकिन उनके नाम सामने नहीं आते. सामने आते हैं केवल प्रीति जिंटा और शाहरुख खान जैसे नाम, क्योंकि एक तो ये बिकाऊ चेहरे हैं और दूसरा यह कि छुपी बातें सामने आ गईं तो इससे लीग की प्रतिष्ठा और खुद मोदी के व्यक्तित्व पर आंच आने का खतरा पैदा हो सकता है.

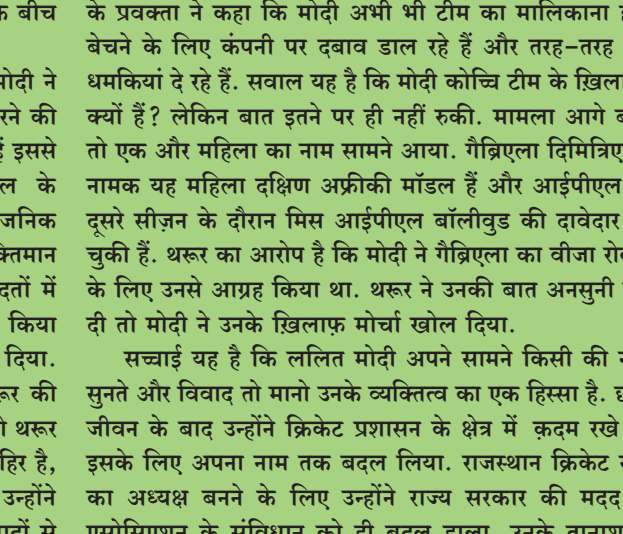

सवाल केवल आईपीएल का ही नहीं है, सवाल देश में क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था बीसीसीआई का भी है. दुनिया की सबसे अमीर खेल संस्थाओं में शामिल बीसीसीआई की कमाई पिछले एक दशक में कई गुना बढ़ चुकी है, लेकिन कमाई के सारे आंकड़े गोपनीयता के तहखाने में छिपे हैं. जानकारी हासिल करने के लिए कई लोगों ने सूचना अधिकार कानून के तहत दर्जनों अर्जियां दीं, लेकिन बोर्ड यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लेता है कि बीसीसीआई की गतिविधियां इस कानून के दायरे में ही नहीं आतीं. लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? बीसीसीआई देश भर में मैचों का आयोजन करती है, जिसके लिए उसे केंद्र और राज्य सरकारों से मदद मिलती है. सुरक्षा व्यवस्था और अन्य आधारभूत सुविधाओं के लिए वह पूरी तरह से सरकार पर निर्भर है तो फिर उसके आर्थिक क्रियाकलापों को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता?

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. 45843/86

चौथी दुनिया

दिल्ली, 26 अप्रैल–02 मई 2010

रंभा इन दिनों अपने पति की कंपनी मैजिक वुड्स को बतौर ब्रांड एंबेसडर प्रोमोट कर रही हैं.

सयानी है सयाली

सयाली भगत क़िस्मत की धनी लगती हैं, इसलिए बिना किसी ख़ास वजह के वह सुर्ख़ियों में आ जाती हैं. इन दिनों वह अपने पुराने प्रेम संबंध की वजह से चर्चा में आई हैं. उनका पुराना प्रेम पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक हुआ करते थे, जिन्होंने भारतीय टेनिस क्वीन सानिया मिर्ज़ा से शादी कर ली हैं. शोएब की इस शादी के सिलसिले में उनकी पहली शादी को लेकर हुए पंगे पर भी सयाली को न्यूज़ चैनलों और अख़बारों में ख़ूब जगह मिली. सयाली ने बड़ी चालाकी से देश की जनता को यह संदेश दिया कि वह इस प्रकरण में कुछ नहीं बोलेंगी, क्योंकि उनके चाहने वालों पर इसका असर पड़ेगा. लेकिन सयाली आख़िर किन फैंस की बात कर रही हैं, यह सोचने वाली बात है. इस देश में ऐसे लोग मुट्ठी भर ही होंगे, जो सयाली को पहचानते भी होंगे. और, अगर उन्हें कुछ बोलना ही नहीं था तो वह मीडिया में आईं ही क्यों? शायद इसे अपनी फेस वैल्यू को बनाए रखने का तरीक़ा समझा है उन्होंने. वैसे सयाली शोएब के प्रेम संबंधों के चर्चे के वक़्त दोनों की एक साथ कास्टिंग वाली फ़िल्म में भी नज़र आने वाली थीं. यह फ़िल्म एक क्रिकेटर आशिक और ख़ूबसूरत लड़की के प्रेम पर बनने वाली थी. लेकिन, दुर्भाग्य यह कि न तो उनका प्रेम संबंध दूर तक चल पाया और न ही उस पर बनने वाली फ़िल्म का कुछ हो सका. हालांकि सयाली ने इस संबंध को फ़िल्म के प्रोमोशन के लिए किया गया एक नाटक बताया, पर बाद में उन्हें शोएब के साथ दिल्ली के एक होटल में देखा गया और उनकी यह दलील झूठी साबित हुई. वह शोएब से दिल्ली में ही किसी स्टोर लांच की पार्टी में मिली थीं. उसके बाद से वह शोएब से ईमेल और फोन कॉल के ज़रिए संपर्क में थीं. शोएब-सानिया प्रकरण में बढ़-चढ़कर बयान देती सयाली शायद अपने अतीत को भूल गई हैं. फेमिना मिस इंडिया बनने के छह साल बाद भी सयाली के पास कोई अच्छी फ़िल्म नहीं है. अफ़वाहों के सहारे चर्चा में आईं सयाली के लिए एक मुफ्त की सलाह है कि जितना बढ़-चढ़कर वह मीडिया में शोएब के लिए बयान दे रही हैं, उतना ही ध्यान अगर अपने करियर पर दें तो आने वाले समय में कुछ अच्छी फ़िल्में उनके हाथ में होंगी.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

शादी के लड्डू

बहुत कम फ़िल्मों में काम करने के बावजूद रंभा को बॉलीवुड में पहचान मिली है. ख़ुशख़बरी यह है कि हाल ही में उनकी शादी हुई है कनाडियन बिजनेसमैन इंद्र कुमार पद्मानाथन से. शादी के बाद अपने चांद के साथ वह हनीमून मनाने न्यूजीलैंड गई हैं. बॉलीवुड में सलमान ख़ान और करिश्मा कपूर के साथ उनकी आख़िरी फ़िल्म जुड़वा थी, जिसमें उनके काम को ख़ूब सराहा गया था. उसके बाद उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बंगाली एवं भोजपुरी फ़िल्मों में काम करना जारी रखा. क्या शादी के बाद फ़िल्मों में काम करेंगी? इस सवाल पर रंभा कहती हैं कि वह काम करना तो नहीं छोड़ेंगी, मगर फ़िल्में करने के मामले में सतर्क ज़रूर हो जाएंगी. क्योंकि शादी के बाद वह अपने परिवार को भी वक़्त देना चाहेंगी और इसलिए अच्छी स्क्रिप्ट वाली फ़िल्में ही करेंगी. अन्यथा अपने पति के बिजनेस में हाथ बटाएंगी. इन दिनों वह अपने पति की कंपनी मैजिक वुड्स को ब्रांड एंबेसडर के तौर पर प्रोमोट कर रही हैं. अच्छा है, उनके पति की कंपनी को मुफ्त में ब्रांड एंबेसडर मिल गया और रंभा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों के सामने आने का प्लेटफॉर्म. बॉलीवुड में एंट्री करने पर उनकी तुलना ख़ूबसूरत अदाकारा दिव्या भारती से की गई, लेकिन उन्हें दिव्या जितनी सफलता नहीं मिल पाई. शायद इसकी वजह उनकी ऐक्टिंग थी. अच्छा होगा, अगर पति के बिजनेस को प्रोमोट करते हुए वह फिर से लोगों के बीच अपनी जगह बना पाएं. फ़िलहाल शादी के लिए ढेर सारी बधाई.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

समाजसेवा में रुचि है : शरमन

शरमन जोशी अधिकतर फ़िल्मों में शर्मीले और कंफ्यूज़्ड किरदार में नज़र आते हैं, पर असल ज़िंदगी में वह काफी कॉन्फिडेंट और स्मार्ट थिंकर हैं. ग्यारह फ़िल्में करने के बाद फ़िल्म थ्री इडियट्स से उन्हें एक अलग पहचान मिली. दिल्ली में *चौथी दुनिया* की संवाददाता रीतिका सोनाली शरमन ने खुलकर बातचीत की. पेश हैं मुख्य अंश :

आप विज्ञापनों में ख़ूब नज़र आ रहे हैं, फ़िल्मों में कम. इसकी वजह?

मैं दर्शकों के बीच अपनी पहचान बनाए रखना चाहता हूं. प्रोडक्ट एंडोर्समेंट इसका अच्छा ज़रिया है. इसके अलावा कोई ख़ास बात नहीं है. मैं फ़िल्में भी कर रहा हूं, पर काफी सोच-समझ कर. इसलिए ज़्यादा फ़िल्में नहीं कर रहा हूं. मेरी आने वाली फ़िल्म है *अल्लाह के बंदे*, जिसमें मेरे साथ नसीरुद्दीन शाह और अनुपम खेर होंगे.

क्या विज्ञापन के मामले में भी चूज़ी हैं?

हां, मैं उसी ब्रांड को प्रोमोट करना चाहता हूं, जो लोगों को पसंद है, जिसकी वैल्यू कस्टमर्स के बीच अच्छी है. मैं नहीं चाहता कि मेरे प्रोडक्ट एंडोर्समेंट से लोगों को ग़लत मैसेज जाए.

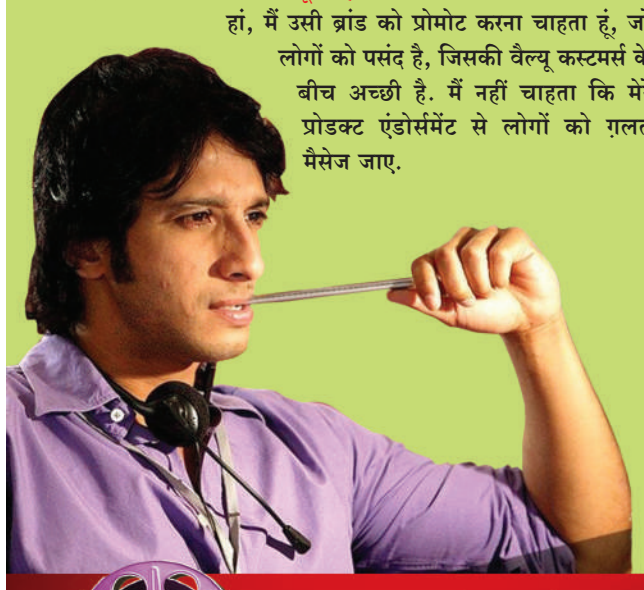

फ़िल्म स्टाइल और एक्सक्यूज़ मी की असफलता के बाद रंग दे बसंती और थ्री इडियट्स ने आपको सफलता के शीर्ष पर पहुंचा दिया. क्या इससे रेपुटेशन पर फ़र्क़ पड़ा?

जी नहीं, मैं ऐक्टिंग इसलिए करता हूं, क्योंकि मुझे इसमें मज़ा आता है. जो भी फ़िल्म मैं चुनता हूं, उसमें अपनी पूरी ताक़त झोंक देता हूं. ऐक्टिंग के मामले में अपने स्तर पर मेरे लिए हर फ़िल्म एक सी होती है. फ़िल्म बनने के बाद ही पता चलता है कि वह हिट या फ्लॉप होती है. इससे पहले किसे पता होता है कि फ़िल्म हिट होगी या फ्लॉप.

ख़ुद को फिट रखने के लिए आप क्या करते हैं?

एक्सरसाइज़ करता हूं, वर्क आउट करता हूं और डाइट का ख़ास ख्याल रखता हूं. सुबह, दोपहर एवं शाम मिलाकर मैं प्रतिदिन 500 ग्राम चिकन खाता हूं. मुझे खाना बहुत पसंद है, पर बॉडी मेंटेन करने के लिए फ़िलहाल ज़ुबान की चाहत को दबा रखा है.

खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है?

मुझे बंगाली खाना बेहद पसंद है. मेरे पिता बहुत अच्छा खाना बनाते हैं. उनके हाथ का बना खाना, ख़ासकर चिकन मुझे बेहद पसंद है.

क्या आप भी खाना पकाना जानते हैं?

जी नहीं, मुझे खाना पकाना बिल्कुल नहीं आता.

आपका पसंदीदा पर्यटन स्थल कौन सा है?

भारत में लद्दाख मुझे बेहद पसंद है.

आपका परिवार थिएटर से संबद्ध रहा. क्या आपकी रुचि नहीं है?

बिल्कुल है, बल्कि मैंने कई गुजराती, अंग्रेजी और हिंदी नाटक किए हैं. फ़िल्मों में आने से पहले मैंने काफी थिएटर परफॉर्मेंस दी हैं. मुझे लगता है कि जो फ़िल्मों में आना चाहता है, उसे थिएटर का अनुभव होना चाहिए.

और किन कामों में रुचि है?

मेरी रुचि समाजसेवा में है. नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर मैं ऐसे कई संगठनों से जुड़ा हूं, जो समाज के उत्थान के लिए काम करते हैं.

ritika@chauthiduniya.com

फिल्म रिव्यू प्रिव्यू

प्रेम का संदेश देती

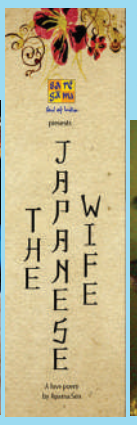

अपनी कलाकारी और काम का दुनिया भर में लोहा मनवा चुकी अपर्णा सेन की नई फ़िल्म द जैपनीज़ वाइफ सुंदरवन जैसे पिछड़े इलाक़े में विकसित होती एक आधुनिक प्रेम कहानी है. आमतौर पर नेटवर्किंग साइट्स, एसएमएस, ई-मेल आदि तकनीक का इस्तेमाल शहरी लोगों को ही करते देखा जाता है, पर ग्रामीण एवं पिछड़े इलाक़े में शिक्षा पाने के बाद भी आधुनिक विचारों वाले स्नेहमॉय मुखर्जी यानी राहुल बोस की प्रेम कहानी चिट्ठियों पर आधारित है. अपर्णा के निर्देशन में राहुल बोस ने कलाकारी का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया है. उनके घर आकर रहने वाली अजनबी विधवा युवती संध्या के किरदार में राइमा सेन ने बढ़िया अदाकारी दिखाई है. सुंदरवन के एक साधारण स्कूल मास्टर स्नेहमॉय से पत्र के ज़रिए शादी करके संबंध बरक़रार रखने वाली जापानी पत्नी के रोल में चिगुसा तकाकू ने भी अच्छा अभिनय किया. कुणाल बासु द्वारा लिखी गई एक अनोखी प्रेम कहानी पर बनी यह फ़िल्म प्रभावित करती है, लेकिन हिंदी के बजाय जापानी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा में रिलीज होने की वजह से फ़िल्म को आम दर्शकों तक पहुंचने में दिक़्क़त हो सकती है. वैसे शुरुआत से अंत तक एक सपाट पटरी पर चलती हुई फ़िल्म दर्शकों को बांधे रखने में सक्षम है. बीच-बीच में दिया गया हास्य का पुट कहानी को दिलचस्प बनाता है. फ़िल्म गंभीर और हृदयस्पर्शी है. प्रेम कहानी के ऐसे प्रारूप, प्रस्तुतिकरण और चित्रण की उम्मीद केवल अपर्णा सेन से की जा सकती है. समाज में देखा जा रहा है कि क़रीब रहते हुए भी प्रेम संबंधों में बिखराव बहुत जल्दी आने लगा है. इसके विपरीत फ़िल्म में सरहद पार का प्रेम केवल चिट्ठियों के माध्यम से जीवित रहता है. जापानी पत्नी और भारतीय बंगाली पति का प्रेम उनकी दैहिक इच्छा, भाषा, संस्कृति- सभ्यता और वातावरण से परे है. यह प्रेम उनके जीवनकाल के अंतिम समय तक जीवित रहता है. चिट्ठियों के माध्यम से जीवित इस प्रेम को यातनाएं, अस्वीकृतियां भी झेलनी पड़ती हैं, पर अपने प्यार पर विश्वास कर वे एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं.

वे अपनी संस्कृतियों से जुड़ी चीज़ों का आदान-प्रदान करते रहते हैं. अपनी मौसी (मौसमी चटर्जी) के साथ रहने वाले स्नेहमॉय मुखर्जी के घर उसकी मौसी की सहेली की विधवा बेटी (संध्या) अपने दस वर्षीय बेटे के साथ रहने आ जाती है. पुराने रीति-रिवाजों को निष्ठापूर्वक मानने वाली संध्या के आने पर स्नेह अपने ही घर में अजनबी सा रहता है. संध्या के प्रति आकर्षित होने के बावजूद वह अपने प्रेम के प्रति ईमानदारी बरतता है. सभी चीजों की बेहतरीन प्रस्तुति के बाद अपर्णा सेन जैसी गंभीर निर्देशक से उम्मीद रहती है कि वह वास्तविकता के धरातल पर भी चीज़ों को प्रदर्शित करें. फ़िल्म की कहानी बंगाल के सुंदरवन नामक स्थान की है, जहां मौसम की हालत बदतर है. इस स्थिति से जोड़ते हुए उन्होंने फ़िल्म के पात्रों के जीवन पर पड़ने वाला असर भी दिखाया है. फ़िल्म का कोई पक्ष कमज़ोर नज़र नहीं आता. लेकिन, दर्शकों और युवाओं को यह फ़िल्म कितनी पसंद आएगी, यह कहना कठिन है.

बदमाश कंपनी

यशराज बैनर्स ने फ़िल्म रब ने बना दी जोड़ी के दौरान अनुष्का को साइन करते वक़्त उसे दो और फ़िल्मों के लिए अनुबंधित किया था. उसी अनुबंध के तहत बनी है बदमाश कंपनी. फ़िल्म में अनुष्का के अलावा शाहिद कपूर, प्रसिद्ध स्टैंडअप कॉमेडियन वीर दास और इंडियन आइडल फेम मियांग चेंग मिलकर बदमाश कंपनी बनाते हैं. कहानी नब्बे के दशक के बांबे (अब मुंबई) की है. उस समय भारत में बाज़ारवाद हावी नहीं था. इंपोर्टेड सामानों की बड़ी अहमियत थी. इसी बिजनेस में मुनाफ़े के चक्कर में चार दोस्त करन, बुलबुल, चंदू एवं जिंग मिलकर एक कंपनी बनाते हैं, जिसका काम विदेशी और इंपोर्टेड सामान को बेचना- ख़रीदना होता है. ज़्यादा मुनाफ़ा होता देख कई लोग उनके इस धंधे में टांग अड़ाते है. वे किस तरह अपनी बदमाशियों से बदमाश कंपनी को बचाते हैं, इसी को थोड़ा सा कॉमिक देते हुए दिखाया गया है. फ़िल्म का निर्देशन परमीत सेठी कर रहे हैं. ग़ौरतलब है कि पहली बार निर्देशन में हाथ आजमा रहे परमीत अर्चना पूरन सिंह के पति हैं. अभिनय के मामले में थोड़ा अनलकी रहे परमीत के लिए यह फ़िल्म किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं है. संगीत प्रीतम चक्रवर्ती का है. गीत लिखे हैं अनविता दत्त गुप्तन ने. स्टोरी और स्क्रिप्ट दोनों परमीत ने ही तैयार की है. सात मई को रिलीज हो रही इस फ़िल्म से अनुष्का एवं परमीत यानी दोनों का ही भविष्य तय हो जाएगा.

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

दिल्ली, 26 अप्रैल-02 मई 2010

www.chauthiduniya.com

नीतीश को पटखनी देंगे शरद

नीतीश कुमार और शरद यादव भले ही एक साथ नज़र आते हों, लेकिन सच्चाई यह है कि इन दोनों कद्दावर नेताओं के रिश्तों में काफ़ी तल्खी आ चुकी है. महिला बिल के अलावा भी कई मसलों पर दोनों की अलग-अलग राय है. अभी तक तो हर मसले पर नीतीश की राय को तवज्जो दी गई, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. अगर राज्यसभा चुनाव में शरद यादव की राय को प्रमुखता नहीं दी गई तो उनके समर्थक विधायक क्रॉस वोटिंग कर नीतीश कुमार की छवि को धक्का पहुंचा सकते हैं.

सरोज सिंह

राज्यसभा में महिला बिल को लेकर हुई फजीहत के बाद आहत शरद यादव ने लोकसभा में आने वाले इस बिल और राज्यसभा चुनाव में नीतीश कुमार को पटखनी देने की तैयारी शुरू कर दी है. सार्वजनिक तौर पर भले ही शरद यादव नीतीश कुमार को दस में से दस अंक दे रहे हों, लेकिन अंदरखाने की सच्चाई यह है कि दोनों नेताओं के रिश्तों में काफ़ी तल्खी आ चुकी है. शरद मौके की तलाश में हैं और महिला बिल एवं राज्यसभा चुनाव में उन्हें मौक़ा दिखाई भी पड़ रहा है. नीतीश की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ लोकसभा में वोटिंग के समय व्हिप जारी करने की तैयारी चल रही है तो राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन में अगर शरद यादव की बात नहीं मानी गई तो पार्टी में उनके समर्थक विधायक क्रॉस वोटिंग भी कर सकते हैं. इस काम में शरद यादव को ललन सिंह का भी पूरा साथ मिलने की उम्मीद है. अगर जदयू का प्रत्याशी चुनाव हार जाता है तो नीतीश कुमार की छवि पर इसका बुरा असर पड़ेगा.

पिछले सप्ताह दिल्ली में नीतीश कुमार के साथ मुलाकात में शरद यादव ने अपने कड़े तेवरों से यह संकेत दे दिया कि जो हुआ सो हुआ, पर आगे अब जदयू में उनकी मर्ज़ी की अनदेखी नहीं की जा सकती है. जदयू के इन दोनों बड़े नेताओं की मुलाकात पर सबकी नज़र थी. नीतीश कुमार ने फोन पर मिलने की इच्छा जताई और कहा कि मेरे साथ दो और नेता आएंगे. इस पर शरद यादव भड़क गए और उन्होंने कहा कि अकेले मिलना हो तो आइए, वरना मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है. नीतीश अपने साथ सांसद रामसुंदर दास और अपने एक खासमखास नेता को ले जाना चाहते थे, लेकिन शरद यादव का मूड भांपकर उन्होंने अकेले जाने का फैसला किया. सूत्रों का कहना है कि लगभग दो घंटे तक चली इस मुलाकात में कई मसलों पर दोनों नेताओं की राय अलग-अलग थी. सबसे अहम मसला महिला बिल का था, जिस पर नीतीश कुमार का कहना था कि लोकसभा में व्हिप जारी न किया जाए, बल्कि सांसदों को अपनी इच्छा से वोट करने दिया जाए. नीतीश कुमार ने शरद यादव से आग्रह किया कि महिला बिल को पहले पास होने दिया जाए, बाद में इसमें संशोधन करा लिया जाएगा. लेकिन शरद यादव ने साफ़ कहा कि बाद में कुछ नहीं होता है. कोटा के भीतर कोटा पार्टी की लाइन है और इसी आधार पर उसे पास होना चाहिए. सूत्रों की मानें तो शरद यादव ने नीतीश कुमार से कहा कि अगर पार्टी लाइन या बिल पास कराने के तरीक़े को लेकर कोई बात थी तो आपको पहले इस बारे में मुझे ज़रूर बताना चाहिए था, लेकिन बात सार्वजनिक होने के बाद आपने नई लाइन ले ली. यह तो लालकिले पर खड़ा करके बेइज्जत करने वाली बात है. नीतीश कुमार बिहार चुनाव को लेकर इस बिल को पास कराने की बात करते रहे और व्हिप जारी न करने का आग्रह भी, मगर शरद यादव ने इस पर कोई आश्वासन नहीं दिया. इसके बाद बात ललन सिंह पर आकर केंद्रित हो गई. नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में पार्टी विरोधी गतिविधियां चला रहे नेताओं का मन बढ़ रहा है. वह ऐसे नेताओं पर कार्रवाई की बात करते रहे, लेकिन शरद यादव ने कहा कि आज जब कुछ लोग लोकसभा में मेरे साथ खड़े हैं तो मैं उन्हें पार्टी से निकाल दूं? उन्होंने कहा कि ललन सिंह ने पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की बात की है तो इसमें गलत क्या है. इसके बाद बात किसान महापंचायत पर आ गई. नीतीश कुमार का कहना था कि यह सब हवा-हवाई है. इस पर शरद यादव ने कहा कि चुनौतियों को पहचानना चाहिए. कुल मिलाकर अर्से बाद दोनों नेताओं के बीच बात तो हुई, पर बात नहीं बनी. अगर शरद यादव महिला बिल पर व्हिप जारी कर देते हैं तो नीतीश कुमार की उलझन बढ़ जाएगी, लेकिन नीतीश के एक करीबी नेता कहते हैं कि इसमें उलझन जैसी तो कोई बात नहीं है. नीतीश जी ने तो महिला बिल पर अपनी व्यक्तिगत राय दी है, न कि पार्टी की. पर राजनीति के जानकार मानते हैं कि अगर लोकसभा में जदयू ने महिला बिल के ख़िलाफ़ वोट दिया तो इससे नीतीश कुमार की छवि को धक्का लगेगा.

जून-जुलाई में होने वाले राज्यसभा और विधान परिषद के चुनावों को लेकर भी शरद खेमा अपनी तैयारी में लगा है. इस बार पांच नेताओं को बिहार से राज्यसभा में जाना है. विधायकों की मौजूदा संख्या के आधार पर यह माना जा रहा है कि इनमें जदयू के कोटे में दो, भाजपा के कोटे में एक और राजद-लोजपा गठबंधन के कोटे में दो सीटों का आना तय है. जदयू से जॉर्ज साहब और एजाज अली का कार्यकाल समाप्त हो रहा है. एजाज अली तो बगावत कर चुके हैं और जॉर्ज साहब बीमार हैं. इसीलिए इन दोनों में से किसी को फिर से प्रत्याशी बनाए जाने की संभावना कम है. हालांकि नीतीश कुमार घोषणा कर चुके हैं कि जॉर्ज साहब को आजीवन राज्यसभा सदस्य बनाए रखा जाएगा. अगर जॉर्ज साहब की सेहत ने साथ दिया तो उन्हें दोबारा प्रत्याशी बनाना नीतीश की मजबूरी हो जाएगी. एजाज अली की जगह पर नीतीश खेमे की ओर से गुलाम रसूल वलियावी का नाम सामने लाया जा रहा है, ताकि मुसलमानों में सही संदेश जा सके. जॉर्ज साहब के प्रत्याशी न बनाए जाने की स्थिति में नीतीश खेमा उपेंद्र कुशवाहा और विजय कुमार चौधरी के नाम पर विचार कर रहा है. शरद एवं ललन खेमा किसी भी कीमत पर इन दोनों नामों पर समझौता करने के मूड में नहीं दिख रहा है. यह खेमा पिछड़ी और भूमिहार जाति से दूसरे प्रत्याशियों के नामों पर विचार कर रहा है. ज़रूरत पड़ी तो यह खेमा प्रभुनाथ सिंह को भी आगे कर सकता है. सूत्रों पर भरोसा करें तो आगे की सोच के तहत यह खेमा रामविलास पासवान के लिए भी वोटों का जुगाड़ कर सकता है. फिलहाल विधानसभा में जदयू के 83, भाजपा के 54, कांग्रेस के 10, राजद के 56, लोजपा के 12, बसपा के पांच, भाकपा के तीन, माकपा, राकांपा एवं अखिल भारतीय जन विकास दल के एक-एक और 11 निर्दलीय सदस्य हैं. राज्यसभा पहुंचने के लिए 41 विधायकों का समर्थन ज़रूरी है. रामविलास पासवान को अतिरिक्त वोटों की ज़रूरत है. ऐसे में चुनावी साल को देखते हुए शरद-ललन खेमा नीतीश कुमार को सबक सिखाने के लिए किसी भी हद तक जाने में नहीं हिचकेगा. उनकी पहली कोशिश होगी कि दोनों प्रत्याशी उनकी पसंद के हों. नीतीश को जानने वाले लोग यह जानते हैं कि ऐसा संभव नहीं है. ऐसे में अपने समर्थक विधायकों से क्रॉस वोटिंग कराना शरद एवं ललन खेमे की मजबूरी हो जाएगी. अपने समर्थक विधायकों एवं कार्यकर्ताओं को बांधे रखने के लिए भी इन दोनों नेताओं को ऐसा करना ज़रूरी है. अलग-अलग कारणों से नीतीश से नाराज़ विधायकों को भी यह खेमा अपने पक्ष में गोलबंद करने में लग गया है. लोकसभा में महिला बिल पर अपनाई जाने वाली रणनीति पर शरद-ललन खेमा पहले ही विचार कर चुका है. मक़सद यह है कि राज्यसभा में जो हुआ सो हुआ, पर अब आगे नीतीश को अपनी राजनीति चमकाने का मौक़ा न दिया जाए. शरद यादव इस बात को भूल नहीं पा रहे हैं कि वह महिला बिल में संशोधन की बात करते रहे, पर नीतीश के इशारे पर जदयू के सांसदों ने राज्यसभा में बिल के समर्थन में वोट दे दिया. बताया जाता है कि दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में इस घटना के बाद शरद यादव का कद काफ़ी घटा है. ललन सिंह भी उन्हें यह समझाने में लगे हैं कि मेरे बाद अब नीतीश के निशाने पर आप ही हैं. बिहार में भी शरद समर्थक विधायकों की राय है कि नीतीश ने शरद यादव को औक़ात बताने का मन बना लिया है, महिला बिल तो एक बानगी भर था. नीतीश आगामी चुनावों में टिकट बंटवारे पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं. ऐसा तभी संभव है, जब शरद यादव कमज़ोर हो जाएं. देर से ही सही, मगर शरद यादव को इसका एहसास हो ज़रूर गया है. शायद इसलिए वह राज्यसभा चुनाव में नीतीश को पटखनी देने की जुगत में लग चुके हैं.

पिछले सप्ताह दिल्ली में नीतीश कुमार के साथ मुलाक़ात में शरद यादव ने अपने कड़े तेवरों से यह संकेत दे दिया कि जो हुआ सो हुआ, पर आगे अब जदयू में उनकी मर्ज़ी की अनदेखी नहीं की जा सकती है. जदयू के इन दोनों बड़े नेताओं की मुलाक़ात पर सबकी नज़रें थीं.

मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है...

पिछले करीब साढ़े चार सालों में यह बात लगभग सभी जान गए हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार में जदयू-भाजपा गठबंधन को अपनी शर्तों पर चलाया. पिछले लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे से लेकर कुछ प्रत्याशियों के चयन तक में भाजपा ने नीतीश कुमार की राय को तवज्जो दी. इसका एक सार्वजनिक प्रमाण उस समय सामने आया, जब नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार न भेजने की सलाह दी और भाजपा ने उसे मान लिया. इस बार भी जब विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई तो नीतीश कुमार ने दिल्ली के कार्यक्रम में कह दिया कि नरेंद्र मोदी और वरुण गांधी को प्रचार के लिए बिहार आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रदेश के भाजपा नेता ही प्रत्याशियों को जिताने का दम रखते हैं, लेकिन इस बार नीतीश कुमार के बयान ने भाजपा को धर्मसंकट में डाल दिया. लोकसभा चुनाव के समय और इस समय की भाजपा में काफ़ी अंतर है. आडवाणी और राजनाथ सिंह की जोड़ी उस समय भाजपा को सत्ता में लाने के लिए नीतीश की बात को ठुकरा नहीं सकी. आडवाणी प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे और बिहार से उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सीटों की ज़रूरत थी, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है. भाजपा की कमान एक ऐसे नेता के हाथ में है, जिसे संघ का आशीर्वाद हासिल है. भाजपा अध्यक्ष नितिन गड़करी तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तक बता चुके हैं. हाल में जब गुजरात दंगे को लेकर मोदी से पूछताछ हुई तो पूरी पार्टी मोदी के साथ खड़ी दिखाई पड़ी. ऐसे में नीतीश के इस ताज़ा बयान से गठबंधन की कुछ परतें हिल गईं. रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कौन प्रचार करेगा और कौन नहीं, इसका फ़ैसला चुनाव अभियान समिति करेगी. विधायक रामेश्वर चौरसिया ने कहा कि गठबंधन धर्म का पालन होना चाहिए. किसी पार्टी के आंतरिक मामले में दखलंदाजी अच्छी बात नहीं है. ज़ाहिर है, भाजपा नेताओं को नीतीश का बयान अच्छा नहीं लगा. पार्टी पर यूं ही जदयू की पिछलग्गू होने का आरोप लगता रहा है. अगर नरेंद्र मोदी मामले में भाजपा ने साफ़ लाइन नहीं ली तो उसकी भद्द पिटनी तय है. कार्यकारिणी की बैठक में नरेंद्र मोदी का पटना आना तय है. उस समय उनकी बातों पर नीतीश के भी कान लगे रहेंगे.

feedback@chauthiduniya.com

बीपीएलधारी रहने के बावजूद इन्हें इंदिरा आवास का लाभ मिलने में भूमिहीन होना बाधक बन रहा है.

अमरेन्द्र सिंह जनता से सेवा का एक मौक़ा देने की बात कर रहे हैं. उनका दावा भी है कि इस बार मोतिहारी में कांग्रेस का पंजा ही रिकार्ड बनाएगा.

दिग्गजों के बीच शह-मात का खेल शुरू

विजेंद्र कुमार

छपरा विधान सभा क्षेत्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनैतिक गतिविधियां तेज़ हो गई हैं. राजनीतिक रूप से यह क्षेत्र अति संवेदनशील माना जाता है. नए परिसीमन के बाद होने वाले इस विस चुनाव में विभिन्न पार्टियों से जुड़े सक्रिय दावेदारों की फेहरिस्त काफी लंबी है. यह यादव बहुल क्षेत्र माना जाता है, जिसकी वजह से दशकों तक इस सीट पर एक ही जाति विशेष का क़ब्ज़ा रहा है. ग़ौरतलब है कि 2005 में हुए विस चुनाव में यहां से जदयू के राम प्रवेश राय विजयी हुए थे. उन्हें पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के हनुमान के तौर पर जाना जाता है. इससे पूर्व इस सीट पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के क़रीबी समझे जाने वाले पूर्व मंत्री उदित राय का क़ब्ज़ा था. वह लगातार तीन बार यहां से विजयी हुए. सारण की राजनीति की दिशा तय करने वाली छपरा विधानसभा सीट पर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की भी पैनी नज़र है. प्रभुनाथ सिंह के लिए भी यह सीट प्रतिष्ठा से जुड़ी है, क्योंकि उन्हें पूरे सारण में नीतीश कुमार को अपनी ताकत का अहसास कराना है. यही वजह है कि अभी से ही दिग्गजों के बीच शह और मात का खेल शुरू हो गया है.

अनिल कुमार सिंह

जनार्दन सिंह सिग्रीवाल

मिथलेश कुमार सिंह

मुरारी सिंह

प्रवीण कुमार यादव

राम बाबू राय

राम प्रवेश राय

सुरेंद्र बागी

उदित राय

नए परिसीमन के बाद विधान सभा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति में हेरफेर हो जाने से जातीय समीकरण में व्यापक बदलाव हो गया है. नए जातीय समीकरण के हिसाब से इस सीट पर राजपूत मतदाताओं की संख्या काफी बढ़ गई है. 2,62,888 मतदाताओं वाले इस क्षेत्र में राजपूत वोटरों की संख्या अब सबसे ज्यादा है. इस विधान सभा क्षेत्र में राजपूत 60 हज़ार, यादव 40 हज़ार, मुस्लिम 28 हज़ार, बनिया 26 हज़ार, भूमिहार 16 हज़ार, ब्राह्मण 12 हज़ार, दलित 10 हज़ार के साथ ही शेष अन्य जाति के मतदाता हैं, जिसके परिणाम स्वरूप राजपूत वर्ग के दावेदारों की संख्या अधिक दिखती है. संख्याबल के लिहाज से दूसरे स्थान पर यादव समुदाय आता है. परिसीमन के बाद पहली बार होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में ज़िले की राजनीति से ताल्लुक रखने वाले दिग्गज राजनेताओं के अलावा सब कुछ नया है, क्योंकि परिसीमन के तहत इस विधान सभा क्षेत्र के यादव बहुल सदर प्रखंड के चौदह पंचायतों के बदले रिवीलगंज प्रखंड को शामिल कर दिया गया है, जो राजपूत बाहुल्य क्षेत्र है. इसी तरह छपरा सदर प्रखंड के सात पंचायत सहित छपरा शहर के 44 वार्ड रिवीलगंज नगर पंचायत एवं प्रखंड को मिलाकर बनाए गए छपरा विस क्षेत्र में राजपूत वोटर निर्णायक स्थिति में हैं. वैसे यादव और मुसलमान का वोट संतुलन बनाने में कारगर सिद्ध हो सकता है.

विधानसभा क्षेत्र छपरा

वर्तमान में विभिन्न दलों से टिकट के दावेदारों में कुछ पुराने चेहरे को छोड़कर शेष युवा पीढ़ी के दावेदार नज़र आते हैं. इनमें पूर्व उपमुख्यमंत्री स्व. राम जयपाल सिंह यादव के पौत्र व भ्रष्टाचार निवारण संस्थान के अध्यक्ष प्रवीण कुमार यादव, पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार सिंह, मुरारी सिंह और सुरेंद्र बागी शामिल हैं. इसके अलावा पिछले दस साल से सारण ज़िला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे अनिल कुमार सिंह, राजद के पूर्व मंत्री उदित राय के साथ ही लोजपा के ज़िला अध्यक्ष रामबाबू राय और सामाजिक कार्यकर्ता ज़रीमन राय का नाम सुर्ख़ियों में है. वहीं दूसरी ओर परिसीमन के तहत जलालपुर विस क्षेत्र का अस्तित्व समाप्त हो जाने से स्थानीय भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल की निगाहें भी इस सीट पर लगी हुई हैं. पिछली बार सूत्रधार की भूमिका निभाकर जदयू से टिकट दिलाने तथा छपरा सीट से रामप्रवेश राय को जिताने तक अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले महाराजगंज के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं.

इससे अलग सारण संसदीय क्षेत्र से विगत लोक सभा चुनाव में राजग प्रत्याशी के रूप में लालू प्रसाद के ख़िलाफ़ चुनाव लड़े भाजपा नेता व राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूढ़ी की नज़रें भी इस सीट पर लगी हैं. उनके क़रीबी कार्यकर्ता बलवंत सिंह का कहना है कि विगत लोक सभा चुनाव में राजग के कुछ स्थानीय राजनेताओं का अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने के बावजूद रूढ़ी छपरा विस क्षेत्र में लालू प्रसाद से साढ़े पांच हज़ार वोटों से आगे रहे थे. यह बात दीगर है कि उस चुनाव में रूढ़ी लालू प्रसाद से शिकस्त खा गए. सूत्रों का कहना है कि रूढ़ी अपने किसी खासमख़ास को छपरा के चुनावी अखाड़े में उतार सकते हैं. जानकारों का मानना है कि कुल मिलाकर नए परिसीमन के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में छपरा सीट के लिए राजनीतिक दिग्गजों के बीच शह–मात का खेल होना तय है.

feedback@chauthidunya.com

कील-कांटा दुरुस्त करने में जुटे दिग्गज

मनोज कुमार राव

मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है. गांवों की पगडंडियों पर नेताओं के पैर पड़ने लगे हैं. वैसे नेता जो जमे–जमाए हैं, उनका सारा काम पुराने ढर्रे पर ही तेजी से चल रहा है, लेकिन नए उम्मीदवार विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने के लिए नए–नए तरीके आजमा रहे हैं. यही नहीं, चुनाव से पहले ही उम्मीदवारी की ताल ठोंकने वाले नेता दीवारों पर अपने पोस्टर व बैनर चिपकाने में लग गए हैं. मोतिहारी में कुछ उम्मीदवार दिन में जनता से उनका दुख–दर्द सुनते हैं, तो वहीं रात होते ही पार्टी के प्रदेश आलाकमान से टिकट देने की गुजारिश करने में लग जाते हैं.

नेताओं का कहना है कि अगर जनता ने उन्हें मौका दिया तो वे क्षेत्र का कायाकल्प करने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे. यहां प्रत्याशियों की लंबी फेहरिस्त है. लिहाजा हर कोई जीत के दावे के साथ चुनावी अखाड़े में कूदने के लिए कील–कांटा दुरुस्त करने की तैयारी में जुट गया है.

यहां से पिछली बार भाजपा के टिकट पर प्रमोद कुमार ने जीत हासिल की थी. प्रमोद कुमार के समर्थक इस बार भी अपने नेता की जीत को सुनिश्चित बता रहे हैं. विधायक प्रमोद कुमार का भी दावा है कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने जनता से न्याय मांगा और उन्हें मिल भी गया, बदले में उन्होंने पूरे कार्यकाल के दौरान हेरें विकास कार्य किए. प्रमोद कुमार की मानें तो पहले मोतिहारी से लखौरा तक का सफ़र तीन घंटे में पूरा होता था, लेकिन आज महज 15 से 20 मिनट में यह यात्रा पूरी की जा सकती है. पहले लखौरा से बहुअरी झिटकहिया तक का सफ़र दो घंटे में पूरा किया जाता था, लेकिन आने वाले दो माह के अंदर यह सफ़र महज 15 मिनट में पूरा कर लिया जाएगा. प्रमोद ने यह भी बताया कि मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र में कई स्कूल भवनों का निर्माण कराया गया है. जिस सदर अस्पताल को पहले सिर्फ ज़ख्म प्रतिवेदन प्रमाण पत्र देने वाला अस्पताल कहा जाता था, आज वहां रोगियों की भीड़ लगी रहती है. प्रत्येक पंचायत में 20 से 25 चापाकल लगवाए गए हैं. उनका ये भी कहना है कि चूंकि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान विकास कार्यों की झड़ी लगा दी है, इसलिए इस बार के विधानसभा चुनाव में जनता से दोबारा विश्वास मांगने जाएंगे. इधर भाजपा के ज़िलाध्यक्ष रह चुके राजेंद्र प्रसाद गुप्ता के चुनाव लड़ने की चर्चा भी जोरों पर है, लेकिन यह तभी संभव है जब प्रमोद कुमार का टिकट कट जाए जिसका संभावना कम ही दिखती है. मौजूदा विधायक यह दावा करने से नहीं चूकते कि उनके काम से आलाकमान और यहां के मतदाता बिल्कुल संतुष्ट हैं और इस बार भी उनकी जीत तय है.

प्रत्येक पंचायत में 20 से 25 चापाकल लगवाए गए हैं. उनका यह भी कहना है कि चूंकि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान विकास कार्यों की झड़ी लगा दी है, इसीलिए इस बार के विधानसभा चुनाव में जनता से दोबारा विश्वास मांगने जाएंगे.

पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर रही राजद की प्रत्याशी रमा देवी अब शिवहर संसदीय क्षेत्र से भाजपा के ही टिकट पर लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन चुकी हैं. इस कारण राजद से उम्मीदवारी को लेकर कम–से–कम एक दर्जन नेताओं की टोली मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र में मंडरा रही है. इस सूची में लोजपा से राजद में आए सुरेश सहनी का नाम सबसे अधिक चर्चा में है. सुरेश सहनी पिछले चुनाव में लोजपा के प्रत्याशी थे और तीसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन इस बार उनका राजद में शामिल होना इस बात की ओर इशारा करता है कि उनकी दावेदारी राजद में सबसे अधिक मजबूत है. शहर में जगह–जगह अपने पोस्टर और बैनर लगवाकर मशहूर हो चुके नगर पार्षद मणिभूषण श्रीवास्तव भी राजद से अपनी उम्मीदवारी को लेकर दिनरात मेहनत कर रहे हैं. उनके समर्थकों का भी दावा है कि इस बार मणि भाई को ही राजद से टिकट मिलेगा और उनकी जीत भी हरहाल में तय है. कायस्थ जाति के मतदाताओं में भी मणिभूषण की उम्मीदवारी को लेकर खासा उत्साह है. इधर अभियंता रह चुके मनोज कुमार गुप्ता भी राजद का दामन थाम चुके हैं और उन्होंने भी आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी दा–वेदारी पेश करने के लिए क्षेत्र भ्रमण शुरू कर दिया है. इन सबके बीच गुप्ता गैस के मालिक बबलू गुप्ता ने भी इस बार अपनी कमर कस ली है. इनके बारे में बताया जा रहा है कि गैस आपूर्ति के माध्यम और अपने कुशल व्यवहार की बदौलत मोतिहारी के लोगों के बीच इन्होंने अपनी अच्छी पैठ बना रखी है. बबलू गुप्ता ने अपने यहां हाल ही में एक प्रेस कांफ्रेंस आयोजित की, जिसमें कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे. इधर लोजपा के ज़िलाध्यक्ष सलाउद्दीन खां ने चौथी दुनिया को बताया कि रमा देवी राजद को छोड़ भाजपा से शिवहर की सांसद बन चुकी हैं और उनके कद का दूसरा राजद नेता फिलहाल ज़िले में नहीं है. इसीलिए इस बार मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र से राजद–लोजपा गठबंधन के तहत लोजपा मैदान में अपना उम्मीदवार उतारेगी. उन्होंने बताया कि इस बात का आश्वासन स्वयं रामविलास पासवान और लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने दिया है. इधर पूरे सूबे सहित देशभर में राहुल बाबा के नाम को कैश कर रही कांग्रेस भी पूर्वी चंपारण में अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज कराने में लगी हुई है. शहर का शायद ही ऐसा कोई चौक–चौराहा होगा, जहां कांग्रेस के संभावित प्रत्याशियों के पोस्टर व बैनर नहीं हों. मतदाता भी इस बार कांग्रेस को एक गंभीर पार्टी के रूप में देख रहे हैं. इसीलिए इस पार्टी से टिकट लेने के लिए सबसे अधिक भागदौड़ है. अगर इस पार्टी से टिकटार्थियों के नामों की सूची बनाई जाए तो इसमें ज़िलाध्यक्ष शैलेन्द्र शुक्ल, पूर्व विधायक सुरेश मिश्र, भाजपा से कांग्रेस में आए अमरेन्द्र सिंह, युवा नेता अमित सिंह उर्फ लड्डू, नप(नगर परिषद) के पूर्व सभापति प्रदीप गुप्ता, ई. रमेश वर्मा सहित पार्टी के कई अन्य लोगों के नाम की चर्चा हर दिन परवान चढ़ती नज़र आ रही है. इधर पहले भी चुनावी अखाड़े में उतर चुकी वरिय चिकित्सक व नेत्री चंद्रलता झा ने लोजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है. खैर, कांग्रेस से टिकट मिलने वाले उम्मीदवार को कांग्रेस और राहुल बाबा के क्रेज का कितना फायदा मिल पाता है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा. बहरहाल अमरेन्द्र सिंह अपने व्यवहार से मतदाताओं के बीच तेजी से जगह बनाते नज़र आ रहे हैं, वहीं अमित सिंह उर्फ लड्डू अपने बड़े–बड़े पोस्टर, बैनर व संदेश वाले तोरण द्वारों के कारण खासा चर्चा में हैं. उनके समर्थकों ने बताया कि इस बार अमित सिंह जैसे युवा नेता को ही जनता अपना मत देगी. अमरेन्द्र सिंह जनता से सेवा का एक मौका देने की बात कर रहे हैं. उनका दावा है कि इस बार मोतिहारी में कांग्रेस का पंजा ही रिकार्ड बनाएगा.

विधानसभा क्षेत्र मोतिहारी

अमरेंद्र सिंह

बबलू गुप्ता

डा. सीएल झा

मणि भूषण श्रीवास्तव

प्रमोद कुमार

राजेन्द्र गुप्ता

सलाउद्दीन खां

शैलेंद्र शुक्ला

सुरेश सहनी

मधुबनी में जदयू गुटबाज़ी का शिकार

विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जहां कांग्रेस, भाजपा, लोजपा समेत अन्य राजनैतिक दलों ने मधुबनी ज़िले में संगठन की मजबूती के लिए पूरी ताक़त झोंक दी है, वहीं सतारूढ़ जदयू के कुनबे में आपसी जंग जोरों पर है. ज़िले के 21 प्रखंडों में से अधिकांश प्रखंडों में जदयू ज़िलाध्यक्ष के पद को लेकर घमासान मचा हुआ है. जदयू प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर महंगाई को लेकर बीते दिनों ज़िला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसका नेतृत्व जदयू प्रदेश नेतृत्व के द्वारा मनोनीत अध्यक्ष सत्येंद्र कामत ने किया.

इस धरना कार्यक्रम के दौरान मधुबनी समाहरणालय पर उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जब सत्येंद्र कामत के समर्थकों द्वारा धरना दिया जा रहा था. इसके ठीक बगल में पार्टी के स्थापित नेता एवं अपने को निर्वाचित जदयू जिलाध्यक्ष कहने वाले लाल बहादुर सिंह भी अपने समर्थकों के साथ धरना पर बैठ गए. एक ही मांग और पार्टी के बैनर तले हो रहे एक साथ दोनों पक्षों के अलग धरने के कारण स्थिति हास्यास्पद तो थी ही, कुछ ही देर में दोनों पक्षों के बीच तनाव की स्थिति हो गई. विवाद इतना गहरा गया कि एक पक्ष विशेष के वक्ताओं ने दूसरे पक्ष के समर्थकों पर न सिर्फ़ ज़ोरदार तरीके से शाब्दिक प्रहार किए, बल्कि असंसदीय भाषा का भी जमकर इस्तेमाल किया. इस कार्यक्रम में मधुबनी जिले के पांच विधायकों में से सिर्फ दो विधायक ही आ पाए.

लाल बहादुर सिंह

रामविनोद सिंह

सत्येंद्र कामत

बेनीपट्टी के विधायक शालिग्राम यादव तथा बाबूबरही के दलीय विधायक कपिल देव कामत, मनोनीत ज़िलाध्यक्ष सत्यदेव कामत वाले खेमे में बतौर मुख्य वक्ता शामिल हुए. पार्टी के पुराने तथा ज़मीनी कार्यकर्ता माने जाने वाले लालबहादुर सिंह अध्यक्ष पद के चुनाव में सर्वाधिक मत प्राप्त करने के बावजूद अध्यक्ष घोषित होने में नाकामयाब रहे, जबकी पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने चुनाव में 43 मत प्राप्त कर तीसरे स्थान पर रहे सत्येंद्र कामत को ज़िलाध्यक्ष मनोनीत कर दिया. हालांकि, स्वतंत्र पेक्षक इसे दल में लोकतांत्रिक व्यवस्था का अभाव मानते हैं. अध्यक्ष पद के चुनाव में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले लालबहादुर सिंह इसे सेटिंग–गेटिंग फॉर्मूला का परिणाम बताते हुए कहते हैं कि वे निर्वाचित अध्यक्ष हैं. श्री सिंह ने कहा कि वह जदयू के पुराने एवं समर्पित कार्यकर्ता की हैसियत से दल में अपनी बात रख रहे हैं. लेकिन, मनोनीत अध्यक्ष सत्येन्द्र कामत इस प्रकरण को विरोधियों की साजिश मानते हुए कहते हैं कि यह विक्षुब्धों द्वारा कांग्रेस की डोर थामने की साजिश है. अध्यक्ष पद को लेकर उठ रहे विवाद का असर मधुबनी ज़िले के सभी 11 विधानसभा क्षेत्रों में पड़ता दिख रहा है. दरअसल, दोनों अध्यक्षों ने ज़िले के 21 में से अधिकांश प्रखंडों में अलग–अलग अध्यक्ष मनोनीत कर रखे हैं. मसलन खुटौना में एक गुट के अध्यक्ष देवदत्त साह हैं तो दूसरे गुट के अध्यक्ष महेन्द्र कामत. कलुआही, खजौली, झंझारपुर समेत कई प्रखंडों में दो–दो अध्यक्ष कार्यरत हैं. नतीज़ा, ज़िले के सभी प्रखंडों में पार्टी का गुटबाजी चरम पर है.

दरअसल, राज्य में सत्ता शीर्ष तक पहुंचने से पहले तक मधुबनी ज़िले में जदयू की सांगठनिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी. गिने–चुने समर्पित कार्यकर्ता ही जदयू में बच गए थे. पर, जैसे ही पार्टी राज्य में सत्ता तक पहुंची, दलबदलू नेताओं ने जदयू का दामन थामना शुरू कर दिया. दलबदलुओं की इसी घुसपैठ में पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हाशिए पर चले गए. इसके दो महत्व–पूर्ण कारणों में से एक प्रमुख कारण तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा महादलित एवं अति पिछड़ों को पार्टी में अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित करना माना जा रहा है. दूसरा कारण दलबदलुओं के द्वारा पार्टी में अपने समर्थकों को सुदृढ़ करने की नीति को माना जा रहा है. समर्पित कार्यकर्ताओं को हाशिए पर डालने का कारण जो भी हो, पर इतना तो तय है कि इससे उनके मनोबल पर प्रतिकूल असर ज़रूर पड़ रहा है. जयनगर प्रखंड जदयू के पूर्व अध्यक्ष रामविनोद सिंह कहते हैं कि यदि प्रदेश नेतृत्व का रवैया नहीं बदला तो विधानसभा चुनाव में दलीय प्रत्याशियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.

ऐसे उदाहरणों से पार्टी के प्रति समर्पित समर्थक हताश हैं. इसका असर आगामी चुनाव में पड़ना तय है. देखना है कि पार्टी का प्रदेश नेतृत्व दलबदलू नेताओं के चलते लंबे समय से पार्टी का झंडा थाम रहे अपने कितने समर्पित कार्यकर्ताओं की बलि देता है. जदयू समर्थकों का मानना है कि पार्टी में ज़िला स्तर पर व्याप्त विवाद में ज़िले से ताल्लुकात रखने वाले कतिपय सांसद एवं विधायक तक रूचि ले रहे हैं. इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि अगर यही स्थिति रही तो आने वाले समय में जदयू के लिए यह घातक साबित हो सकता है.

चित्रानंद झा
feedback@chauthidunya.com

पहले बसाओ फिर उजाड़ो

मस्तीपुर ज़िले के शिवाजी नगर प्रखंड में मुसहर समुदाय के लोग बसने को ज़मीन नहीं, रहने को घर नहीं, पर सारा जहां हमारा है, के तर्ज़ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं. वे तीन एकड़ ज़मीन पर किसी तरह झुग्गी–झोंपड़ी में रहकर ज़िंदगी की गाड़ी आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन विडंबना देखिए कि इन मुसहर परिवारों की शासन–प्रशासन ने अब तक कोई ख़बर नहीं ली है.

पिछले 40 वर्षों से करेह नदी के सिरसिया–सिरनिया बांध पर धिबाही गांव के सामने बसे इन मुसहरों पर उस समय शामत आ गई, जब तटबंध चौड़ीकरण की योजना स्वीकृत हुई. उसके बाद योजना के तहत चौड़ीकरण का कार्य शुरू हुआ, लेकिन यहां बसे परिवारों के बारे में किसी ने भी नहीं सोचा. मुसहरों के घरों को उजाड़ दिया गया. अब उनके सामने यह समस्या उत्पन्न हो गई कि आखिर जाएं तो जाएं कहां. काफी लंबे समय तक इधर–उधर भटकने के बाद 140 मुसहर परिवारों ने एक रणनीति के तहत धिबाही मठ की ज़मीन पर अपना डेरा डाल लिया. तब से लेकर आज तक वे लोग उसी ज़मीन पर झुग्गी–झोंपड़ी डालकर खानाबदोश की तरह जीवन यापन कर रहे हैं. अपनी ज़मीन नहीं रहने के कारण उन्हें सरकारी इंदिरा आवास का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है.

फरवरी माह में मठ के महंथ द्वारा अनाधिकृत क़ब्ज़ाधारियों को हटाने और ज़मीन कब्ज़ा करने को लेकर उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई थी, जिसमें न्यायालय द्वारा हथौड़ी थाना को उक्त ज़मीन पर से मुसहरों को हटाने का निर्देश दिया गया था. न्यायालय के निर्देश के आलोक में जब दलबल के साथ पहुंची पुलिस ने मुसहरों का घर उजाड़ना चाहा, तो उनके परिवारों ने सामूहिक रूप से पुलिस को खदेड़ दिया. इस घटनाक्रम के बाद मुसहरों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर सामूहिक आत्महत्या करने की चेतावनी दे डाली. उन्होंने प्रशासन के सामने सामूहिक रूप से नारा बुलंद किया, पहले बसाओ, फिर उजाड़ो. उनके मज़बूत इरादों को भांपकर प्रशासन के तेवर ढीले पड़ गए. फिर शुरू हुई उन्हें बसाने की कवायद, लेकिन विगत एक दो– महीने में ही प्रशासन ने इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया. प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय कुमार लाल से जब इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुसहरों को बसाने के लिए ज़मीन चिन्हित करने का कार्य शुरू हो गया है. यह सब करने में समय तो लगेगा ही. पुलिस द्वारा अवैध क़ब्ज़ाधारी मुसहर परिवारों को उजाड़े जाने के संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी लाल ने कहा कि यह न्यायालय और पुलिस का मामला है. मुसहर समुदाय के रामविलास सदा, परमेश्वर सदा, हरिकिशुन सदा, जयकिशुन सदा, केदार सदा, महेश सदा, मुनेश्वर सदा, महेश सदा, गुलटेन सदा, परमानंद सदा, चंद्रशेखर सदा, बिंदु सदा आदि ने चौथी दुनिया को बताया कि वर्षों से तटबंध ही हमारा घर–आंगन था. जब हमें उजाड़ गया तो सचमुच हमलोगों ने धिबाही मठ की ज़मीन पर कब्जा जमाकर झुग्गी–झोंपड़ी बना ली. वैसे भी यह तो सार्वजनिक संपत्ति है. इसी प्रकार राधे सदा, रंजीत सदा, अशोक सदा, त्रिवेणी सदा, मोनू सदा, मो. गोलकी देवी, रामप्रकाश सदा, श्रवण सदा, पीतांबर सदा, दीपेन सदा, बिंदु सदा, फकीर सदा, योगेन्द्र सदा रोते हुए कहते हैं कि मठ की ज़मीन का उपयोग कर महंथ ऐशो–आराम की ज़िन्दगी बिता रहे हैं. हमलोग तो ज़मीन के अभाव में यहां पर झुग्गी–झोंपड़ी बना कर बाल बच्चों के साथ समय बिता रहे हैं. यह कैसा न्याय है कि हमें फिर से उजाड़ा जा रहा है.

तटबंध चौड़ीकरण के नाम पर मुसहरों के घरों को उजाड़ा जा रहा है. मगर उन्हें बसाने की बात कोई नहीं करता. हालांकि जब वे धरना–प्रदर्शन या दूसरे रास्ते से उग्र रूप अख्तियार करते हैं तो पुन: उन्हें बसाने की कवायद शुरू होती है, लेकिन एक–दो महीने बाद मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है. यह कैसा न्याय है.

सूत्रों की मानें तो सरकार से सहायता नहीं मिलने के कारण मुसहर परिवार के युवा गलत रास्ता अख्तियार करने को मजबूर हैं. ज़िंदगी से नाराज़ ये युवा रोजगार के बदले गुनाह की राह पर चल पड़े हैं. ऐसा नहीं है कि इन सारे तथ्यों से शासन–प्रशासन अनभिज्ञ है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी नियम–कायदे की आड़ में कुछ नहीं कर रहे हैं. अगर समय रहते इन भटके युवाओं को रास्ते पर नहीं लाया गया तो भविष्य में इन्हें संभालना काफी मुश्किल होगा. इस संबंध में धिबाही पंचायत की मुखिया अमीरकला देवी स्वीकारती हैं कि मठ की ज़मीन पर बसे सभी मुसहर परिवार भूमिहीन हैं. बीपीएलधारी रहने के बावजूद इन्हें इंदिरा आवास का लाभ मिलने में भूमिहीन होना बाधक बन रहा है. वैसे 140 मुसहर परिवार प्रखंड में लिखित रूप से सूचना दे चुके हैं कि पहले ज़मीन संबंधी पर्चा मिले तब इंदिरा आवास की राशि. वहीं पूर्व मुखिया अनिल कुमार सिंह दावा करते हैं कि 2001 में बांध पर बसे इन मुसहरों के बारे में प्रशासन को आगाह किया गया था, लेकिन शासन–प्रशासन द्वारा इसे गंभीरतापूर्वक नहीं लिया गया.

एक ओर जहां नीतीश सरकार महादलितों के उत्थान के लिए व्यापक स्तर पर कार्य करने का दावा करती है, वहीं इतनी बड़ी तादाद में मुसहरों का भूमिहीन होना उनके दावे को खोखला साबित करता नज़र आ रहा है. मुसहरों की इन समस्याओं पर नाराज़गी जताते हुए लोजपा के जिलाध्यक्ष सह वारिसनगर के विधायक विश्वनाथ पासवान नीतीश कुमार सरकार पर आरोप लगाते हैं कि वे वोट के लिए घड़ियाली आंसू बहाते हैं, जबकि हकीकत कुछ और ही है. मुख्यमंत्री का महादलित प्रेम छलावा के सिवा और कुछ नहीं है. अगर सरकार वास्तव में महादलितों के जीवनस्तर में सुधार लाना चाहती है तो अविलंब इन 140 महादलित परिवारों को बसाने का उपाय ढूंढे.

संजीव कुमार
feedback@chauthidunya.com

चौहान DJ साउण्ड
गोपालपुर, शेरघाटी (गया) बिहार
नोट हमारे यहाँ DJ के अलावा किसी भी शुभ अवसर पर साउण्ड हेतु सम्पर्क
प्रो० - बासुदेव चौहान
मो०-9931821483

शेरघाटी विधानसभा क्षेत्रवासियों समेत गया जिले के समस्त मतदाताओं को
हार्दिक शुभकामनाएँ
आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहनेवाला आपका
अपना
अताउल्ला खाँ
अध्यक्ष
गया जिला लोकजनशक्ति पार्टी

GYAN BHARTI SENIOR SECONDARY SCHOOL
EXTENSION CENTRE OF GBRC BODH GAYA
VAISHALI COMPLEX, KATARI HILL ROAD, GAYA
AN EXCLUSIVE + 2 EDUCATIONAL INSTITUTION WITH AN INNOVATIVE VISION
UNDER THE NOBLE GUIDANCE OF Er. Vinit Kumar
An Institution that Provides
The Basics of +2 (Science Stream-PCM/BIO) and Guides for IIT, Medical, Eng & Other Entrance Tests
Separate Classroom Facilities for engineering Aspirants within the school frame work
Lab for regular Practical Classes
Practice Classes
AN INSTITUTION WITH A 3 D MOTO
DEDICATION & DETERMINATION leads you to your DESTINATION
COME, JOIN HANDS WITH US
CONTACT 9431246988, 9386790516
motherpride@rediffmail.com

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. 45843/86

चौथी दुनिया

दिल्ली, 26 अप्रैल–02 मई 2010

लीजा कहती हैं कि उन्होंने मुंबई जाकर करियर बनाने का सोचा ज़रूर था, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंज़ूर था. इसीलिए उन्हें स्पेन जाना पड़ा.

विनोद सिन्हा

कोड़ा प्रकरण

विनोद सिन्हा को बचाने की रणनीति तैयार

नवल किशोर सिंह

खानों के आवंटन में दलाली के रूप में अर्जित की गई अकूत संपत्ति के मुख्य आरोपियों को बचाने की रणनीति तैयार की जा रही है. तक़रीबन चार हज़ार करोड़ रुपए की माइंस दलाली के आरोपी मधु कोड़ा एंड कंपनी के मामले की जांच सीबीआई के हवाले करने से राज्य सरकार के इंकार का रहस्य अब परत-दर-परत खुलने लगा है. इस प्रकरण के प्रमुख टीम लीडर विनोद सिन्हा को आरोपमुक्त करने की पूरी तैयारी हो चुकी है. इसमें झारखंड से लेकर दिल्ली तक की राजनैतिक और प्रशासनिक लॉबी सक्रिय है.

सूत्रों का कहना है कि विनोद सिन्हा फ़िलहाल कोलकाता में हैं. वह आयकर तथा प्रवर्तन निदेशालय के शीर्ष अधिकारियों से नियमित तौर पर संपर्क में हैं. रेवेन्यू बोर्ड के सदस्य (अनुसंधान) के परामर्श से बचाव का रास्ता निकाला जा रहा है. उनके क़रीबी लोग भी सशरीर या दूरभाष के ज़रिए उनसे संपर्क बनाए हुए हैं. रेवेन्यू बोर्ड, आईटी और ईडी के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के बाद विनोद सिन्हा 1000 करोड़ के अपने काले धन के बारे में घोषणा करने जा रहे हैं. इसके एवज में उनसे 35 प्रतिशत अर्थात 350 करोड़ रुपये आयकर के रूप में जमा करने को कहा जाएगा. इसके बाद उनके पास 750 करोड़ का शुद्ध सफेद धन हो जाएगा. और इस तरह वह सभी आरोपों से मुक्त हो जाएंगे. आय के स्रोत पर कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा. जानकारी के मुताबिक हाल में दिल्ली की दो कंपनियों को आयकर विभाग द्वारा इसी तर्ज़ पर राहत दी गई. दो हज़ार करोड़ रुपये की टर्नओवर वाली कंपनी के मालिक ने अपने पास आय से 212 करोड़ रुपये अधिक राशि की घोषणा की. उनसे 35 प्रतिशत आयकर जमा करवा कर काले धन को सफेद करने का मौका दिया गया. दिल्ली की ही एक स्टील उत्पादक कंपनी को भी इसी तर्ज़ पर लाभ पहुंचाया गया. यह कोई नई बात नहीं है. आज़ादी के बाद भारत सरकार कम से कम दो बार टैक्स दो, काले धन को सफेद करो, का खुला आमंत्रण दे चुकी है. इसके ज़रिए काफी काला धन खुले बाज़ार में आया था.

यहां यह चर्चा अप्रासंगिक नहीं होगी कि चारा घोटाले में अकेले सबसे ज्यादा 450 करोड़ रुपये के घोटाले के आरोपी दीपेश चांडक को सरकारी गवाह बनाकर आरोपमुक्त कर दिया गया था, जबकि डॉ. जगन्नाथ मिश्र, लालू प्रसाद जैसे कम राशि के घोटाले के आरोपियों को लंबे समय तक क़ानूनी मामलों में उलझा कर रखा गया. सूत्र बताते हैं कि ठीक इसी तर्ज़ पर माइंस आवंटन दलाली मामले में मगरमच्छों को बचाने और छोटी मछलियों को फंसाए रखने का खेल चल रहा है. क़ानून की नज़र में विनोद सिन्हा भले ही फरार हों, लेकिन आज की तारीख में वह झारखंड के सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं. आयकर निदेशक, अनुसंधान उज्जवल चौधरी का तबादला उन्हीं के इशारे पर किया गया था. चौधरी के पास माइंस घोटाले में शामिल 51 लोगों की सूची थी, जिनके विरुद्ध छापेमारी की तैयारी चल रही थी. दिल्ली दरबार से इनमें से 34 लोगों पर हाथ नहीं डालने का निर्देश आया. चौधरी का कहना था कि क्या शेष 17 लोगों पर सिर्फ इसलिए हाथ डाला जाए, क्योंकि उनकी पैरवी नहीं आई? चौधरी सभी आरोपियों के खिलाफ एक समान कार्रवाई पर अड़े रहे. इसी वजह से उनका तबादला करा दिया गया. बाद में भले ही जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मामले के अनुसंधान तक तबादले पर रोक लगा दी. अभी झारखंड में कई प्रोजेक्ट विनोद सिन्हा के पैसे से चल रहे हैं और खबर यह है कि कम से कम दस बड़े प्रोजेक्ट उनके धन से शुरू होने वाले हैं. झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के प्रधान सचिव सुखदेव सिंह मधु कोड़ा के मुख्यमंत्रित्व काल में भी इसी पद पर थे. माइंस आवंटन की तमाम फाइलें उनके टेबल से होकर ही गुजरती थीं. बीच में उन्हें हटाकर बीके त्रिपाठी को प्रधान सचिव बनाने की बात आई, लेकिन टल गई. कहते हैं कि विनोद सिन्हा का उन पर वरदहस्त है. इसलिए उन पर कोई हाथ नहीं डाल रहा है. पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के आप्त सचिव एमएन पाल के घर पर दो बार छापेमारी हुई. इस क्रम में वह एक सौ करोड़ रुपये काले धन की घोषणा कर उसे सफेद बना चुके हैं. उनकी जगह सीएम के आप्त सचिव बने सुनील श्रीवास्तव भी विनोद सिन्हा के क़रीबी बताए जाते हैं.

ग़ौरतलब है कि मधु कोड़ा के मुख्यमंत्रित्व काल में 47 आयरन ओर माइंस के आवंटन की जांच का मामला अभी ठंढे बस्ते में डाल दिया गया है. झारखंड सरकार इन्हीं कारणों से मामले की जांच सीबीआई को दिए जाने से बार-बार इंकार कर रही है, लेकिन न्यायपालिका भी इसमें सीधे हस्तक्षेप कर सीबीआई जांच का आदेश क्यों नहीं दे रही है, यह बात समझ से परे है. यदि काले धन को सफेद बनाने की यह सहूलियत बरकरार रहती है तो कल को कोई बैंक लुटेरा, तस्कर, ब्लैकमेलर, रंगदार या कोई अपहर्ता भी आय से अधिक संपत्ति की घोषणा कर 35 प्रतिशत की कर अदायगी के ज़रिए एक सम्मानित नागरिक बनकर रह सकता है. यह भारतीय अर्थव्यवस्था में एक खतरनाक परंपरा की शुरुआत का संकेत है. यदि ऐसा हुआ तो आय के स्रोतों के वैध या अवैध होने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा. विनोद सिन्हा जैसे लोग आर्थिक जगत के आदर्श पुरुष का दर्ज़ा प्राप्त कर लेंगे. बहरहाल व्यवस्था पर पकड़ रखने वाले लोग कुछ भी कर सकते हैं. इन पर कोई नियम कानून व्यवहारत: लागू नहीं होता. विनोद सिन्हा बच गए तो संजय चौधरी के लिए दुबई से वापसी और विकास सिन्हा का जेल से बाहर निकलना आसान हो जाएगा.

feedback@chauthiduniya.com

लीजा की भोजपुरी लीला

छहरी काया और हुस्न का ऐसा तालमेल कि दर्शक उनके ठुमकों पर मदमस्त हो जाते हैं. वह चार्मिंग हैं, एनर्जेटिक हैं. सीरियल से लेकर म्यूजिक एलबम और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट से लेकर भोजपुरी सिनेमा तक का सफर तय कर चुकी हैं. अब वह भोजपुरी फ़िल्मों में अपने जलवे बिखेरेंगी. हालांकि, इस बला की खूबसूरत बाला को आपने दरोगाजी चोरी हो गइल में मनोज तिवारी के साथ ठुमके लगाते देखा होगा. अब तक तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि हम किस अदाकारा की बात कर रहे हैं. जी हां, यहां हम बात कर रहे हैं लीजा मलिक की. अपने पहले ही आइटम नंबर से दर्शकों और मृदुल को इंप्रेस करने वाली यह तारिका दिल्ली की कुड़ी है. राजधानी में पली बढ़ी लीजा को अगर सबसे ज़्यादा क्रेज किसी चीज का है, तो वह है डांस. डांस के प्रति उनके जुनून को इसी बात से समझा जा सकता है कि वह महज तीन साल की उम्र से ही डांस करने लगी थीं. इस तरह धीरे-धीरे क्रेज बढ़ता गया और वह पहुंच गई छोटे पर्दे पर. उस जमाने में डांस कंपीटिशन का सबसे बड़ा मंच बूगी-बूगी था. इसी मंच पर उन्होंने तय किया कि वह मुंबई जाकर भाग्य आजमाएंगी. लीजा कहती हैं कि उन्होंने मुंबई जाकर करियर बनाने का सोचा ज़रूर था, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंज़ूर था. इसीलिए उन्हें स्पेन जाना पड़ा. स्पेन में कुछ साल बिताने के बाद उन्होंने अपना म्यूजिक एलबम निकाला. उनका यह एलबम चल निकला और फिर वह मीका के एक रीमिक्स एलबम में भी नज़र आई. ठीक उसी वक्त एक कार्यक्रम के दौरान उन्हें भोजपुरी फ़िल्म दरोगा जी चोरी हो गइल में आइटम गीत का ऑफर मिला. अपने डांस के पैशन को देखते हुए उन्होंने इस ऑफर को झट से स्वीकार कर लिया. बस फिर क्या था, इस गाने के बाद तो उनके पास भोजपुरी फ़िल्मों के ऑफर्स की झड़ी लग गई. दरोगा जी चोरी हो गइल के बाद वह किस रूप में लीला रचाएंगी, यह तो समय ही बताएगा. पर दर्शकों को उनकी दीद के लिए हो सकता है, थोड़ा और इंतजार करना पड़ जाए. क्योंकि वह जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहती है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

वार्ड पार्षद मस्त, गयावासी पस्त

कहा जाता है कि रोम जल रहा था और वहां का शासक नीरो अपनी धुन की बंसी बजाने में मस्त था. कुछ ऐसा हो रहा है गया शहर में. एक ओर शहरवासी इस गर्मी में बिजली पानी के संकट से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गया नगर निगम के वार्ड पार्षद और वहां के पदाधिकारी एक दूसरे से अहं की लड़ाई लड़ रहे हैं. नतीजा यह है कि नगर निगम की राजनीति में उबाल आ गया है. नगर आयुक्त हरेन्द्र शर्मा के खिलाफ मेयर और डिप्टी मेयर तक मोर्चा खोल चुके हैं. एकतरफ मेयर, डिप्टी मेयर के साथ अधिकांश वार्ड पार्षद हैं तो दूसरी ओर नगर निगम कर्मियों से भी नगर आयुक्त का पंगा हो गया है. इस लड़ाई में नगर आयुक्त हरेन्द्र शर्मा अकेले पड़ते नज़र आ रहे हैं. निगम में उनकी पदस्थापना के बाद से ही चर्चा थी कि अपने स्वभाव के कारण उनका टकराव निगम कर्मियों और वार्ड पार्षदों से होना तय है, वही हुआ. सशक्त स्थायी समिति और बोर्ड से पारित प्रस्ताव पर भी नगर आयुक्त के रवैए ने वार्ड पार्षदों को उनके ख़िलाफ़ उद्वेलित होने को बाध्य किया. नतीजा यह हुआ कि नगर आयुक्त हरेन्द्र शर्मा के कार्यकलापों से खफ़ा वार्ड पार्षदों ने एक महीने के अंदर ही उनके ख़िलाफ़ मोर्चा खोल दिया. उन्हें वापस भेजने के लिए गया नगर निगम की मेयर शगुफ्ता प्रवीण ने बिहार नगर पालिका 2007 की धारा 41 के तहत वार्ड पार्षदों की बैठक कर 43 पार्षदों के हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन नगर विकास विभाग को भेजा है. सशक्त स्थायी समिति और बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णय को नज़रअंदाज़ कर नगर आयुक्त द्वारा कथित मनमानी किए जाने के ख़िलाफ़ नगर निगम के वार्ड पार्षद एकजुट हो गए हैं. इस मामले में मेयर तथा डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्वत के नेतृत्व में वार्ड पार्षदों ने अभियान छेड़ दिया है. कुल 53 वार्ड वाले गया नगर निगम में एक वार्ड पार्षद स्व. मेयर ललिता देवी के निधन के बाद कुल बचे 52 वार्ड पार्षदों में से 41 ने नगर आयुक्त के ख़िलाफ़ ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. मेयर शगुफ्ता प्रवीण, डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव, वार्ड पार्षद लालजी प्रसाद, चितरंजन प्रसाद वर्मा आदि ने बताया कि नगर आयुक्त हरेन्द्र शर्मा निगम में योगदान देते ही मेयर के आवास में ताला तोड़कर जबरन घुस गए और मेयर को प्रतिदिन वाहन के लिए मिलने वाले 5 लीटर पेट्रोल को भी बंद कर दिया. साथ ही मेयर के पी.ए. को भी हटा दिया. महिला वार्ड पार्षदों के प्रतिनिधिमंडल से बात करने से इंकार किए जाने, कर्मचारियों से बर्ताव अच्छा नहीं करने आदि बातों को लेकर वार्ड पार्षदों का मुखर विरोध शुरू हो गया. नतीजा है कि ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गया में गंदगी के अलावा इस भीषण गर्मी में पानी की समस्या बढ़ती जा रही है. शहर में जलापूर्ति का जिम्मा निगम के जल पर्षद को है. बीस माह से कर्मचारियों का वेतन बकाया है और बावजूद इसके नगर आयुक्त उन कर्मियों से कार्य कराने के लिए दबाव बनाए हुए हैं. अरबों रूपए बजट वाले गया नगर निगम को जो टैक्स आता है, उससे सिर्फ नगर निगम के कर्मियों का वेतन दिया जा सकता है. विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार के नगर विकास विभाग की ओर टकटकी लगाना नगर निगम की लाचारी है. वार्ड पार्षदों का आरोप है कि एक ओर करीब पांच लाख की आबादी वाले गया नगर निगम के निवासी गंदगी और भीषण जल संकट से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नगर आयुक्त चुने गए जन प्रतिनिधियों की उपेक्षा कर अपनी मनमानी करने का प्रयास कर रहे हैं. इसके कारण शहर में विकास और साफ़-सफ़ाई के अलावा सभी तरह के कार्य बाधित हैं. नगर आयुक्त द्वारा मेयर तथा डिप्टी मेयर की अनदेखी कर सभी फाईलों का अपने स्तर से निष्पादन करना चुने गए जनप्रतिनिधियों पर नौकरशाह के हावी होने का प्रमाण दे रहे हैं. इधर

मेयर, डिप्टी मेयर और वार्ड पार्षदों द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में हरेन्द्र शर्मा ने कहा कि उनलोगों को जो करना था, वह उन्होंने किया. अब हमसे सरकार पूछेगी तो सरकार को जबाब देंगे. उन्हीं लोगों से पूछिए उन्होंने ऐसा क्यों किया.

सुनील सौरभ
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

मध्य प्रदेश

छत्तीसगढ़

दिल्ली, 26 अप्रैल-02 मई 2010

www.chauthiduniya.com

बिजली संकट

बीमारी कुछ, इलाज कुछ

मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार न जाने कौन सी राह चल रही है कि समस्याएं हल होने के बजाय लगातार बढ़ती जाती हैं. बिजली संकट इसका ताज़ा उदाहरण है, जिससे उबरने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास सिर्फ़ राजकीय कोष पर भार डालने वाले साबित हो रहे हैं.

संध्या पांडे

प्रदेश में पिछले दस सालों से बिजली संकट गहराया हुआ है, लेकिन भाजपा के लिए यह केवल एक राजनीतिक मुद्दा भर है. 2003 के विधानसभा चुनाव में बिजली संकट पर हंगामा करके ही भाजपा ने जीत हासिल की थी. 2008 के चुनाव में भी बिजली संकट के लिए केंद्र को ज़िम्मेदार बताकर वह अपनी सत्ता बचाने में सफल हो गई. लेकिन, अब बिजली संकट भाजपा के गले की हड्डी बना हुआ है. फिर भी सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं है. वर्ष 2003 में राज्य में 800 मेगावाट बिजली की कमी थी, जो आज बढ़कर 1200 से 1500 मेगावाट तक हो गई है. बिजली संकट का समाधान ज़्यादा बिजली पैदा करके ही किया जा सकता है, लेकिन सरकार को इससे क्या लेना-देना. पार्टी नेता केवल हो-हल्ला मचाते हैं और

> राज्य सरकार बिजली संकट को हल करने में नाकाम रही है. इसका सबूत यही है कि विद्युत उत्पादन संयंत्र जब-तब ख़राब हो जाते हैं और एक माह तक बंद पड़े रहते हैं.
>
> *सुरेश पचौरी, अध्यक्ष, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी*

समाधान के नाम पर सरकार बिजली ख़रीद कर चुपके से बेच देती है. एक बात तो साफ़ है कि बिजली की ख़रीद-बिक्री के इस काम में करोड़ों रुपये की काली कमाई की गुंजाइश ज़रूर हो जाती है. ग़ौरतलब है कि पावर बैंकिंग के नाम पर सरकार द्वारा बिजली की कमी पूरा करने के लिए दूसरे राज्यों और अन्य स्रोतों से बिजली ख़रीदना तो समझ में आता है, लेकिन उसी बिजली को बेच देना समझ में नहीं आता. जानकारों के अनुसार, कुछ निजी कंपनियों के माध्यम से बिजली की ख़रीद-बिक्री नेताओं और आला अफ़सरों के लिए फ़ायदेमंद होती है, इसीलिए यह कारोबार बदनामी के बावजूद भी जारी है.

राज्य सरकार ने अपनी विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किए. वर्तमान में राज्य की कुल उपलब्ध विद्युत क्षमता 9878.25 मेगावाट है. इसमें केंद्रीय कोटे एवं संयुक्त उपक्रम जल विद्युत परियोजनाओं से मिलने वाली बिजली और उद्योगों के निजी केप्टिव उत्पादन की विद्युत क्षमता भी शामिल है. राज्य सरकार ने अपने स्रोतों से केवल 210 मेगावाट की एक ताप बिजली परियोजना पिछले वर्ष पूरी की है, जबकि चालू वित्तीय वर्ष के लिए सरकार ने किसी भी नई परियोजना को शुरू या पूरा करने की कोई योजना नहीं बनाई है. पूरा दारोमदार केंद्र और अन्य क्षेत्रों से प्राप्त होने वाली बिजली पर है, लेकिन इससे बिजली संकट दूर होने वाला नहीं है. बिजली के क्षेत्र में निवेश के लिए सरकार ने कई निवेशकों और निजी विद्युत कंपनियों को आकर्षित करने के उपाय किए, लेकिन शासन-प्रशासन के हठी और भ्रष्ट रवैये से तंग आकर निवेशक जल्दी ही भाग खड़े हुए. इससे राज्य में 26000 मेगावाट बिजली उत्पादन का सपना भी भंग हो गया. भारत सरकार ने कोयला भंडारों की सीमित क्षमता और जल भंडारों पर बढ़ते दबाव को ध्यान में रखते हुए ग़ैर परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने की योजना पर काम शुरू किया है. तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं राजस्थान आदि राज्यों ने अपने यहां ग़ैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से बिजली पैदा करने के लिए पिछले तीन वर्षों में सराहनीय प्रयास किए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश अभी भी फिसड्डी बना हुआ है.

सरकारी सूत्रों के मुताबिक़, राज्य में ग़ैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से 212.800 मेगावाट बिजली पैदा किए जाने की क्षमता है, लेकिन वर्तमान में इसका केवल 18 फीसदी ही उपयोग हो रहा है. ग़ैर परंपरागत ऊर्जा कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाना शिवराज सिंह सरकार की प्राथमिकता में नहीं है, इसलिए राज्य को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है. प्रदेश के चार महानगरों को सोलर सिटी के रूप में स्थापित करने का काम तो आज तक शुरू नहीं हो सका, जबकि यह काम 2009 में पूरा हो जाना चाहिए था. ख़बर है कि भोपाल नगर निगम ने हाल में ही इस आशय का प्रस्ताव मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम को भेजा है, जबकि केंद्र सरकार बहुत पहले इसकी परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए 50 लाख रुपये की राशि स्वीकृत कर चुकी है. इतना ही नहीं, भारत सरकार एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की माइग्रेशन योजना के तहत राज्य में अब तक एक भी सोलर प्रोजेक्ट नहीं लग सका है. मंत्रालय की ओर से इस योजना के लिए राज्य को भारी अनुदान मिलने की संभावना है. केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग ने भी केंद्र की सोलर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए 18.44 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली ख़रीदने का प्रस्ताव पारित कर दिया है. बावजूद इसके ऐसे मामले जब राज्य सरकार के पास आते हैं तो अटक कर रह जाते हैं. सूत्रों का कहना है कि राज्य सरकार इस क्षेत्र में आने वाले निवेशकों को समय पर न तो ज़मीन मुहैया कराती है और न ही परियोजना की स्वीकृति का सरलीकरण ही करती है. इसके अलावा ऐसी कोई प्रोत्साहन योजना भी राज्य सरकार ने नहीं बनाई है, जिससे निवेशकों का रुझान इस ओर बढ़ सके.

सोलर परियोजनाओं के संबंध में राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग के पास महीनों से प्रस्ताव लंबित हैं, लेकिन सही दिशानिर्देश जारी न होने की वज़ह से निवेशकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है. जानकारी के अनुसार, सौर ऊर्जा से प्रदेश को कम से कम 500 मेगावाट बिजली मिल सकती है. यदि इस परियोजना के लिए प्रदेश में व्यापक सर्वेक्षण कराया जाए तो यह आंकड़ा दो हज़ार मेगावाट तक पहुंच सकता है, लेकिन हालात यह है कि प्रदेश में सौर ऊर्जा का कोई भी प्रोजेक्ट आज तक स्थापित नहीं हो सका. दूसरी ओर बायोमास से भी प्रदेश में विद्युत उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं. करीब 470 मेगावाट की परियोजनाओं के प्रस्ताव राज्य सरकार और उसकी नोडल एजेंसी के पास लंबित पड़े हैं, लेकिन इनमें एकाध को छोड़कर शेष को अभी तक स्वीकृति नहीं मिली. बताया जाता है कि बायोमास आधारित बिजली परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार ने ज़मीन देने का प्रावधान तो कर रखा है, लेकिन बेलगाम नौकरशाहों ने प्रक्रिया को इतना जटिल बना दिया है कि निवेशकों ने सरकारी ज़मीन पर परियोजना लगाने से तौबा कर ली है. राज्य सरकार के पास बायोमास आधारित विद्युत परियोजनाओं के बीस से ज़्यादा प्रस्ताव लंबित हैं और सभी निवेशक निजी भूमि पर ही परियोजना स्थापित कर रहे हैं. इसके अलावा ग्रिड कनेक्टिविटी और प्रदूषण निवारण विभाग की अनुमति लेने में भी अनावश्यक समय लगता है. लापरवाही का आलम यह है कि इन परियोजनाओं के प्रस्तावों को दो वर्ष से ज़्यादा बीत गए, लेकिन राज्य सरकार की ओर से अंतिम स्वीकृति अभी तक जारी नहीं की गई है. बार-बार परेशान होने के कारण निवेशक अब गुजरात की ओर रुख़ कर रहे हैं, क्योंकि वहां एकल खिड़की प्रणाली से परियोजना को समय सीमा में स्वीकृत कर दिया जाता है और निवेशकों को अनुमतियों के लिए अलग-अलग विभागों में भटकना नहीं पड़ता. राज्य सरकार की लालफीताशाही के कारण अब लगता है कि पवन ऊर्जा परियोजना के निवेशकों ने मध्य प्रदेश को अलविदा कह दिया है. 5500 मेगावाट की कुल क्षमता के विरुद्ध मध्य प्रदेश में अब तक 212 मेगावाट की ही पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित हो सकी हैं. अनुकूल माहौल न बन पाने के कारण निवेशकों और डेवलेपर्स कंपनियों ने यहां पंजीयन तो 1200 मेगावाट के कराए थे, लेकिन अब उनका रुझान गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान की ओर ज़्यादा है. इन राज्यों में पवन ऊर्जा परियोजना के लिए सरकारी भूमि की सहज उपलब्धता, कम प्रोसेसिंग शुल्क और बिजली की उच्च क्रय दरों ने निवेशकों को ख़ासा आकर्षित कर लिया है. गौरतलब है कि राज्य में पवन ऊर्जा की शुरुआत 1995 में हुई थी. राज्य में इस ओर अनदेखी की गई, परिणामस्वरूप दूसरे राज्यों में यह परियोजना बाद में शुरू होने के बावजूद मध्य प्रदेश की अपेक्षा ज़्यादा विकास की राह पर है. निवेशकों को अवसाद में लाने की शिवराज सिंह सरकार की नीति का इससे बेहतर उदाहरण कोई नहीं हो सकता है कि केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा पवन ऊर्जा से उत्पादित बिजली के लिए ख़रीद दर 5.44 रुपये प्रति यूनिट निर्धारित की गई है, जबकि राज्य सरकार यहां के निवेशकों को औसतन 3.35 रुपये प्रति यूनिट से ज़्यादा नहीं देना चाहती.

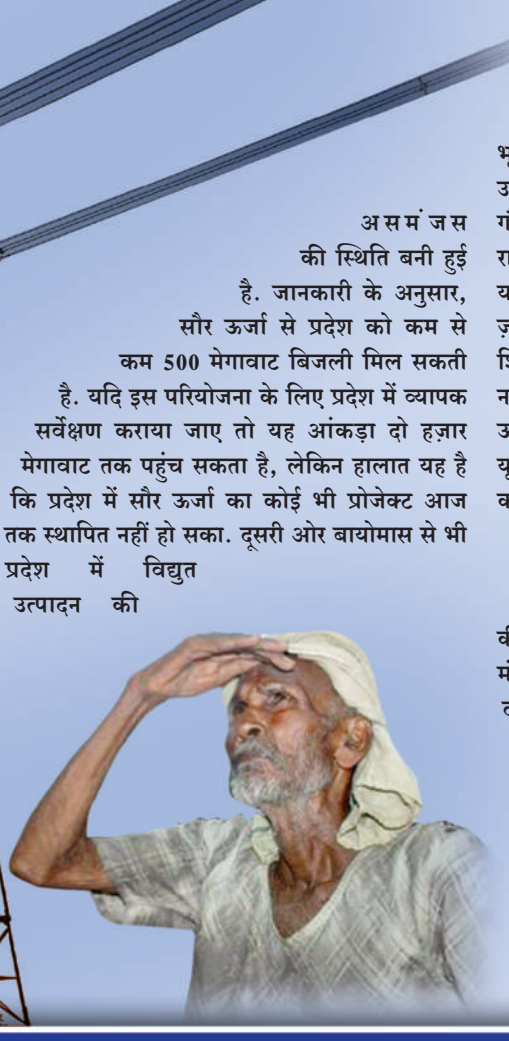

किसानों से पांच अरब की वसूली

मध्य प्रदेश विद्युत मंडल और उसकी सहायक बिजली कंपनियों की वित्तीय स्थिति ख़राब हो रही है. भारी घाटा सह रहे विद्युत मंडल ने बिजली कंपनियों को अपनी स्थिति सुधारने की हिदायत दी है. कंपनियों ने बकाएदारों से विद्युत शुल्क वसूलने की तैयारी पूरी कर ली है. राज्य की तीन विद्युत वितरण कंपनियों को किसानों से लगभग 5 अरब रुपये वसूली करने हैं, लेकिन राज्य सरकार के हस्तक्षेप के कारण यह वसूली अब तक नहीं की जा सकी. केवल पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को ही दो लाख किसानों से लगभग 250 करोड़ रुपये वसूलने हैं. इस वर्ष राज्य में गेहूं की अच्छी फसल हुई है, इसे ध्यान में रखकर बिजली कंपनियां मान रही हैं कि किसान बकाया भुगतान की स्थिति में आ चुके हैं.

(शेष पृष्ठ 18 पर)

चौथी दुनिया

राज्य शासन ने उच्च न्यायालय के आदेश की विधि विभाग से समीक्षा करने के उपरांत तीनों अधिकारियों को साकेत कवीर धाम और दांतेवाड़ा में बहाल करके पदस्थ कर दिया.

चौथी दुनिया

अशोक नगर क्षेत्र में अंत्योदय राशन कार्डधारियों की संख्या 26244, बीपीएल धारकों की संख्या 61521 और एपीएल राशन कार्डधारियों की संख्या 99049 है, जिन्हें ज़िले में संचालित 190 उपभोक्ता भंडारों के माध्यम से राशन उपलब्ध कराया जाता है.

सार -संक्षेप

महिलाएं पुलिस में झूठी रिपोर्ट लिखवाती हैं

महिलाओं के हितों की सुरक्षा के लिए बनाए गए दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा जैसे विशेष क़ानून का महिलाएं ही नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं. महिला थाना पुलिस के पास 50 फीसदी ऐसे मामले आ रहे हैं जिनमें पति या ससुराल पक्ष के ख़िलाफ़ झूठी शिकायत का प्रकरण दर्ज़ कराने के प्रयास किए जाते हैं. यह अलग बात है कि सच्चाई सामने आने के बाद भी पुलिस क़ानून के साथ खिलवाड़ करने वाली झूठी महिलाओं के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करती.

थानों में झूठी शिकायतें ससुराल पति या ससुराल पक्ष के अन्य लोगों पर अनावश्यक दबाव बनाने और परेशान करने के लिए की जाती हैं. झूठी शिकायत करने वाली महिलाएं ससुराल वालों को जेल अथवा हवालात की हवा खिलवाने की धमकी देकर मनमानी करती हैं.

महिला थाना की एक अधिकारी के मुताबिक़ परामर्श केन्द्र में आने वाले अधिकतर मामलों में पत्नी द्वारा पति व ससुराल वालों पर अनावश्यक दबाव बनाने का प्रयास किया जाता है. कई बार अड़ियल रवैये के कारण काउंसलिंग नाकाम हो जाती है. ऐसी स्थिति में पत्नी द्वारा दहेज प्रताड़ना या घरेलू हिंसा का प्रकरण दर्ज़ करने का दबाव बनाया जाता है. उन्होंने बताया कि यदि प्रकरण दर्ज़ नहीं किया जाता है तो वे महिलाएं महिला आयोग व न्यायालय में वाद लगा देती हैं. न्यायालय के आदेश पर हमें दहेज प्रताड़ना का प्रकरण दर्ज़ करना पड़ता है.

ट्रैफिक चौकी पर अवैध वसूली जारी है

मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के तमाम उपाय विफल हो चुके हैं और अब भ्रष्टाचार खुलकर सड़क पर आ गया है. उत्तरी मध्य प्रदेश में ट्रैफिक चौकी और नाकों पर अवैध वसूली मानो सरकारी दस्तूर बन गया है.

एक माह पूर्व राज्य के मुख्य सचिव अवनि वैश्य का पारिवारिक सामान दिल्ली से भोपाल ला रहे ट्रक के ड्राइवर से मुरैना के बॉर्डर चेकपोस्ट पर अवैध वसूली के मामले को लेकर मीडिया और प्रशासन में हंगामा मचा था. तब उम्मीद बनी थी कि मुख्य सचिव इस खुलेआम भ्रष्टाचार पर नकेल ज़रूर लगाएंगे, मगर हुआ कुछ नहीं.

उसके तुरंत बाद भिण्ड-इटावा क्षेत्र के भाजपा सांसद अशोक अर्गल ने इटावा ट्रैफिक चौकी पर वाहन चालकों से अवैध वसूली करने वाले होमगार्ड के तीन सिपाहियों को रंगे हाथों पकड़ा. सांसद ने इसकी शिकायत चंबल क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक से की. अर्गल ने होमगार्ड सिपाही सिंह, कल्याण और मैथिली के अलावा ट्रैफिक सूबेदार अतुल सिंह और थाना प्रभारी अजय भार्गव को हटाने की मांग की.

इटावा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आर के सागर ने इस घटना को सही बताया और कहा कि सांसद की शिकायत पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी.

फ़रार विधायक द्वारा विधायक निधि का उपयोग

मध्य प्रदेश के पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित कांग्रेस विधायक बृजेन्द्र सिंह राठौर दिसम्बर 2008 में चुनाव के समय विधायक सुनील नायक की हत्या सहित तीन मामलों में आरोपी बनाए गए हैं और पुलिस को उनकी तलाश है. कहा जाता है कि वह पुलिस की पहुंच से बाहर हैं, फिर भी टीकमगढ़ ज़िला कलेक्टर और दूसरे सरकारी अधिकारियों को वह विधायक निधि के उपयोग के बारे में आदेश-निर्देश और अनुशंसा लिखकर पत्र भेजते रहते हैं. पिछले विधानसभा सत्र में न्यायालय से अग्रिम जमानत लेकर राठौर ने विधानसभा में उपस्थित होकर विधायक पद की शपथ ली थी. जमानत की शर्त पूरी नहीं होने पर भी पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाई. विधायक राजेन्द्र सिंह राठौर पर भाजपा विधायक सुनील नायक के अलावा ग्राम चन्द्रपुरा के सरपंच की हत्या और भाजपा नेता भूपेन्द्र पर जानलेवा हमले के भी मामले दर्ज़ हैं और इन सभी मामलों में पुलिस को उनकी तलाश है. विधायक किसी अज्ञात स्थान पर आराम से रह रहे हैं और विधायक निधि के ज़रिए अपने क्षेत्र में काम भी करा रहे हैं. बताया जाता है कि पुलिस ने राठौर पर 25 हज़ार रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है.

बृजेन्द्र सिंह

फ़रारी के बावजूद विधायक राठौर का कोई भी प्रशासनिक कार्य रूका नहीं है. अफ़सरों पर उनका दबदबा क़ायम है. अपने चुनाव क्षेत्र के विकास के लिए विधायकों को दी जाने वाली निधि का उपयोग राठौर बड़ी दबंगई के साथ कर रहे हैं. उन्होंने पिछले वित्त वर्ष में पूरे 77 लाख रुपये के निर्माण और लोकहित के कार्यों के प्रस्ताव शासन को भेजे. इसके अलावा ज़िला योजना मंडल को 8 मार्च को 49 लाख रुपये के और 18 मार्च को 28 लाख रुपये के प्रस्ताव विधायक निधि के उपयोग बाबत भेजे. इन पर अमल भी हुआ. ज़िला योजना मंडल के सदस्य सचिव व ज़िला कलेक्टर और कई सरकारी अधिकारी भी इसे ठीक मानते हैं. जब इस बारे में पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ का ध्यान आकर्षित किया गया, तो पुलिस अधीक्षक आकाश जिंदल ने कहा कि पुलिस ब्रजेन्द्र सिंह राठौर को गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश कर रही है. विधायक निधि के उपयोग के प्रस्ताव कहां से आ रहे हैं और कौन ला रहा है, इसका पता लगाया जाएगा. उन्होंने कहा कि हमें भरोसा है कि जल्दी ही फ़रार विधायक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

महिला सरपंचों को काम नहीं दिया

महिला सशक्तिकरण और लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी के लिए आरक्षण व्यवस्था लागू करने के सराहनीय सरकारी प्रयासों के बावजूद पुरुष प्रधान समाज में आज भी महिला जनप्रतिनिधियों को पुरुषों की कृपा पर निर्भर रहना पड़ता है. मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में दबंगों के दबाव के कारण पांच ग्राम पंचायतों की महिला सरपंचों को पंचायत संचालन होने के चार माह बाद भी अपने पद पर काम नहीं करने दिया जा रहा है.

अधिकृत सूत्रों के अनुसार बड़ामलहरा विकास खण्ड की मेलवार, बमनी, सुरजपुरा कलां, जसगुवां और सुरजपुरखुर्द ग्राम पंचायतों में महिला सरपंचों को पदभार ग्रहण नहीं करने दिया गया है. इस बारे में बताया जाता है कि इन पंचायतों के पूर्व सरपंचों और पंचायत सचिवों के ख़िलाफ़ राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के कार्यों में धांधली, घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोपों की रिपोर्ट जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने पुलिस में दर्ज़ कराई है. अतः ये पूर्व सरपंच और सचिव नहीं चाहते कि नई सरपंच काम संभाले और उनके घपले, घोटालों के दस्तावेज पुलिस के सुपुर्द कर उन्हें मुसीबत में डाल दें. यद्यपि पंचायत सचिवों को शासन ने निलंबित किया है, लेकिन वे अपना दबदबा बनाए हुए हैं. मेलवार ग्रामपंचायत की सरपंच श्रीमती उर्मिला विश्वकर्मा और नए पंचायत सचिव का कहना है कि उन्हें अभी तक पंचायत की चेक बुक तक नहीं मिली है. इसके लिए वे जनपद पंचायत और बैंक शाखा के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन बैंक खाते में अभी पूर्व सरपंच का ही नाम दर्ज़ है. बमनी ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती सुशीला शर्मा का भी कहना है कि उनकी पंचायत के पूर्व सरपंच पर 14 लाख रुपये के ग़बन का मामला पुलिस में दर्ज़ है. इसलिए वे उन्हें पद का चार्ज नहीं देना चाहते हैं. कई बार शासन से वे शिकायत भी कर चुकी हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

आंखों देखा नक्सलवाद

विदेशी हथियारों से लैस नक्सलवादी समूहों के पास सरकार से अधिक मज़बूत सूचनातंत्र है. गहराई तक जानें तो, इन नक्सलवादी समूहों के पास पैसा, हथियार, योजना सभी कुछ उम्मीदों से कहीं ज़्यादा है. लेकिन, ये समूह जन विश्वास और जन आस्था धीरे-धीरे खोते जा रहे हैं. उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के मध्य पड़ने वाले कुछ ऐसे भूभाग हैं जहां से नक्सलवादियों को लगातार गुज़रना पड़ता है. केंद्र सरकार बिना स्थानीय मदद के इस समस्या पर नियंत्रण कभी नहीं पा सकती. नक्सलवादी समूहों का प्रतिदिन सामना करने वाले और उनके नियंत्रण वाले क्षेत्र में समाज सेवा कर रहे सुधीर साबत का यह कथन वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा नक्सलवादियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के पूर्णतया विपरीत है. उड़ीसा राज्य में आंध्र प्रदेश की सीमा से सटे हुए गंजाम ज़िले के पात्रपुर, स्वरोडा, भंजनगर, और जगन्नाथ प्रसाद जैसे क्षेत्रों में सामाजिक संस्था इंडियन सोसायटी फॉर रूलर डेवेलपमेंट पिछले 14 सालों से लगातार काम कर रही है. इस संस्था का मुख्यालय ब्रम्हापुर में स्थित है. सोसायटी के डायरेक्टर सुधीर साबत ने नक्सलवादियों के जीवन को बहुत क़रीब से देखा है. पिछले दिनों संस्था के कार्यों के वास्ते भोपाल आए सुधीर साबत ने चौथी दुनिया समाचार पत्र के साथ बातचीत करते हुए नक्सलवाद के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से अपनी बात रखी.

सुधीर साबत

सुधीर साबत के अनुसार, नक्सलवाद प्रभावित आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा सहित छत्तीसगढ़ के विभिन्न भागों में बड़ी संख्या में नक्सलवादी समूह सक्रिय हैं. नक्सलवादी अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए युवा और शिक्षित हो रहे वर्ग में से अपने प्रतिनिधियों की बालात खोज करते हैं. हर गांव से नक्सलवादी 5 युवक इस आंदोलन में शामिल होने के लिए चुने जाते हैं. अबोध युवकों को प्रशिक्षण के दौरान न सिर्फ़ शारीरिक रूप से नक्सलवादी बनाया जाता है, बल्कि उनका मानसिक परिवर्तन भी नई विचारधारा की ओर कर दिया जाता है. सुधीर साबत के अनुसार गांव वाले स्वेच्छा से इस अभियान में युवकों को नहीं भेजते, परंतु जान जाने की डर से गांव के युवक इस कथित क्रांति की धारा में शामिल कर लिए जाते हैं. हाई स्कूल, कॉलेज और 10+2 शिक्षा प्राप्त युवक-युवतियों को इस आंदोलन से जोड़ा जाता है. सुधीर साबत के अनुसार, नक्सलवादी समूहों को धन देने का काम बड़ी तादाद में निजी मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेजों द्वारा बड़े ठेकेदारों के द्वारा और कॉरपोरेट क्षेत्र के माध्यम से किया जाता है. इस संदर्भ में स्थानीय स्तर पर संभवत: प्रत्येक व्यक्ति को पूरी जानकारी है. इसकी संभावना नहीं के बराबर है कि नक्लवादी समूहों को धन का आभाव होगा. अपने क्षेत्र में कार्य करते हुए सुधीर साबत ने नक्सलवादियों के पास विदेशी हथियारों को बड़े पैमाने पर देखा है. नक्सलवादी प्रत्येक दस गांव के बीच अपना शस्त्र गोदाम स्थापित करते हैं. नक्सलवाद की योजना के लिए प्रत्येक गांव में एक लीडर, प्रत्येक दस गांव में एक लीडर और इसी तरह 10-10 के समूहों में इनके नेतृत्व की संख्या बढ़ती जाती है. सुधीर साबत के मुताबिक, उड़ीसा क्षेत्र का कंदमाल क्षेत्र वर्तमान में नक्सलवादियों का गढ़ बन चुका है.भुवनेश्वर से 280 किमी दूर स्थित इस क्षेत्र में बड़े जंगल होने के चलते और छिपने की पर्याप्त जगह होने के कारण नक्सलवादियों को एकत्र होने में सुविधा होती है. नक्सलवाद की मुहिम में वर्ष 1956 के बाद से लगातार परिवर्तन होता आया है. वर्तमान में नक्सलवादी नेता इस वारदात और धमकियों के तंत्र का उपयोग स्वयं का घर भरने के लिए कर रहे हैं, जिसका प्रमाण पिछले दिनों उड़ीसा में एक बड़े नक्सलवादी नेता की पत्नी के एकाउंट में पुलिस द्वारा 1 करोड़ रुपये की राशि का पकड़ा जाना, माना जा सकता है. सुधीर साबत बताते हैं कि नक्सलवादी समूहों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनकी संस्था ने कई प्रयास किए हैं, जिसके तहत नक्सलवादियों से सीधी बातचीत भी की गई है. नक्सलवादी समूह सरकार द्वारा चलाई जा रही योजन-ाओं के प्रति पूर्णत: असंतोष प्रदर्शित करते हुए क्षेत्र के विकास, रोज़गार और दूसरे बुनियादी सुविधाओं को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जबकि स्थिति इसके विपरीत है. नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में सरकारी अधिकारियों ने जाना बिल्कुल बंद कर दिया है. ठेकेदार काम करने को तैयार नहीं हैं. नतीजा ये सभी क्षेत्र विकास की गतिविधियों से पूरी तरह कट चुके हैं.

केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही ऑपरेशन ग्रीन हंट भी इन क्षेत्रों में पूरी तरह क्रियान्वित नहीं की जा सकती. सरकार के पास सूचनातंत्र की कमी है, जबकि नक्सल-वादी किसी भी क्षेत्र की सूचना कुछ ही मिनटों में अपने तंत्र के माध्यम से हासिल कर पाने में पूरी तरह से सक्षम हैं. 50 किलोमीटर वृत्त के क्षेत्र में नक्सलवादियों का कोई भी समूह आपसी सूचनातंत्र के बड़े जाल में सुरक्षित रहता है. सरकार चाहकर भी इस सूचनातंत्र को आतंकित ग्राम वासियों के कारण लागू नहीं कर सकती. उड़ीसा सरकार द्वारा नक्लवाद के लिए बनाई गई कोई भी योजना कंदमाल जैसे वन आच्छादित क्षेत्र में कभी सफलता प्राप्त कर सकेगी, इसमें संदेह है. नक्सलवादियों पर लगाम लगाने के लिए सुधीर साबत ने गांव वालों को आत्मनिर्भर बनाना शिक्षा-प्रणाली का व्यापक विस्तार करना और आत्मनिर्भरता के लिए रोज़गार के नए अवसरों को ईमानदारी से गांव तक पहुंचाना, एक महत्वपूर्ण कदम माना है. सुधीर साबत के मुताबिक़, बेहतर भविष्य के लिए क्रांति का सूत्रपात करने के स्वप्न दिखाकर युवा वर्ग को नक्सलवाद की ओर मोड़ा जाता है. इस बुनियादी व्यवस्था की दिशा परिवर्तन करने के स्थान पर हम नक्सलवाद से संघर्ष करने की कोशिश कर रहे हैं. उड़ीसा क्षेत्र में ही कुछ गांव ऐसे बचे हैं, जिन्होंने नक्सलवादियों को किसी भी तरह का सहयोग देने या उनसे संबंध रखने से इंकार कर दिया. इन गांवों में अभी भी नक्सलवाद नहीं पहुंच पाया है.

उड़ीसा उन क्षेत्रों में से है जहां से नक्सलवादी आंध्रा से छत्तीसगढ़ तक और छत्तीसगढ़ से आंध्रा तक का सफ़र बिना रोकटोक करते हैं. सुधीर साबत के अनुसार, नक्सलवादी आम तौर पर जंगलों के रास्ते पैदल चलना ज़्यादा उचित समझते हैं. साइकिलों पर चलने वाले नक्सलवादी अमूमन सूचनातंत्र के लिए काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, इसके अतिरिक्त नक्सलवादियों के वाहनों को भी उड़ीसा में बेरोकटोक हथियार बंद स्थिति में घूमते देखा जा सकता है. इंडियन सोसायटी फॉर रूलर डेवेलपमेंट का मुख्यालाय भुवनेश्वर से 180 किमी दूर है. गंजाम ज़िले की सीमा आंध्र प्रदेश के इच्छापुर ज़िले से सीधे जुड़ती है. नक्सलवादी समूहों ने दंतेवाड़ा की घटना को अंजाम देने के पूर्व इसी रास्ते से छत्तीसगढ़ तक आवागमन किया था. सुधीर साबत के अनुसार, नक्सलवाद की समस्या अब धीरे-धीरे क्षेत्र के रूके हुए विकास और आतंकवाद के प्रति युवकों के रूझान से जुड़ती जा रही है. बेरोज़गारी के चलते और घटते खेती के रकबे के कारण ग्रामीण युवा इस कथित क्रांति की ओर मुड़ रहा है. भारत सरकार की आयकर में छूट संबंधी 35 एसी, की छूट का पूरा उपयोग नक्सलवादी समूहों द्वारा धन संग्रह के लिए किया जा रहा है. सुधीर साबत के मतानुसार, स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका नक्सलवाद को लगाम लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण हो सकती है. स्वयंसेवी संगठनों में से वे समूह जो नक्सलवादियों के साथ सीधी बातचीत कर उन्हें राष्ट्र निर्माण और विकास की ओर मोड़ने की ताक़त रखते हैं, का उपयोग इस अभियान के तहत किया जाना चाहिए. माओवादी संगठनों से संबद्ध नक्सलवादियों द्वारा भी जन, जंगल और ज़मीन के लिए संघर्ष क्रांति के माध्यम से किया जा रहा है. गांधीवादी चिंतन या विचारधारा पर इन समूहों का कोई प्रभाव नहीं है. राज्य या केन्द्र सरकार यदि अपने स्तर पर स्वयंसेवी संगठनों के उस वर्ग को खोज करे, जो इस समस्या के मूल में छिपे असंतोष को शांत कर पाने में सक्षम हो, तो नक्सलवाद का स्थाई हल निकाला जा सकता है. इस आंदोलन को रोकना राष्ट्र के एकीकरण के लिए आवश्यक मानते हुए सुधीर साबत का मत है कि आपसी टकराहट इन घने जंगलों के मध्य सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है. इन क्षेत्रों में कार्यरत छोटे शासकीय कर्मचारियों सहित नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में कार्यरत बड़े अधिकारी तक आतंक के कारण नक्सलवादियों का हिस्सा बन चुके हैं.

यहां तक कि, इन अधिकारियों द्वारा अर्जित की गई अवैध धन राशि का एक बड़ा हिस्सा इन नक्सलवादियों को चंदे के रूप में नियमित दिया जाता है. नक्सलवाद की समस्या धीरे-धीरे क्षेत्र में धार्मिक उन्माद को बढ़ाने या घटाने का भी एक कारण बन रही है. नक्सलवादी समूह अपनी गतिविधियों के लिये हिंदुओं और इसाई मिशनरी के साथ पक्ष-विपक्ष में कार्यवाही करने लगे हैं. कंदमाल में एक साल पूर्व लोखड़ानंद सरस्वती की हत्या इस कथन की पुष्टि के लिए पर्याप्त है. धार्मिक आधार पर नक्सलवादी समूह समाज को विघटित कर उसमें आतंक भर देना चाहते हैं. उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश तीनों ही राज्यों में हिंसा की गतिविधियों का आधार यदि नक्सलवादियों द्वारा धार्मिक कर दिया गया तो यह समस्या और घातक हो जाएगी. अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर सुधीर साबत का मानना है कि अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में होने वाली सामाजिक गतिविधियों में नक्सलवादी दखल नहीं देते और न ही किसी स्वयंसेवी संगठन को इस बात के लिए मजबूर करते हैं, कि वे उनकी विचारधारा के अनुसार अपने कार्यो का संचालन करे.

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के जन प्रतिनिधियों के बारे में स्वयंसेवी संगठन के संचालक का मत है कि जनप्रतिनिधि इन क्षेत्रों में आतंक के सामने नतमस्तक हो चुके हैं. व्यापारिक और राजनैतिक गतिविधियों के शून्य हो जाने के कारण नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र इन तीनों ही राज्यों में लकवाग्रस्त हो चुके हैं. केन्द्र सरकार दिल्ली में बैठकर नक्सलवाद को आतंकवाद समझते हुए इसके ख़ात्मे की कोई भी योजना बना ले, परंतु एक सामाजिक समस्या के रूप में 1956 में पैदा हुआ असंतोष धीरे-धीरे युवा वर्ग की आय और छीनकर कुछ हासिल करने की प्रक्रिया का एक हिस्सा बनता जा रहा है. इसका परिणाम यह है कि नक्सल-वाद को जड़ से उखाड़ देने की बात एक मिथ्या बनकर रह गई है.

सुधीर साबत के अनुसार, उड़ीसा राज्य में इन दिनों नक्सलियों का भारी जमावड़ा है. बार-बार यह अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है कि इस राज्य में नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं. राज्य से मिल रही सूचनाओं के अनुसार, दंतेवाड़ा की घटना के बाद आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ से पलायन कर बड़ी तादात में नक्सली उड़ीसा राज्य में पहुंच चुके हैं. दंतेवाड़ा की घटना के बाद से इन प्रभावित राज्यों में पुलिस तंत्र का नक्सली प्रभवित क्षेत्रों में निष्क्रिय होना और सूचना तंत्र का यथावत होना इस अभियान के प्रति बढ़ती जा रही उपेक्षा का परिणाम है. नक्सलवादी बेरोकटोक अपनी योजनाओं पर लगातार काम कर रहे हैं, जबकि केन्द्र और राज्य सरकार उच्च स्तर पर योजना बनाने के नाम पर बैठकों पर संभवत: और कुछ नहीं कर रही है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

भाजपा और कांग्रेस में

रेलवे ट्रैक पर श्रेय की दौड़

वैसे तो विकास के नाम पर सरकार के ढुलमुल रवैये से हर कोई वाकिफ़ है, फिर भी अगर धोखे से कोई विकास कार्य हो गया तो क्रेडिट लेने के लिए राजनैतिक दल बिल्लियों की तरह झपट पड़ते हैं. ऐसा ही कुछ नज़ारा भाजपा और कांग्रेस के बीच देखने का मिला.

ग्वालियर से श्योपुर तक चलने वाली छोटी लाईन रेल को बड़ी लाईन में किसने परिवर्तित करवाया, इसका श्रेय लेने के लिए इन दिनों कांग्रेस और भाजपा के मध्य संघर्ष चल रहा है. भाजपा के नेता इसे अपनी मांग की पूर्ति बताकर विजयी मुद्रा में खड़े हैं, तो वहीं क्षेत्र के प्रभावशाली केंद्रीय मंत्री सिंधिया भी अन्य केंद्रीय मंत्रियों से अपनी वाहवाही का गान करवा रहे है.

ग्वालियर चंबल संभाग में ग्वालियर से श्योपुर तक चलने वाली नैरागेज रेल लाईन ब्राडगेज में क्या बदली ज़िले में श्रेय लेने की प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो गई. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर और राज्यसभा सदस्य प्रभात झा ने छोटी लाईन पर चलने वाली ट्रेन में बैठकर ही अपना चुनाव प्रचार अभियान पूरा किया था. यह छोटी लाईन आम व्यक्तियों के लिए कितनी बड़ी परेशानी थी, इसका एहसास इन नेताओं को नहीं था. क़ानून का पालन करने का दावा करने वाले इन नेताओं के सैंकड़ों समर्थकों ने इस ट्रेन की छत पर बिना टिकट बैठकर भाजपा के झंडे लहराये थे.

यही नैरोगेज रेलवे लाईन अब ब्राडगेज में बड़ी परिवर्तित हो गई है. इस परिवर्तन का श्रेय किसे जाए इसके लिए भाजपा और स्थानीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के मध्य संघर्ष जारी है. भाजपा नेताओं के इस दावे को कि उनकी मांग की पूर्ति करने के लिए ही इस लाईन का विस्तार हुआ है. सिंधिया ने भी मोर्चा खोल लिया है. पिछले दिनों केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल एवं रेल राज्य मंत्री मुनियप्पा का हाथ पकड़कर उन्हें क्षेत्र में घुमाते हुए सिंधिया ने उनसे ही बयान दिलवा डाला.

मंत्री सिब्बल ने बयान में कहा कि नैरोगेज में परिवर्तन ज्योतिरादित्य सिंधिया की मेहनत का ही नतीजा है. इस मौक़े पर सिंधिया ने बता दिया कि 1879 में नैरोगेज लाईन उनके पूर्वजों द्वारा ही प्रारंभ की गई थी. दोनों ही पक्ष इस विकास का श्रेय लेने के लिए अपने-अपने दावे करते रहे पर क्षेत्र की जनता को इस ब्राडगेज लाईन से बहुत उम्मीदें है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

सार -संक्षेप

पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारी में हाथापाई

मध्य प्रदेश पुलिस में अनुशासन नहीं रह गया है. यहां तक कि कुछ छोटे कर्मचारी अपने आला अफ़सरों की भी परवाह नहीं करते हैं. हाल ही में भिण्ड में पुलिस अधीक्षक चंचल शेखर और थाना प्रभारी एमके वर्मा के बीच कार्यालय में ही हाथापाई की घटना से पुलिस विभाग शर्मिंदा है और प्रशासन के शीर्ष अधिकारी भी चिंतित हैं. घटना के बारे में बताया जाता है कि पुलिस थाना प्रभारी वर्मा का तबादला भिण्ड से मुरैना कर दिया गया था और वह पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कार्यमुक्ति आदेश लेने गए थे. जब वह पुलिस अधीक्षक से मिलने गए तो कुछ ही देर में इन दोनों में हाथापाई होने लगी. बताते हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर काफ़ी समय से दोनों में विवाद चल रहा था.

बाद में चंबल क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक संजय कुमार झा को इस बारे में जब जानकारी मिली तो उन्होंने कहा कि इस घटना के बारे में दोनों ही पुलिसकर्मियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है, इसके बाद आगे की कार्यवाही पर विचार किया जा सकता है.

करे कोई और भरे कोई

पुराने टेलीफोन बिलों का बकाया भुगतान न होने के कारण मध्य प्रदेश सरकार के छह मंत्रियों के टेलीफोन काट दिए गए हैं. जब फोन कट गए तो राज्य के मंत्रियों में हड़कंप मचा और उन्होंने गृह विभाग से अपने बिलों के भुगतान के बारे में जानकारी मांगी. पता चला कि सभी बिलों का नियमित भुगतान हो रहा है.

इस पर गृह विभाग ने बीएसएनएल से फोन काटने के बारे में जब जवाब-तलब किया, तो वहां से जवाब मिला कि 1999 और उससे पहले के सरकार के मंत्रियों के टेलीफोन के 30 से 32 हज़ार रुपये तक के बिल बकाया हैं.

अब गृह विभाग पुराने बकाया बिलों की तलाश कर रहा है. सरकार में पहले मंत्रियों के फोन बिलों का भुगतान सामान्य प्रशासन विभाग करता था, लेकिन अब यह ज़िम्मेदारी गृह विभाग को दी गई है. दोनों विभाग पुराने बिलों की तलाश में हैं.

वेतन की मांग की तो खेत और घर जला दिया

एक ज़माने में हिटलर जैसे तानाशाहों से कोई अपने हक़ की मांग करता था तो उसे फांसी दे दी जाती थी या फिर ज़िंदा जला दिया जाता था. सामंती तबका किसानों का शोषण करते थे. ख़ैर, वो उस ज़माने की बात थी, अब ज़माना बदल गया है. लेकिन मध्य प्रदेश के सिंगरौली में हाल में हुए एक वाकये ने उस ज़माने की याद को फिर से ताजा कर दिया है.

लोकतंत्र में अभी भी सामंती विचार धारा का बोलबाला है. इसका जीता-जागता प्रमाण चितरंगी पंचायत के ढिघर गांव में देखने को मिला. बेगारी का विरोध करने की सज़ा एक परिवार को यह मिली कि उसके खेत-खलिहान और घर सभी जलकर राख कर दिए गए. आज इस आतंक से पीड़ित परिवार की आवाज़ सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है. सिंगरौली ज़िले के जनपद पंचायत क्षेत्र चितरंगी के डिघर खुर्द गांव में 29 मार्च को एक ग़रीब के मकान और खेत में आग लगा दी गई. गोमती नाई नामक इस व्यक्ति का कसूर बस इतना था कि इसने सामंतों की बेगारी करने से इंकार कर दिया था. इस घटना के पीछे इसी क्षेत्र के प्रभावशील लोगों के नाम सामने आ रहे हैं. यही वज़ह है कि, ज़िले की पुलिस भी इस मामले के प्रति अपने रवैये को उदा-सीन बनाए बैठी है. गोमती नाई पुत्र शालिक राम नाई, उम्र 52 वर्ष, जब उसने अपने काम का पारिश्रमिक मांगा तो ग्राम पंचायत के सचिव लुटई पुत्र बजरंगी, इंस्पेक्टर पुत्र राजबहादुर सिंह और उस्ताद सिंह ने गोमती के खेत खलिहान और मकान को बर्बाद कर दिया. प्राप्त जानकारी के मुताबिक, ग्राम पंचायत के सदस्य लुटई सिंह द्वारा इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार से काफ़ी अवैध धन राशि एकत्र कर ली गई है. अब इसी धन बल का उपयोग ग़रीब परिवारों को परेशान करने के लिए किया जाता है. गांव की मां कुडार वासिनी स्वयंसहायता समूह में गोमती बाई को और उसकी पत्नी कलावती को प्राथमिक शाला में खाना बनाने के काम पर लगाया गया था. कलावती स्वयं समूह की सदस्या है, फिर भी उसे 6 महीने तक काम करने के बाद नौकरी से निकाल दिया गया. कलावती द्वारा वेतन मांगे जाने पर जान से मारने की धमकियां दी जाने लगी, जिसकी परिणिति अग्निकांड के रूप में हुई है. लुटई सिंह वर्तमान में गांव के पंचायत होने की स्थिति में उनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है, और वर्तमान में देवसर न्यायालय से आईपीसी की धारा 420 के तहत उनके विरूद्ध प्रकरण भी विचाराधीन है. उपरोक्त प्रकरण की रिपोर्ट होने के बावजूद भी स्थानीय पुलिस ने इस मामले पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई है, जबकि प्रताड़ित परिवार भुखमरी की कगार तक पहुंच चुका है. विंध्य क्षेत्र में सामंती विचारधारा का बोलबाला होने के कारण शोषण की घटनाओं को पुलिस भी सामान्य घटनाओं की तरह ही देखती है, जिसके परिणामस्वरूप अत्याचार करने वालों के हौसले काफ़ी हद तक बुलंद हैं.

ए बी सिंह
feedback@chauthiduniya.com

बीमारी कुछ, इलाज कुछ

पेज एक का शेष

इसीलिए कंपनियां अगली फसल में सिंचाई के लिए बिजली देने से पहले ही किसानों से बकाया राशि वसूल कर लेना चाहती हैं. किसान राहत योजना की अवधि सरकार ने 31 दिसंबर 2009 से बढ़ाकर 30 अप्रैल 2010 कर दी है. इस कारण लगभग साढ़े तीन लाख किसानों से बिजली शुल्क वसूलना फिलहाल स्थगित है, लेकिन 30 अप्रैल के बाद बिजली कंपनियां बकाया वसूली अभियान चलाने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगी. बुंदेलखंड को अलग से 100 मेगावाट बिजली राज्य के बुंदेलखंड अंचल में बिजली संकट दूर करने के लिए केंद्र सरकार अलग से 100 मेगावाट बिजली केंद्रीय पूल से उपलब्ध कराएगी. यह बिजली केवल बुंदेलखंड अंचल को दी जाएगी. मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेश पचौरी ने छतरपुर में कांग्रेस के पंच-सरपंच सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी. पचौरी ने कहा कि राज्य सरकार बिजली संकट को हल करने में नाकाम रही है. इसका सबूत यही है कि विद्युत उत्पादन संयंत्र जब-तब ख़राब हो जाते हैं और एक माह तक बंद पड़े रहते हैं. बिजली बोर्ड की आर्थिक स्थिति भी ख़राब है. संकट के बावजूद राज्य सरकार दूसरे राज्यों को बिजली बेचती है, यह यहां के किसानों और ग्रामीणों के साथ छल है. गांवों में हर दिन 12 से 15 घंटे बिजली कटौती हो रही है.

दो बिजली संयंत्र कई दिनों से बंद

बिजली संयंत्रों की देखरेख पर ध्यान न दिए जाने के कारण सतपुड़ा में 210 मेगावाट और अमरकंटक में 120 मेगावाट क्षमता के दो विद्युत उत्पादन संयंत्र बंद पड़े हैं. सतपुड़ा विद्युत संयंत्र पिछले डेढ़ माह से बंद है. इसे 30 मार्च तक चालू किया जाना था, लेकिन यह अभी तक चालू नहीं हो सका है. सतपुड़ा ताप विद्युत गृह की यूनिट क्रमांक 9 में टरबाइन ब्लेड टूट गई थी और इसे सुधारने के लिए 31 मार्च तक का समय तय किया गया था, लेकिन मरम्मत का काम अब तक पूरा नहीं हो सका है. वहीं अमरकंटक ताप बिजलीघर की यूनिट क्रमांक 4 संरचनात्मक सुधार के कारण बंद पड़ी है. इससे 120 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है. इस यूनिट को फिर से चालू करने के लिए 30 अप्रैल तक का समय तय किया गया है.

जबलपुर में गोबर गैस संयंत्र

गोबर गैस प्लांट से उत्पादित होने वाली बिजली के लिए पहला विद्युत क्रय अनुबंध मध्य प्रदेश पावर ट्रेडिंग कंपनी और आरडीएम केयर इंडिया कंपनी के बीच पूरा हुआ. गोबर गैस से उत्पादित होने वाली बिजली क्रय के एमओयू पर मध्य प्रदेश पावर ट्रेडिंग कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक एबी वाजपेयी और आरडीएम केयर कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मलिंदर सिंह आनंद ने हस्ताक्षर किए. अनुबंध के तहत आरडीएम केयर कंपनी 14 करोड़ रुपये की लागत से जबलपुर शहर की परियट नदी पर अपना गोबर गैस आधारित बिजली संयंत्र स्थापित करेगी. इस संयंत्र में 120 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाएगी.

ग़ैर-जमानती वारंट के बाद भी अधिकारी बहाल

शिवा कुमार

राज्य में भ्रष्टाचार और घोटालों पर लगाम लगाना वैसे ही मुश्किल हो रहा है. उस पर जो मामले अदालत में चल रहे हैं, उनके दोषियों पर कोई कार्रवाई न कर प्रशासन अप्रत्यक्ष रूप से अपराधियों को संदेश दे रहा है कि क़ानून से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. यही वज़ह है कि ग़ैर जमानती वारंट के बावजूद कई आला अधिकारी अपनी अपनी कुर्सियों में जमे हुए हैं.

छत्तीसगढ़ शासन ने परिवहन विभाग के तीन निलंबित अधिकारियों को चार्टशीट और ग़ैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद भी बहाल कर दिया. सुप्रीम कोर्ट तक जमानत के लिए पहल कर चुके इन अधिकारियों को सिर्फ़ चार सप्ताह की मोहलत मिली थी और इसके बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने प्रस्तुत होकर वहां से जमानत लेने के निर्देश दिए गए थे. इन सभी तथ्यों को नज़र अंदाज़ कर शासन ने उन्हें बहाल कर दिया है. छत्तीसगढ़ शासन की प्रशासनिक कमज़ोरियों की एक अनोखी कहानी सामने आई है. राज्य शासन ने वर्ष 2002-03 में कोयला परिवहन घोटाले में एसईसीएल के गेवरा क्षेत्र में ठेके में परिवहनकर्ता द्वारा ट्रकों की भार वहन क्षमता को बढ़ाकर अतिरिक्त लाभ कमाने के मामले में निलंबित तीन अधिकारियों को समस्त कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए बहाल कर दिया है. मामले की शिकायत की जांच कर रही सीबीआई के अधिकारी राज्य शासन के इस आदेश पर आश्चर्य चकित है.

कोयला परिवहन घोटाले की जांच के दौरान सीबीआई ने 2007 में 36 लोगों के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज़ की थी. जिसमें 26 परिवहनकर्ता थे, 6 कर्मचारी एसईसीएल और 6 कर्मचारी आरटीओ के भी शामिल थे. इन सभी को अपराध क्र. आर.सी.0092994ए004 में संबंध जारी किया गया. संबंधित व्यक्तियों ने उपरोक्त प्रक्रिया के प्रारंभ होने के बाद जमानत के प्रयास शुरू कर दिए. निचली अदालतों से निराश होने के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी इनकी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया. सीबीआई की ट्रायल कोर्ट में सिर्फ़ 11 लोग 29 अगस्त 2007 को हाज़िर हुए जिसमें से 10 परिवहनकर्ता और एक आरटीओ का कर्मचारी था. कोर्ट ने सभी 11 व्यक्तियों को जेल भेज दिया.

मामला दर्ज़ होने और चार्टशीट दाखिल होने के बाद आरटीओ के तीन सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी पीआर नेताम, एस एन सिंह, एल एक्का और सहायक वर्ग-2 से अरूण और राजेन्द्र गुप्ता निलंबित कर दिए गए. कुल 12 लोगों को जेल होने के बाद शेष फ़रार लोगों में से एल एक्का एवं अन्य ने उच्चतम न्यायालय की शरण ली सुप्रीम कोर्ट ने चार सप्ताह के लिए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और निर्देश दिया कि सीबीआई के अदालत में समर्पण करने के बाद आरोपी वही से जमानत की मांग करें. आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया. इस बीच दो परिवहन ठेकेदारों राजेन्द्र अग्रवाल और राजकुमार केडिया के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इंटर्म रिलिफ देने का फैसला किया.

उच्च न्यायालय के इस आदेश से सभी आरोपियों को राहत मिली और सीबीआई के लिए यह प्रकरण एक लंबी लड़ाई का कारण बन गया. उपरोक्त आदेश के आधार पर निलंबित कर्मचारियों ने विभाग में बहाली के आवेदन लगाने शुरू कर दिए. राज्य शासन ने उच्च न्यायालय के आदेश की विधि विभाग से समीक्षा करने के उपरांत तीनों अधिकारियों को साकेत कवीर धाम और दांतेवाड़ा में बहाल करके पदस्थ कर दिया.

छत्तीसगढ़ शासन के निर्णय से सीबीआई द्वारा की जा रही जांच पर व्यापक प्रभाव पड़ा है. यह जांच और परिवहन घोटाला अब लंबे समय के लिए लंबित हो चुका है.

feedback@chauthiduniya.com

अनाज क्रय एवं वितरण प्रणाली में धांधली

सहकारी विपणन संघ द्वारा शासकीय समर्थन मूल्य में ख़रीदे जा रहे गेहूं के लेन-देन पर दलालों का साया पड़ चुका है. सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राशन माफियाओं ने कई अनियमितताएं फैला रखी हैं. परिणाम यह है कि किसान और आम उपभोक्ता शासन की समस्त नीतियों के बाद भी शोषित हैं.

अशोक नगर कृषि उपज मंडी का नाम मध्य प्रदेश की उत्कृष्ट मंडियों में शुमार किया जाता है. यहां इन दिनों लाखों क्विंटल अनाज प्रतिदिन ख़रीदा और बेचा जाता है. 1200 रु. क्विंटल समर्थन मूल्य में सहकारी समीतियों द्वारा उक्त ख़रीद 15 जून तक की जानी है. इस ख़रीद के कारोबार में दलाल पूरी तरह सक्रिय हैं जो गांवों के भोलेभाले किसानों से कमीशन के रूप में अवैध वसूली कर रहे हैं.

किसान संघ के ज़िला उपाध्यक्ष परमाल सिंह हैदर के अनुसार जिन किसानों ने सहकारी बैंकों से क़र्ज़ा ले रखा है, वे समिति के सचिव से मिलकर किसी अन्य किसान के नाम पर गेहूं बेच रहे हैं, इससे बैंकों को ऋण वसूली में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा. शासन को लाखों रुपये का राजस्व नुकसान पहुंचाने में किसानों को दलालों की पूरी मदद मिल रही है. हैदर के अनुसार मुंशियों की मिलीभगत से प्रत्येक ट्राली जो गेहूं बेचने केंद्र पर आती है, उससे तयशुदा कमीशन वसूल किया जाता है.

चौथी दुनिया संवाददाता ने ख़रीदी केंद्र में चल रही इस आपाधापी का स्वयं निरीक्षण किया और यह पाया कि एक तरफ मध्य प्रदेश शासन किसानों एवं सहकारी बैंको के बेहतर समन्वय एवं उन्नयन के लिए शासकीय ख़रीदी केंद्रों पर किसानों को उनकी उपज का वाज़िब मूल्य दिलाकर गेहूं विक्रय पर बोनस के लिए प्रेरित कर रहा है, तो दूसरी ओर समिति के सचिव और दलाल भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं.

अशोक नगर क्षेत्र में अंत्योदय राशन कार्डधारियों की संख्या 26244, बीपीएल धारकों की संख्या 61521 और एपीएल राशन कार्डधारियों की संख्या 99049 है, जिन्हें ज़िले में संचालित 190 उपभोक्ता भंडारों के माध्यम से राशन उपलब्ध कराया जाता है. इसमें से एपीएल कार्ड धारक उन्हें मिलने वाला 10 किलो गेहूं उपयोग नहीं करते हैं. मात्र 45 प्रतिशत राशन कार्डधारी ही इसका उपयोग करते हैं. एक सर्वेक्षण के अनुसार 55 से 60 प्रतिशत उपभोक्ता राशन दुकान से सामान ही क्रय नहीं करते, इसके बावजूद ज़िले में राशन की दुकानों में खाद्यान्न का अभाव बना रहता है.

अशोक नगर क्षेत्र में अनाज के क्रय एवं उसके विक्रय की पूर्ण प्रणाली स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों के कारण भ्रष्टाचार की परिधि में घिरी हुई है, इसके परिणाम स्वरुप आम व्यक्तियों का जीवन यापन और मुश्किल होता जा रहा है.

क्रमांक 12626

कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा)
जिला- अशोकनगर (म.प्र.)
(खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग)
जिला खाद्य शाखा का दूरभाष क्रमांक 07543-225510

'गरीबी रेखा से नीचे के परिवार का राशनकार्ड'
वर्ष - 2006

(केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपयोग के लिए)

राकेश वर्मा
feedback@chauthiduniya.com

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. 45843/86

चौथी दुनिया

दिल्ली, 26 अप्रैल–02 मई 2010

शिवराज सिंह ने स्वीकार किया कि व्यवसायिक तौर पर साधना सिंह को डंपर कारोबार से 16 लाख रुपये की कमाई हुई.

गोंड राजाओं की राजधानी

रामनगर बर्बादी की कगार पर

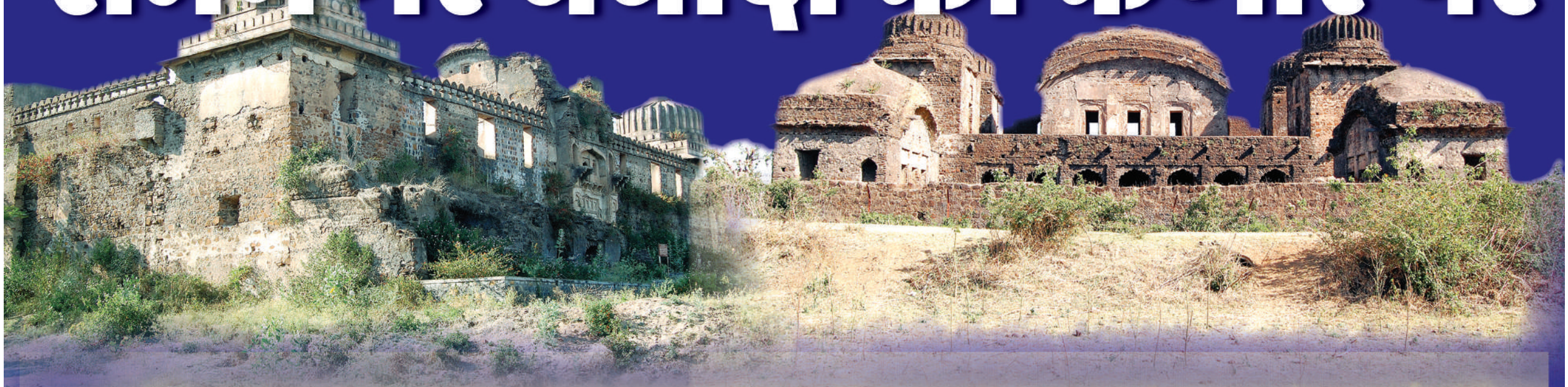

असगर कुरैशी

रामनगर के अनेक पुरातत्व महत्व के स्मारक संरक्षण के आभाव में नष्ट हो रहे हैं, जबकि केंद्र और राज्य के पुरातत्व विभाग इनकी रक्षा के लिए करोड़ों रुपया ख़र्च होने का हिसाब बताते हैं, लेकिन सच तो यह है कि रामनगर के महल जर्जर हो चुके हैं और कई शानदार स्मारक बर्बादी की कगार पर हैं.

इतिहास और पर्यटन के मामले में भी सरकार और बाज़ार की शक्तियों का संकीर्ण रवैया बना हुआ है. भारत के इतिहास और पर्यटन में लाल किला, कुतुबमीनार, ताजमहल, खजुराहो, विजय नगरम्, कोणार्क आदि का तो बढ़–चढ़कर महत्व बताया गया है, लेकिन प्रतापी गोंड राजाओं के भव्य और शानदार किलों, महलों, मंदिरों और नगरों पर किसी का कोई ध्यान नहीं, जबकि यदि इन स्मारकों और खंडहरों को ईमानदारी से देखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि गोंड राजाओं की निर्माणकला, भवनों और ईमारतों की सजावट कितनी अद्भुत और विशिष्ट रही है.

मध्य प्रदेश का मंडला ज़िला प्राचीन और मध्यकालीन गोंड राजाओं के अनेक स्मारकों की समृद्ध स्थली है, लेकिन दुख की बात है कि मध्य प्रदेश और देश के पर्यटन मानचित्र में इनका कहीं कोई ज़िक्र नहीं मिलता है. मंडला ज़िले के गोंड राजाओं की राजधानी रामनगर, उपेक्षा के कारण खंडहर होते–होते अब अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है. रामनगर के अनेक आकर्षक स्मारक संरक्षण के अभाव में नष्ट हो रहे हैं, जबकि केंद्र और राज्य के पुरातत्व विभाग इनकी रक्षा के लिए करोड़ों रुपया ख़र्च होने का हिसाब बताते हैं. रामनगर के महलों का इतिहास जानने के लिए हमने इतिहास के प्रध्यापक डॉ. शरद नारायण खरे से जानना चाहा तो, उन्होंने बताया कि मण्डला में स्थित गोंड कालीन राजधानी एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो सकता है, परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो पा रहा है. गोंड राजा समय–समय पर अपनी राजधानी बदलते रहे हैं, ऐसा वे परिस्थितियों के अनुसार करते थे. इस प्रकार गोंड राज्य की राजधानी कभी जबलपुर के नगर निगम के अंतर्गत गढ़ा क्षेत्र में थी, कभी सिंगोरगढ़ (ज़िला दमोह), तो कभी चौरागढ़ (ज़िला नरसिंहपुर) में थी. 1651 ई. में जुझार सिंह बुंदेला के छोटे भाई पहाड़ सिंह बुंदेला ने चौरागढ़ पर आक्रमण किया. इस आक्रमण के समय गढ़ा का शासक हिरदेशाह था. इस आक्रमण के फलस्वरूप चौरागढ़ सदा के लिए गोंड राजाओं के अधिकार से निकल गया. ऐसी स्थिति में हिरदेशाह ने अपनी राजधानी मंडला नगर से 17 किमी दूर नर्मदा के तट पर रामनगर में स्थापित की. हिरदेशाह ने यहां अनेक इमारतों का निर्माण कराया, जिनमें से अधिकांश वर्तमान में भी मौजूद हैं तथा पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हैं. लेकिन इनका पर्यटन की दृष्टि से न तो अभी तक उपयोग हुआ है और न ही प्रचार–प्रसार. इसके अतिरिक्त ज़िला मुख्यालय से यहां तक पहुंचने और इमारतों के भ्रमण हेतु भी पर्याप्त सुविधा का अभाव है. गाइड की उपलब्धता तथा लिखित विवरण (बुकलेट/पेम्पलेट आदि) का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है. यदि हम हिरदेशाह द्वारा निर्मित इन इमारतों व भवनों का अध्ययन करें, तो इनकी विशिष्टता के पूर्ण दर्शन होते हैं. रामनगर दुर्ग तो अब नष्ट (केवल दो बुर्ज़ों को छोड़कर) हो चुका है, परंतु उसके अंदर निर्मित इमारतें (अधिकांश) आज भी अच्छी स्थिति में है. अगर हम रामनगर स्थित राजा हिरदेशाह के महल मोती महल की बात करें तो यहां के हालात भी कुछ बाकी खंडहरों की तरह ही हैं. यह महल नर्मदा के दक्षिणी तट पर स्थित है. कनिंघम की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 1881 ई. में मोतीमहल नर्मदा के जलस्तर से 80 फुट ऊपर था. अब यह दूरी कम हो गई है. अपने निर्माण काल में अवश्य ही मोती महल नर्मदा से 80 फुट से भी बुहत अधिक ऊपर रहा होगा. यहां से नर्मदा नदी का बहुत रम्य दृश्य देखने को मिलता है. निश्चित ही दुर्ग–निर्माण के लिए स्थल का चुनाव करते समय हिरदेशाह को इस स्थान का सौंदर्य भाया होगा. मोतीमहल आयताकार है, जो बाहर से 64.5 मीटर लंबा और 61 मीटर चौड़ा है. भीतर आंगन 50.5 मीटर लंबा और 47.25 मीटर चौड़ा है. बीच के कमरे लंबे हैं और बगल के कमरे सामान्यत: आकार में छोटे हैं. मोतीमहल के बारे में मंडला गजेटियर (1912 ई.) के विचार पूर्वाग्रह पूर्ण और भ्रामक हैं, जो इसके सौंदर्य पर प्रश्नचिन्ह लगाते हैं. हालांकि मंडला गजेटियर में भी यहां से नर्मदा के सुंदर दृश्य की बात कही गई है. महल की तीन मंज़िलें हैं, उसमें बहुत से कमरे हैं, जिनमें राजा का अंत:पुर निवास करता था और हिरदेशाह के समय महल में स्त्रियों की संख्या 100 थी. इसमें एक शिलापट्ट भी है. मोतीमहल के आंगन में स्नानगार है. मंडला गजेटियर में इसे राजप्रासाद (पैलेस) कहा गया है. 1984 ई. में इसे मध्य प्रदेश शासन द्वारा संरक्षित घोषित किया गया था. वास्तव में राजमिस्त्रियों ने रामनगर के भवनों के रूप में उस समय का बेहतरीन स्थापत्य कौशल का नमूना प्रस्तुत किया था. अगर हम रानी महल की बात करें तो मोतीमहल से डेढ़ मील पर उत्तर–पूर्व दिशा में रानी महल है, इसे बघेल रानी का महल कहा जाता है. कनिंघम के अनुसार बघेल रानी के समीप एक बावड़ी भी है. रानी महल भारत शासन द्वारा सुरक्षित घोषित कर दिया गया है, पर इसकी भी स्थिति जस की तस बनी हुई है. मोतीमहल से दक्षिण–पश्चिम, लगभग तीस मीटर की दूरी पर एक विष्णु मंदिर स्थित है, जो बाहर से मक़बरे जैसा दिखाई देता है. इस मंदिर का निर्माण हिरदेशाह की पत्नी सुंदरी देवी द्वारा करवाया गया था. कक्ष के ऊपर एक गुम्बज है और साथ ही प्रत्येक कोने में एक–एक छोटा कक्ष है. प्रत्येक पार्श्व के मध्य में एक खुला बरामदा है. पूर्व में बरामदे के दो स्तंभ गिर चुके हैं, परंतु उसका गारा इतना अच्छा है कि छत अब भी दुरूस्त है. मंदिर का यह वर्णन कनिंघम ने अपनी रिपोर्ट में दिया है. यह मंदिर मध्यकालीन गोंड स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण है. मोतीमहल में रखे शिलापट्ट के लेख से ज्ञात होता है कि यह सिंहशाह दयाराम और भगीरथ नाम के स्थानीय कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया था. आज भी इस मंदिर के गुम्बज लगभग उसी प्रकार अक्षुण्ण हैं, जैसा उनका वर्णन कनिंघम की रिपोर्ट में है. पूर्वी बरामदे के भग्न स्तंभों और छत की भी वैसी ही स्थिति है, जैसी कनिंघम के समय थी. जहां तक मंदिर के स्थापत्य का संबंध है तो ज़िले के अन्य किसी भी मंदिर से इसकी समानता नहीं है. इस मंदिर को मध्य प्रदेश शासन ने 1984 में संरक्षित घोषित कर दिया था.

विष्णु मंदिर में प्रतिष्ठित देवमूर्तियों (गणेश, दुर्गा, शिव, सूर्य और विष्णु) में से गणेश व सूर्य गोंडकालीन हैं, शेष कलचुरिकालीन हैं. इस मंदिर का भी बुरा हाल है. रामनगर स्थित रायभगत की कोठी जो कि मोतीमहल से थोड़ी दूरी पर एक विशाल भवन है, जिसे रायभगत की कोठी कहा जाता है. रायभगत राजा हिरदेशाह के दीवान थे. यह भवन दीवान का निवास था. आज भी यह भवन भव्य दिखता है, भवन के प्रवेश द्वार पर सफ़ेद संगमरमर लगा हुआ है. द्वार के ऊपर नौबतखाना बना हुआ है. 1984 में इसे मध्य प्रदेश शासन द्वारा संरक्षित घोषित किया गया था पर इसकी भी स्थिति जर्जर है. अगर शासन चाहे तो इन सब किलों की हालत आज भी बदल सकती है और रामनगर का नाम अच्छे पर्यटन स्थलों की लिस्ट में शुमार किया जा सकता है. यह पर्यटन स्थल सरकार की आय का साधन बन सकता है तथा इससे गोंडकालीन इतिहास भी सुरक्षित रह सकेगा. इनकी समुचित देखभाल और विकास तो होना ही चाहिये, साथ ही इन्हें पर्यटन–केंद्रों के रूप में इस प्रकार से विकसित किया जाना चाहिए, जिससे कि वे पर्यटन–उत्पाद के रूप में काम आ सके. ऐसे पर्यटन–केंद्र बनने से वंचित स्थलों को सूचीबद्ध किया जाए और इसका सर्वे करके उन्हें संरक्षण व देखभाल की स्थिति में लाया जाए. मंडला ज़िला प्रदेश के मध्य में स्थित है. नर्मदा नदी ज़िले में से होकर बहती है, जिसने यहां के जीवन और चिंतन को सहस्त्राब्दियों से प्रभावित किया है, न केवल भौगोलिक–दृष्टि से बल्कि वैचारिक दृष्टि से भी नार्मदीय क्षेत्र का बहुत महत्व है. निश्चित रूप से मंडला ज़िले में स्थित गोंडकालीन ऐतिहासिक स्थली रामनगर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की पूरी संभावनाएं हैं, तथा परिस्थितियां भी अनुकूल हैं. नर्मदा के कारण वैसे भी ज़िले की आध्यात्मिक व सांस्कृतिक महत्ता है. महत्वपूर्ण किलों, मंदिरों, मूर्तियों व आदिवासी सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण ज़िले मे पर्यटन के विकास की अच्छी संभावनाएं हैं. आवश्यक बस यह है कि इस दिशा में गंभीरतापूर्वक प्रयास किये जाएं. यद्यपि कुछ स्थलों का संरक्षण व रखरखाव किया गया, परंतु अधिकांश स्मारक आज भी उपेक्षित हैं.

निष्कर्षत: धाराशायी होती इस धरोहर को गंभीरतापूर्वक संरक्षण की आवश्यकता है. चूंकि इन स्मारकों में हमारा गौरवशाली इतिहास, संस्कृतिक, कला व पुरातत्व समाहित है. इसलिए नष्ट होती हुई इस विरासत का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है.

feedback@chauthiduniya.com

अभी भी चुनौती है

डंपर काड

साधना सिंह, शिवराज सिंह की पत्नी

राज्य में भुखमरी और आर्थिक तंगी छाई हुई है. मुख्यमंत्री जनता को दरकिनार कर अपना धंधा पानी जमाने में लगे हुए हैं. संपत्ति का व्यौरा और उनकी पत्नी द्धारा चलाए जा रहे ट्रेवल बिज़नेस के पीछे की कहानी साफ़ बताती है कि उन्हें प्रदेश की कितनी फ़िक्र है.

मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों द्वारा विधानसभा के पटल पर रखी गई, संपत्ति संबंधी जानकारी में राज्य के वित्तीय विशेषज्ञों को असमंजस में डाल दिया है. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी समेत सात व्यक्तियों के ख़िलाफ़ जनहित याचिका ख़ारिज़ कर दी है. इसके बावजूद स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों पर बड़ा प्रश्नचिन्ह लग चुका है. प्रस्तुत किए गए उन दस्तावेजों में कई महत्वपूर्ण जानकारियां छिपाए जाने की आशंका है.मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों द्वारा विधानसभा के पटल पर रखी गई संपत्ति संबंधी जानकारी ने राज्य के वित्तीय विशेषज्ञों को असमंजस में डाल रखा है. विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी निजी संपत्ति का ब्यौरा क्या रखा, प्रश्नों की बौछार शुरू हो गई. उन्होंने बीती 23 फरवरी को स्वयं एवं पत्नी श्रीमती साधना सिंह के पास मौजूद धन, संपत्ति एवं संसाधनों का ब्यौरा प्रस्तुत किया था. उक्त घोषणा के बाद शिवराज सिंह पर डंपर कांड को लेकर लग रहे आरोप और गहरे हो गए हैं. मुख्यमंत्री के संपत्ति विवरण को कांग्रेस संदिग्ध और अविश्वसनीय मानती है. उसने एक पृथक एजेंसी के माध्यम से जांच कराने की मांग की है.

मुख्यमंत्री के विरुद्ध लोकायुक्त संगठन में एक निजी कंपनी जेपी सीमेंट में लगाए गए डंपरों को लेकर प्रकरण क्रमांक सीआर 41/7 दर्ज़ है. उपरोक्त प्रकरण दर्ज़ होने के बाद नेता प्रतिपक्ष जमुना देवी को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री स्वयं स्वीकार कर चुके हैं कि उनकी पत्नी साधना सिंह ने मई 2006 में कर्ज़ लेकर 72 लाख रुपये में डंपर ख़रीदे थे, जिन्हें एक साल बाद निजी कारणों से जेपी सीमेंट रीवा को बेच दिया गया.

एक साक्षात्कार में उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उनकी पत्नी कई सालों से ट्रैवल्स का बिज़नेस संचालित कर रही हैं. शिवराज ने इसी साक्षात्कार में कहा था कि आजीविका चलाने के लिए व्यवसाय करना कोई ज़ुर्म नहीं है.

उन्होंने स्वीकार किया कि व्यवसायिक तौर पर साधना सिंह को डंपर कारोबार से 16 लाख रुपये की कमाई हुई. यह बात अलग है कि साधना सिंह की कंपनी को जेपी सीमेंट ने प्रति डंपर 75 हज़ार रुपये मासिक किराया दिया, जिसमें बाद में 10 हज़ार रुपये की वृद्धि कर दी गई थी. मुख्यमंत्री द्वारा घोषित संपत्ति के विवरण में कुछ तथ्य संदिग्ध हैं. जैसे डंपर ख़रीद में साधना सिंह ने शिवराज सिंह चौहान के नाम को एसआर सिंह क्यों बताया, आरटीओ के पंजीयन में जेपी नगर प्लांट में निवास का ग़लत पता क्यों दिया गया, डंपर ख़रीद के लिए कितनी मार्ज़िन मनी दी गई और किस्तों में भुगतान कैसे किया गया?

उक्त घोषणा के बाद डंपर प्रकरण में मुख्यमंत्रीद्वारा घोषित संपत्ति में साधना सिंह द्वारा संचालित व्यवसाय में ट्रेवल्स से संबंधित आय–व्यय का ब्यौरा नहीं दिया गया है. आरटीओ की साइट से डंपर संबंधी जानकारी पूर्व में ही हटा दी गई थी. यह भी ज्ञात नहीं है कि डंपर किसे और कितने में बेचे गए. इन डंपरों को बेचने से हुई आय और डंपरों से प्रतिमाह होने वाली आय का विवरण भी संपत्ति की घोषणा से ग़ायब है. बैंक ऋण के संदर्भ में यह जानकारी भी अज्ञात है कि विक्रय के बाद कितना ऋण चुकाया गया और आयकर विवरणी में इसका उल्लेख किया गया है या नहीं.

नेता प्रतिपक्ष जमुना देवी ने मुख्यमंत्री से वर्ष 2007 में संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग की थी. उक्त मांग के पौने तीन साल बाद मुख्यमंत्री ने संपत्ति को सार्वजनिक किया है. घोषित की गई संपत्ति में डंपर से हुई आय से संबंधित तथ्यों को छिपाए जाने का आरोप कांग्रेस प्रवक्ता के के मिश्रा पहले ही लगा चुके हैं. उनके अनुसार, लोक सेवक होने के नाते संपत्ति की घोषणा के समय हुई इस चूक की जांच एक पृथक एजेंसी के माध्यम से किया जाना चाहिए. वर्तमान में यह प्रकरण लोकायुक्त के पास है, जिसकी विवेचना का काम जारी है. ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए इस ग़ैर ज़िम्मेदाराना कार्य से जनआस्था पर संकट पैदा होता है.

उल्लेखनीय है कि 14 मार्च 2008 को शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी साधना सिंह के नाम पर एक एंबेसडर कार का होना बताया था. 26 मई 2006 को साधना सिंह के नाम पर चार डंपरों की ख़रीद का मामला सामने आया. 17 अगस्त 2007 को शिवराज सिंह ने स्वीकार किया कि साधना सिंह के नाम पर चार डंपर हैं और वह ट्रैवल व्यवसाय से जुड़ी हैं. इसके लिए 77 लाख रुपये का ऋण लेना भी उन्होंने स्वीकार किया. विधानसभा के बजट सत्र 2009–10 में घोषित आय के विवरण में डंपरों का ज़िक्र न होना ही विवाद का प्रमुख कारण बना.

मुख्यमंत्री की इस भूल को कांग्रेस एक मुद्दा बनाकर प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है. कांग्रेस के प्रवक्ता आज भी डंपर कांड और मुख्यमंत्री के आर्थिक निजी तंत्र की जांच कराए जाने की मांग कर रहे हैं, जिस पर सरकार पूरी तरह मौन है. आश्चर्य इस बात का है कि मुख्यमंत्री पर होने वाले हमलों से बचाव के लिए भाजपा का कोई भी नेता उनके पक्ष में बयान देने के लिए आगे नहीं आ रहा है.

संध्या पाण्डे
feedback@chauthiduniya.com